

• औद्योगिक जमीन को भू-खंड बनाकर बेचा • पीले सोने पर मौसम की मार

In Pursuit of Truth

आक्षर

पाक्षिक

www.akshnews.com



फिसान भरोसे जीत

वर्ष 19, अंक-1

1 से 15 अक्टूबर 2020

पृष्ठ-48

मूल्य 25 रूपये

R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2018-20

बाबरी से सब बरी





*We Deal in
Pathology & Medical
Equipments*

Anu Sales Corporation

Add: Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

● इस अंक में

प्रशासनिक

9

गरीबी में आटा गीला

मप्र लगातार कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है। आलम यह है कि विकास योजनाओं के लिए सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण आर्थिक तंगी झेल रही मध्यप्रदेश सरकार की मुश्किलें...

राजपथ

10-11

पायलट प्रोजेक्ट

मप्र की कांग्रेस सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को उपचुनाव में पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके लिए पार्टी सर्वे कराकर प्रत्याशी उतार रही है।

समस्या

13

8 हजार गर्भवती महिलाएं लापता

पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करने के बाद एक-एक गर्भवती महिला का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखा जाता है। दरअसल डॉक्टर की सलाह पर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसके जरिए ये रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि सोनोग्राफी करवाते...

विवाद

16

दावे 35 साल में भी पूरे नहीं

सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित और प्रभावित हजारों लोगों को जो मिला है, वह निश्चित ही दुनिया की किसी अन्य परियोजनाओं में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिला होगा, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया गया। शासन करने वालों से लेकर समाज के विभिन्न तबकों...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28



अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-धार्मिक विवाद था, जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर था। इन दोनों मुद्दों का 2020 में पटाक्षेप हो गया है। इसके साथ ही राजनीति का एक ऐसा मंच समाप्त हो गया, जिसको लेकर बार-बार राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद धर्म की राजनीति पर विराम लग जाएगा। अब काशी और मथुरा के विवादों को हवा दी जा रही है।

18



30-31



35



45



सियासत

32-33

जमीन खो चुकी कांग्रेस

देश में कांग्रेस की आज भी गहरी पैठ हैं। जानकारों का कहना है कि सही नेतृत्व की कमी के कारण कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। जिस राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावशाली है वहां पार्टी मजबूत स्थिति में हैं। अब तो उप्र कांग्रेस के संगठन पर प्रियंका गांधी की कुशल रणनीति का प्रभाव भी...

उत्तरप्रदेश

36

फिल्म सिटी की सियासत

उप्र की योगी सरकार ने उस 'मुंबई' को आड़ना दिखा दिया है जो 'बॉलीवुड' के चलते 'इतराया' करता है। बॉलीवुड की पहचान हिन्दी फिल्मों से जुड़ी है। बॉलीवुड में करीब 80 प्रतिशत कलाकार, लेखक, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ उत्तर भारत...

राजस्थान

37

खनन माफिया की जागीर

राजस्थान खनन माफिया की जागीर बनता जा रहा है। सरकारों के संरक्षण में यहां हमेशा से माफिया का बोलबाला रहा है। शासन-प्रशासन उनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। यहां हमेशा माफिया का खूनी खेल चलता रहता है।

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य



देवी-देवता के देश में और कितनी 'निर्भया'?

33 करोड़ देवी-देवता के इस देश में जब-जब किसी बेटी की अस्मृत लुटती है तो अक्सर हमारे मन में ये पक्तियां उमड़ने-घुमड़ने लगती हैं कि...

**उठी नजरें जब वैदेही पर, सर्वनाश हुआ उस अहंकारी का,
अब कौन राम शास्त्र उठाएंगे, देखर हाल कलियुग की नारी का।**

दरअसल, हमारे देश में **यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता**, युगों से चले आ रहे इस भाव के बावजूद यहां की बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। श्लोक का मतलब यह है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अपने देश में देवों से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। सीता-राम, राधे-कृष्ण, लक्ष्मी-नारायण, गौरी-शंकर। ये सभी नाम हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। द्वापर में महाभारत और त्रेता की रामायण में राम-रावण युद्ध भी नारी सम्मान के लिए लड़ा गया था। लेकिन 21वीं सदी में हर रोज नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ हैवानियत हो रही है, लेकिन तमाम तरह के कायदे-कानून के बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर देवी-देवता हैं तो नारी पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आज से **करीब 8 साल पहले** देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो देश जिस तरह उबला था, उससे लगा था कि अब कोई निर्भया हैवानियत का शिकार नहीं होगी। लेकिन हैवानियत का झिलझिला लगातार जारी है। हाथरस में 19 साल की लड़की से गैंगरेप की घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। पीड़िता के साथ जिस तरह की बेरहमी की गई, उससे पूरे देश में आक्रोश है। हाथरस की बेटी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई कि उप्र के ही बलरामपुर में एक और बेटी को बलात्कारियों ने मार दिया। वहीं मप्र के ब्रह्मगोन में 15 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। ये घटनाएं हर किसी को विचलित कर रही हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह हैवानियत रुक क्यों नहीं रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इस कारण अपराधियों के मन में कानून का भय नहीं रहता है। ऋषि-मुनियों और तपस्वियों के इस देश में नारी की दुर्दशा का आंकलन एनसीआरबी की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि यहां हर दिन औसतन 87 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहा जाता है कि वक्त के साथ-साथ समाज ज्यादा सभ्य होता है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसके उलट सबूत दे रहे हैं। इसके मुताबिक, देशभर में 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर के लिहाज से देखें तो इस लिस्ट में असम सबसे ऊपर है। वहां पिछले वर्ष प्रति लाख महिलाओं में 117.8 महिलाएं हैवानियत की शिकार हुई थीं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान में बलात्कार के सबसे ज्यादा 5,997 केस दर्ज करवाए गए जबकि मप्र 2,485 रेप केस के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। कितनी हैरत की बात है कि 100 प्रतिशत शिक्षित आबादी वाला राज्य केरल प्रति लाख आबादी पर महिलाओं के रेप केस की दर में दूसरे स्थान पर है। वहां प्रति लाख आबादी पर 11.1 महिलाओं का रेप हुआ। वहीं, 15.9 की दर से राजस्थान इस लिस्ट में टॉप पर है। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश में जब भी कोई हैवानियत का मामला सामने आता है, उस पर राजनीतिक रोटी खिंकने लगती है। लेकिन सरकार किसी की भी हो हैवानियत कम होने का नाम नहीं ले रही है।

-राजेन्द्र आगाल

अक्षर

वर्ष 19, अंक 1, पृष्ठ-48, 1 से 15 अक्टूबर, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जॉन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPEPL/642/2018-20

ब्यूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्डोलेव मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पावती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेहरू, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुध्ति सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वातंत्र्यकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जॉन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



अवैध खनन पर सख्ती हो

मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल है, जहां अवैध खनन बड़े स्तर पर होता है। यहां कई जगह अवैध खनन चोरी-छिपे, तो कई जगह सीना टोककर होता है। माफिया प्रदेश की प्रत्येक नदी में सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार को इसके खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए।

● आशीष श्रीवास्तव, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल-इंदौर मेट्रो सिटी

प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सरकार है। भोपाल और इंदौर की मेट्रो रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एमपीएमआरसी का गठन किया है। यदि तेज गति से मेट्रो का काम चलता रहा तो जल्द ही भोपाल और इंदौर मेट्रो सिटी कहलाने लगेगी।

● नीलेश बड़कुर, इंदौर (म.प्र.)



250 करोड़ का चावल घोटाला

चावल घोटाला माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से 250 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चावल की गुणवत्ता जांच का कोई पुरस्ता तंत्र मप्र में नहीं है। प्रदेश में अनाज की खरीदी और भंडारण की जिम्मेदारी 4 संस्थाओं- नागरिक आपूर्ति निगम, एमपी एग्री, खाद्य विभाग और वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी अमानक खरीदी या भंडारण की जांच नहीं कर पाता है। इनके रहते केंद्र की टीम आती है और 52 हजार टन चावल की सैपलिंग करती है, जिसमें से 3 हजार टन खराब निकलता है। दरअसल, प्रदेश में एक आउटसोर्स कंपनी गुणवत्ता देखती है। लेकिन मिलर्स और विभाग की मिलीभगत से अमानक चावल गोदामों में खरीदा जाता है।

● आरती सिंह, ग्वालियर (म.प्र.)

अन्य राज्यों में मजबूत हो आम आदमी पार्टी

आम आदमी पार्टी का संगठन आज की तारीख में जितना दिल्ली में मजबूत है उतना देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। पार्टी के नेता बार-बार दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। आप के बड़े नेताओं का यह दावा है कि जिस मॉडल या चुनावी रणनीति के सहारे उन्होंने पहले शीला दीक्षित जैसे दिग्गज को मात दी। दिल्ली की राजनीति से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को साफ कर दिया। फिलहाल तो आप के चुनावी इरादों ने कई राज्यों की राजनीति में हलचल तो पैदा कर ही दी है। आप को अन्य राज्यों में मजबूती दिखानी होगी।

● महेश सोनी, नई दिल्ली

अच्छा है पायलट प्रोजेक्ट

मप्र के 11 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जो कि अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 4 विभागों को खरीदा गया है, जिसमें पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। केंद्र ने अप्रैल 2021 तक का टारगेट तय किया है। इससे सड़क हादसों की जानकारी में मदद मिल सकेगी।

● प्रांजल उपाध्याय, सीहोर (म.प्र.)



शौचालय नहीं...

हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि हर घर में शौचालय हो, लेकिन आज भी देश के कई क्षेत्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस ग्राम पंचायत को प्रशासनिक अधिकारियों ने खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया वहां भी लोगों को साड़ियों की आड़ में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ रहा है। बीपीएल सूची में शामिल लोगों को शौचालय की योजना का लाभ मिलता है। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं, जहां पक्के शौचालय नहीं हैं।

● लोकेश साहू, जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



राजनीति का मोह

भारत में संवैधानिक संस्थाओं और राजनीति के बीच की दूरी धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों में राजनीति का मोह तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने या भाजपा की केंद्रीय राजनीति की कमान उनके हाथ में आने के बाद से यह प्रक्रिया तेज हुई है। पहले भी ऐसा होता था कि उच्च पदों पर बैठे लोग रिटायर होने के बाद राजनीति में आते थे पर वह अपवाद के तौर पर था। अब वह अपवाद मुख्य धारा बनता जा रहा है और विधायिका के अलावा लोकतंत्र के बाकी स्तंभों से जुड़े लोगों का राजनीति के प्रति रुझान बढ़ रहा है। इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यह इस सरकार में हुआ है कि सेना के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए व्यक्ति ने हाथ के हाथ राजनीति ज्वाइन कर ली और लोकसभा में सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए। जनरल वीके सिंह अपने विवादित कार्यकाल के बाद रिटायर होते ही भाजपा में शामिल हो गए। सोचें, सेना का प्रमुख रहे वीके सिंह सांसद और राज्य मंत्री बनकर खुश हैं, सांसद में सवालियों का जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही न्यायपालिका के प्रमुख रहे रंजन गोगोई रिटायर होते ही राज्यसभा के सांसद बन गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में सरकार के पक्ष में अनगिनत फैसले दिए और राज्यसभा में जाने के लिए इंतजार भी नहीं किया।

गिले-शिकवों का असर नहीं

उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को कोरोना के भय ने एक दिन तक ही सीमित कर दिया। पर उसी दिन गुल खूब खिले। कांग्रेसी विधायकों से ज्यादा सरकार की लानत-मलानत भाजपा के ही विधायक कर बैठे। पूरनचंद फर्त्याल ने तो अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही रख दिया। भाजपा के ही राजेश शुक्ला ने अवमानना प्रस्ताव तो एक आईएस अफसर के खिलाफ रखा पर खरी-खोटी अपने मंत्री मदन कौशिक को सुनाई। फरमाया कि नैनीताल की बैठक में अफसर ने उनकी तौहीन की, पर कौशिक कान में तेल डाले सब अनसुना करते रहे। विधायक ही क्यों नौकरशाही के प्रति गुस्सा तो महिला कल्याण राज्यमंत्री रेखा आर्य ने भी कम नहीं निकाला। अपने ही विभाग के एक अफसर के खिलाफ पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत कर दी। लेकिन नौकरशाही को ही अपने आंख-कान मान सरकार चला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अपने विधायकों के गिले-शिकवों का कोई असर नहीं दिखा। सत्र में कांग्रेस की इंदिरा हृदयेश और करण मेहरा संक्रमित होने के चलते गैरहाजिर थे। नतीजतन नेता और उपनेता दोनों की गैरमौजूदगी ने कांग्रेस के विधायकों को भी वाचाल बना दिया। भाजपा विधायकों की सनातन पीड़ा अफसरों द्वारा भाव नहीं दिया जाना है।



दो धारी तलवार पर दुष्यंत

हरियाणा के लोग लाग लपेट में भरोसा नहीं रखते। साफगोई से बोलते हैं। जैसे जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेन्द्र सिंह बबली ने अपनी व्यथा-कथा पत्रकारों से कह डाली। फरमाया कि दुष्यंत चौटाला अगर हरियाणा की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं तो बाकी नौ विधायकों की बंदौलत। हरियाणा में भाजपा और जजपा की साझा सरकार है। जजपा के दस विधायक विजयी हुए थे। बबली टोहाना से जीते थे। बबली ने दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला। कहा कि जब भाजपा का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित कराया था तो दुष्यंत ने चार मंत्री पद और कुछ दूसरे लालबत्ती वाले पद मिलने की बात कही थी। लेकिन खुद उप मुख्यमंत्री बन उन्होंने पार्टी विधायकों की अनदेखी करा दी। कैप्टन अभिमन्यु को पटखनी देने वाले रामकुमार गौतम तो मंत्री पद न मिलने से पहले से ही बागी हैं। जाहिर है कि दुष्यंत दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। एक तरफ किसानों के बारे में मोदी सरकार के अध्यादेश का हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा विरोध उन्हें गठबंधन से निकलने को उकसा रहा है। तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायक भाजपा की शह पर कभी भी बगावत कर पार्टी तोड़ सकते हैं, इसका खतरा सिर पर मंडरा रहा है।

खतरे की घंटी

सहयोगी दलों के भीतर अब भाजपा को लेकर राजग में डर का माहौल है। महाराष्ट्र में जब शिवसेना से पार्टी का गठबंधन टूटा था तो हर कोई हैरान हुआ था। वाजपेयीजी ने जब 1996 में सबसे बड़े दल के नेता के नाते बहुमत के बिना ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो शिवसेना के अलावा उसका सबसे भरोसेमंद सहयोगी शिरोमणी अकाली दल ही था। कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में हरसिमरत कौर ने मोदी मंत्रिमंडल से जब इस्तीफा का ऐलान किया तभी साफ हो गया था कि भाजपा की तरफ से अकाली दल की मनुहार की कोई कोशिश नहीं होगी। मानो भाजपा तो अपने इस सबसे पुराने सहयोगी दल से पीछा छुड़ाने की फिराक में ही थी। अकाली दल से नाता तोड़ने की मांग पंजाब के भाजपा नेता पहले से ही कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो बगावत ही अकाली दल के साथ पार्टी के गठबंधन से नाराज होकर की थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा धीरे-धीरे अपने सहयोगी पार्टियों से दूरी बनाना चाहती है।

भाजपा फिर बनी पंच

अन्ना डीएमके सुप्रीमो और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन के बाद जब उनकी पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए थे, तब भाजपा ने पंच की भूमिका निभाई थी। भाजपा की मध्यस्थता से दोनों खेमों का विलय हुआ था और ई पलानीस्वामी मुख्यमंत्री व पनीरसेल्वम उप मुख्यमंत्री बने थे। तब के राज्यपाल की इन दोनों नेताओं की हाथ मिलवाते हुए फोटो खूब वायरल हुई थी। इन दोनों के मिल जाने के बाद भी अन्ना डीएमके का एक खेमा फिर भी अलग रहा। जयललिता की करीबी वीके शशिकला और उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरण अलग पार्टी बनाकर राजनीति करते रहे हैं। अब भाजपा एक बार फिर तमिलनाडु में पंचायत करने वाली है। इस बार भाजपा शशिकला और टीटीवी दिनाकरण की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम, एएमएमके का अन्ना डीएमके में विलय कराने का प्रयास कर रही है।

दो की लड़ाई में तीसरे की चांदी

अक्सर देखा गया है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदेमंद रहता है। लेकिन इसके बाद भी लोग सबक नहीं लेते हैं। आम लोगों की तो छोड़िए देश के सबसे समझदार वर्ग में शुमार नौकरशाह भी अक्सर गलती कर बैठते हैं। ऐसी ही एक गलती की चर्चा प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में हो रही है। दरअसल, प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में पुलिस महकमे के सबसे बड़े पद को पाने के लिए दो आईपीएस अधिकारियों में खींचतान चल रही थी। एक साहब जो अपनी ईमानदार छवि के कारण जाने जाते हैं वो वहां जाना चाहते थे, तो एक दूसरे साहब जिन्हें जुगाडू माना जाता है, उन्होंने ने भी वहां जाने के लिए जोर लगाया था। पहले वाले साहब अपनी मैरिट के आधार पर उक्त पद की चाह लगाए बैठे थे तो दूसरे वाले साहब ने उस पद को पाने के लिए दमदार सोर्स लगाया था। लेकिन विधि का विधान देखिए, दोनों ताकते ही रह गए और बाजी तीसरा मार गया। जिन साहब की वहां पदस्थापना हुई है, वे पत्थर पर दूब उगाने में माहिर माने जाते हैं। इन साहब की वहां पदस्थापना कैसे हुई इसको लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं हैं तथा कई अफसर हैरान भी हैं। क्योंकि जिनकी जगह उन्हें पदस्थ किया गया है, उन साहब की कार्यप्रणाली अभी तक सराहनीय रही थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान में जिन साहब की पदस्थापना हुई है, वे वहां अपना जलवा दिखाकर लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं।

सुदामा की नाराजगी

जिस तरह कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ख्यात थी, उसी तरह प्रदेश की राजनीति में दो नेताओं की दोस्ती हमेशा चर्चा में रहती है। कृष्ण-सुदामा की तरह ही एक दोस्त सत्ता के शिखर पर हैं, तो दूसरे उनके सहयोग से सत्ता सुख पाते रहे हैं। लेकिन ये दोस्त सुदामा की तरह थोड़े में संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए इन दिनों ये नाराज चल रहे हैं। इनकी नाराजगी का आलम यह है कि इन्होंने सरकारी सुख-सुविधाओं का त्याग कर आँटो से चलना शुरू कर दिया है। दरअसल, ये आधुनिक सुदामा एक ट्रांसफर को लेकर अपने दोस्त से नाखुश चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग में एक अफसर का ये ट्रांसफर कराना चाहते थे, लेकिन उक्त अफसर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं थे। यह उक्त नेताजी को नागवार गुजरा और उन्होंने इसके लिए विभागीय मंत्री से मुलाकात की। मंत्रीजी ने उनसे कहा कि आप मेरे पास कहां आए हो? जहां आपकी पैठ है, वहीं से सब काम होता है। मंत्रीजी का सुझाव सुन सुदामा अपने कृष्ण के पास पहुंच गए और उक्त अफसर के ट्रांसफर की मांग कर डाली। लेकिन बताते हैं कि कृष्ण ने भी सुदामा की गुहार पर ध्यान नहीं दिया और नानुकुर करने लगे। यह बात सुदामा को नागवार गुजरी और वे कृष्ण की कृपा से मिली सरकारी गाड़ी छोड़कर अब उनसे मिलने आँटो से जाते हैं।



माननीय का किस-किस पर वरदहस्त

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक मंत्री को सत्ता के सुपर पावर के रूप में गिना जाता है। दरअसल, ये माननीय सीएम बनने का सपना संजोए हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये सरकार में एक दमदार और ताकतवर विभाग के मंत्री बने हुए हैं। इनकी छत्रछाया में प्रदेश की राजनीतिक, प्रशासनिक वीथिका के साथ ही मीडिया जगत में भी कई लोगों को संरक्षण मिल रहा है। इनके एक ऐसे ही संरक्षण की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल, विगत दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी का विवाद जिस तरह हाईप्रोफाइल मामला बना है, उसमें कई लोग घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में माननीय ने विवाद को संभालने की जिम्मेदारी ली है। इसकी वजह यह है कि उक्त अधिकारी और इस मामले में बाहर वाली का किरदार निभाने वाली भी माननीय के जिले की हैं। ऐसे में माननीय ने मोर्चा संभालते हुए अधिकारी की पत्नी को फोन पर समझाइश दे डाली कि आप विचलित न हों। इस मामले में पुलिस में शिकायत कराने की जरूरत नहीं है। इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। बताया जाता है कि माननीय की बात मानकर अधिकारी की पत्नी ने केस दर्ज कराने की अपनी मंशा त्याग दी है। इस मामले में लोगों का कहना है कि दरअसल, मंत्रीजी का वरदहस्त केवल अधिकारी पर ही नहीं बल्कि उन पर भी था, जिनके कारण अधिकारी और उनकी पत्नी में विवाद बढ़ा था।

अब भाव नहीं दे रहे

प्रदेश की नौकरशाही में कुछ अफसर इस कदर मिलनसार हैं कि वे शुरू से कनिष्ठों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। उनकी मिलनसारिता के कारण प्रशासनिक वीथिका में उनकी भरपूर सराहना होती है। वहीं कुछ अफसर ऐसे होते हैं, जो अपनों से भी दूरी बनाकर रखते हैं। ऐसे ही एक अफसर इन दिनों मंत्रालय की पांचवीं मंजिल पर आसीन हैं। जब ये साहब पावरफुल नहीं थे, तब भी वे नवागत अफसरों से मिलते नहीं थे। नवागत अफसर बड़ी चाह के साथ उनसे मिलने के लिए पहुंचते थे, लेकिन साहब उन्हें समय ही नहीं देते थे। अब ये साहब प्रदेश के सबसे पावरफुल अफसर बन गए हैं। ऐसे में हर अफसर की यही कोशिश रहती है कि वह साहब से किसी न किसी तरह रूबरू हो सके। लेकिन साहब का स्वभाव पहले से और कड़क हो गया है। पहले तो वे अफसरों से मिलते नहीं थे, लेकिन अब तो किसी को भाव भी नहीं दे रहे हैं। साहब की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में उनके खिलाफ अफसरों का एक वर्ग संगठित हो रहा है, वहीं सरकार के खिलाफ भी माहौल बन रहा है।

भ्रष्टों का जमावड़ा

प्रदेश सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जिस विभाग के मंत्री बनते हैं उस विभाग में भ्रष्टों का जमावड़ा हो जाता है। यही नहीं मंत्रीजी अपने क्षेत्र में भी भ्रष्ट अफसरों की महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करा लेते हैं। इसको लेकर तो प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक कहावत भी बना दी गई है कि 'मंत्रीजी हैं जहां, भ्रष्टाचार है वहां।' इस कहावत को चरितार्थ करते हुए मंत्रीजी ने उद्यानिकी विभाग में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले अफसर को अपने जिले में पदस्थ करा लिया है। गौरतलब है कि मंत्रीजी अपनी करतूतों के लिए शुरू से ख्यात हैं। पिछले दिनों उन्होंने मंच पर एक नाई से दाढ़ी बनवाकर उसे 50 हजार रुपए देने का प्रहसन भी किया था, लेकिन मंत्रीजी को शायद उसी वजह से कोरोना भी हो गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी मंत्रीजी ने कई ऐसे कार्य किए हैं, जो एक राजनेता की छवि के अनुरूप नहीं रहे हैं। लेकिन मंत्रीजी अपने समाज की दुहाई देकर अपनी करनी को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं।



मुंबई फिल्म इंडस्ट्री लोगों की हत्या करती है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाती है, महिलाओं का वहां अपमान किया जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुंबई पुलिस चुपचाप बैठी रहती है। ऐसे में जब इंडस्ट्री पर आरोप लग रहे हैं तो बवाल क्यों मचा है।

● रूपा गांगुली



पाकिस्तान में हर तानाशाह ने औसतन 9 साल राज किया। इमरान के दो साल पूरे हो गए हैं। इससे ज्यादा वो सरकार नहीं चला पाएंगे। जिन्होंने सरकार और उसके स्पॉन्सर्स के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें कोर्ट में घसीटा जा रहा है। उनके परिवारों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये सच्चाई है कि चुनी हुई सरकारों के हाथ भी बंधे होते हैं। यहां कठपुतली सरकार है।

● नवाज शरीफ



मुझे लगता है धोनी उन्हीं खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों विभागों में अच्छा कर सकते हैं। एक बॉलर के लिए कोई भी दिन खराब हो सकता है लेकिन वह एक अच्छा कैच पकड़ कर मैच बदल सकता है। धोनी इन सबका ध्यान रखते हैं। टी-20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आपको सबकुछ करना पड़ता है।

● दीपक चाहर



पाकिस्तान में को-एजुकेशन के कारण बलात्कार जैसे मामले बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा, लड़के-लड़कियां साथ पढ़ते रहे तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। पिछले कुछ सालों से नैतिकता खत्म हुई है। इसलिए को-एजुकेशन बंद करना चाहिए।

● मौलाना तारिक जमील



मैंने मुंबई को पीओके जैसा ऐसे ही नहीं बोला था। मुझे हरामखोर कहा गया। इसलिए मैंने कहा था कि यह मुंबई जैसा नहीं दिखता, पीओके जैसा दिखता है। फिर उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। भीड़ जमा की और मुझे लिंच किया। मैंने पीओके कहा था। लेकिन मुझे सीरिया कहना चाहिए था। जब राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें इंडिया सीरिया जैसा दिखता है तो कोई उन्हें लिंच नहीं करता या उनका घर तोड़ने नहीं जाता। इन लोगों को दिक्कत क्या है?

● कंगना रनौत

वाक्युद्ध



बिहार में भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन भाजपा की नीयत जदयू के प्रति ठीक नहीं है। पहले वह जदयू को बड़ा भाई बताते थे, अब खुद को बड़ा भाई मानने लगे हैं। यह बात का संकेत है कि बिहार में भाजपा इस कोशिश में लगी है कि विधानसभा चुनाव के बाद वह प्रदेश में प्रमुख पार्टी बन जाए।

● मदनमोहन झा

कांग्रेस अपने और अपने गठबंधन के बारे में सोचे। भाजपा और जदयू में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है, दोनों जुड़वा भाई हैं। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने वाले प्रत्याशियों के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। विपक्षी हमारे बीच के समन्वय को देखकर जल रहे हैं। कोई जले तो हम क्या कर सकते हैं।

● शाहनवाज हुसैन



गरीबी में आटा गीला



मप्र में वित्तीय वर्ष का कर्ज अब 9 हजार करोड़ पहुंचा

प्रदेश सरकार की आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल से अगस्त तक राज्य सरकार बाजार से सात बार कर्ज ले चुकी है। भाजपा सरकार जबसे बनी है उसने साढ़े 5 माह के कार्यकाल में 7 हजार करोड़ रुपए कर्ज लिया। इस तरह नई सरकार बनने के बाद प्रतिमाह औसतन 1200 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया जा चुका है, हालांकि अब इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 12 अगस्त को लिया गया कर्ज लगातार सातवां कर्ज था। 13 सितंबर के पहले सप्ताह में जो कर्ज लिया गया वह इस सरकार का आठवां कर था। हाल ही में सितंबर माह की शुरुआत में लिए गए कर्ज से मध्यप्रदेश पर कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 8 हजार करोड़ रुपए हो गया था, जबकि अब यह बढ़कर 9 हजार करोड़ रुपए हो गया है। बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने और अनेक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन के नाम से यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लेती है। राज्य सरकार को इस समय विकास कार्य के बजाय जरूरी खर्च चलाने के लिए नगद राशि की आवश्यकता है। प्रदेश में कर्ज का ग्राफ लगातार बढ़ने से इस वित्तीय वर्ष में लगातार कर्ज लेने का सिलसिला बना हुआ है। जानकारी के अनुसार ऐसा कोई महीना नहीं बीता जब सरकार को कर्ज लेने के लिए बाजार का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा हो। कोरोनाकाल में प्रदेश की आमदनी पर बड़े वित्तीय प्रभाव का असर है कि अब सरकार माह में दो से तीन बार कर्ज लेने के लिए निवेशकों के पास जा रही है। गत दिनों ही शिवराज सरकार ने करीब 22 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में फसल बीमा के 4686 करोड़ रुपए डाले हैं।

सात हजार करोड़ रुपए नुकसान होने का अनुमान है। सरकार की आय के मुख्य स्रोत वाले विभाग आबकारी, खनिज और परिवहन में बड़ा घाटा हुआ है। अप्रैल से जुलाई की अवधि में करीब 3200 करोड़ रुपए का नुकसान एसजीएसटी और आईजीएसटी में झेलना पड़ा था। यह राशि पिछले वर्ष के मुकाबले 45 फीसदी से कम है। इसी तरह सरकार को खनिज से होने वाली आय में भी नुकसान हुआ है। बसों का संचालन शुरू नहीं होने से भी सरकार को बड़ी राशि का नुकसान झेलना पड़ा। एक आंकलन के मुताबिक सरकार को चार महीने में लगभग 46 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार को अब तक की स्थिति में प्रत्येक माह एक हजार से ग्यारह सौ करोड़ रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है।

वित्त विभाग के अनुसार राज्य कर की तरह केंद्रीय करों में भी राज्य सरकार को इस बार भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्रीय करों से राज्य को मिलने वाला हिस्सा इस बार 50 हजार करोड़ से नीचे ही रहने का अनुमान है। मध्यप्रदेश को इस बार वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों से जो राशि मिलेगी वह पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम होगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार को लगभग 18 हजार रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरह अब राज्य और केंद्रीय करों को मिलाकर मप्र को करीब 35 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान सहन करना पड़ सकता है। जिसका सीधा असर राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा।

● सुनील सिंह

म प्र लगातार कर्ज के बोझ तले दबता चला जा रहा है। आलम यह है कि विकास योजनाओं के लिए सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण आर्थिक तंगी झेल रही मध्यप्रदेश सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। दरअसल सरकार के आंकलन के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र और राज्य करों में करीब 35 हजार करोड़ से अधिक के नुकसान का अंदेशा है। निकट भविष्य में प्रदेश की विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर इस नुकसान का असर दिखाई दे सकता है। प्रदेश सरकार के ताजा अनुमान के मुताबिक अब राज्य सरकार को करीब 16,972 करोड़ 89 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को पिछले वर्ष राज्य कर से 65,273 करोड़ 74 लाख रुपए मिले थे लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष में यह राशि घटकर महज 47,801 करोड़ रुपए तक ही सीमित होने की संभावना है। यानी सरकार को पिछले वर्ष के मुकाबले बड़ी राशि का नुकसान इस बार झेलना पड़ेगा।

प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर इस समय उपचुनाव भी होना है। ऐसे में गरीब, किसान और युवा मतदाताओं को लुभाने राज्य सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। कई कार्यों के भूमिपूजन का सिलसिला भी जारी है। साथ ही विधानसभा उपचुनाव से पहले गरीब कल्याण सप्ताह में सरकार पूरी उदारता दिखा रही है। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कोरोना के चलते सरकार की आय के स्रोत सुस्त पड़े हैं। हर विभाग में नुकसान देखने मिल रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा लगातार खातों में पैसा डालने का काम चल रहा है। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय अनुशासन का दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में खासतौर से विधानसभा उपचुनावों के बाद प्रदेश की योजनाओं और कार्यक्रमों पर इसका सीधा असर भी देखने को मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह चुनाव आयोग प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस कारण सरकार के पास समय कम बचा है। ऐसे में सभी वर्गों को साधने की कोशिश अंतिम चरणों में है। बता दें, कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकार ना तो कोई भूमिपूजन कर पाएगी और ना ही लोकार्पण के कार्यक्रम। इतना ही नहीं आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं ले सकेगी। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर घोषणाएं और भूमिपूजन के कार्यक्रम उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किए जा रहे हैं।

प्रदेश में राजस्व में आई कमी का असर दिखने भी लगा है। पिछले माह के अंत तक राज्य सरकार को मिलने वाले टैक्स में ही लगभग साढ़े



मप्र की कांग्रेस सरकार को गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को उपचुनाव में पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके लिए पार्टी सर्वे कराकर प्रत्याशी उतार रही है। वहीं सिंधिया को घेरने के लिए उनके करीबी दोस्त सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को चुनावी चौसर पर उतारा जा रहा है।

मप्र की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भले ही अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन यहां की सियासत जोरों पर है। सत्ताधारी भाजपा को इन चुनावों में मात देने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करनी है इसलिए जोड़-तोड़ की रणनीति पर भी अंदरूनी तौर पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस का असली सिरदर्द ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिसका 28 में से 16 सीटों पर गहरा प्रभाव है। हालांकि यहां के लोगों में सिंधिया को लेकर हलकी नाराजगी जरूर है लेकिन ये सिंधिया को उनके के गढ़ में मात देने के लिए काफी नहीं है। ऐसे में सिंधिया गढ़ को हिलाने के लिए कांग्रेस एक मास्टर प्लान बना रही है जिसमें राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सिंधिया के किले में सेंध लगाते हुए दिखाई देंगे।

दरअसल, ग्वालियर-चंबल अंचल की सीटों पर सिंधिया का अपना क्षेत्र है यहां उनका अपना दबदबा कायम है। इस संभाग का कुछ इलाका राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि सचिन पायलट सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा सकते हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का यह भी मानना है कि पायलट चुनाव-प्रचार में सिंधिया पर भारी पड़ सकते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मप्र कांग्रेस का पायलट को प्रचार में लाना जातिगत रणनीति के लिहाज से भी फायदा पहुंचा सकता है। संभाग की 16 सीटों पर गुर्जर-राजपूत वोट ज्यादा संख्या में हैं। इनमें से भी 9 सीटें गुर्जर बाहुल्य हैं। इन 9 में से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो

स्टार प्रचारक हैं पायलट

सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ग्वालियर में उपचुनाव के प्रचार के लिए सचिन पायलट ने सहमति दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री व पीसीसी चीफ कमलनाथ की उनसे फोन पर चर्चा हुई है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर गुर्जर वोट बैंक व युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने ये प्लान तैयार किया है। सचिन पायलट के जरिए गुर्जर वोटों को साधने की कांग्रेस की कोशिश होगी। इससे पहले भी मप्र में सचिन पायलट चुनाव प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस इस फैवटर को भुनाने से कभी पीछे नहीं हटेगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का काम दृढ़ मानना है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का केंद्रीय आलाकमान इस मामले में एक्शन लेता है या फिर सचिन पायलट की मर्जी को त्वज्जो दी जाती है।

राजस्थान के जिलों से सटी हैं। राजस्थान के दिग्गज गुर्जर नेता सचिन पायलट यहां पर अपना असर छोड़ सकते हैं। पायलट का इन सीटों पर प्रचार करना भाजपा और सिंधिया की परेशानी बढ़ा सकता है। इसी सोच के साथ पायलट को कम से कम इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस आलाकमान भी इसे सीरियसली ले रहा है।

जब से पायलट के मप्र में चुनाव प्रचार की खबरें मीडिया में आई हैं, राजस्थान सहित अन्य लोगों में भी जिज्ञासा बनी हुई है कि दो जिगरी दोस्त जब एक-दूसरे के खिलाफ सामने होंगे तब क्या होगा। वे पार्टी के बारे में बोलते हैं या

एक-दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। हम उम्र नेता पायलट और सिंधिया की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। ये फोटो उस वक्त की हैं जब सिंधिया कांग्रेस में थे और वह दोनों अक्सर एक साथ मंच साझा करते थे।

ऐसे में कांग्रेस ने हाल के दिनों में राजस्थान में अपने बगावती तेवर से चर्चा में आए तेजतरार नेता सचिन पायलट को इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में उतारने की योजना बनाई है। सचिन पायलट को मप्र में चुनाव प्रचार में उतारने के पीछे कांग्रेस की सोची-समझी रणनीति है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट एक-दूसरे के दोस्त रहे हैं। पायलट ने जब राजस्थान में बगावती तेवर दिखाए थे, तो सिंधिया ने उनके समर्थन में बयान भी दिया था। गौर करने वाली बात है कि मप्र में जिन 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें से अधिकतर सीटें ग्वालियर-चंबल इलाके की हैं, जिसे सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र वाला माना जाता है। इसी साल मार्च में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस लिया और भाजपा में शामिल हुए, उस समय सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दिया था। इसके बाद प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। बाद में तीन और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। एक सीट पर निलंबन और एक निर्दलीय के इस्तीफा देने से रिक्त सीटों की संख्या 27 हो गई। वहीं गत दिनों पहले कांग्रेस के ब्यावरा विधायक के निधन के बाद अब 28 सीटें खाली हो चुकी हैं। इसे लेकर मप्र विधानसभा ने अधिसूचना जारी किया है और केंद्रीय चुनाव



आयोग को यह अधिसूचना भेज दी गई है।

सिंधिया समर्थक विधायक इन्हीं इलाकों से आते हैं। मप्र का यह इलाका राजस्थान से सटा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि सचिन पायलट का चुनाव प्रचार करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। कुछ दिनों पहले मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने सचिन पायलट से ग्वालियर-चंबल संभाग की सीटों पर चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया था। हालांकि पायलट की तरह से कोई अधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है लेकिन उड़ते-उड़ते खबर आ रही है कि पायलट ने न तो हां कहा है और न ही ना। करीबी सूत्रों के अनुसार पायलट का कहना है कि मेरे लिए पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है। मैं एक कांग्रेस नेता हूँ और पार्टी जब चाहे जहाँ मेरा उपयोग कर सकती है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा।

वैसे भी राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की आग फिर से सुलगती हुई दिख रही है। सचिन पायलट पहले ही इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर गुर्जर आरक्षण की फाइल आगे बढ़ाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में गुर्जरों के लिए पायलट की पैठ पहले से पक्की होती दिख रही है। वहीं किरोड़ी सिंह बैसला भी राज्य सरकार एवं अपनी ही केंद्र सरकार को गुर्जर आरक्षण और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के नाम पर आखें दिखा चुके हैं। गहलोत सरकार को 15 दिन और केंद्र सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है, कुछ न होने पर दिल्ली कूच की चेतावनी भी दी जा चुकी है। ऐसे में यहाँ गुर्जर नेता होने के चलते सचिन पायलट की भूमिका भी अहम हो जाती है। वैसे पायलट ने गहलोत सरकार में गुर्जर

प्रियंका गांधी करेंगी हिसाब बराबर

ज्योतिरादित्य सिंधिया से हिसाब बराबर करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके गढ़ में आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का कार्यक्रम कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि 1 तीर से 2 निशाने साधे जा सकें। प्रियंका गांधी दतिया जिले में स्थित पीतांबरा देवी के दर्शन के लिए आ रही हैं। पीतांबरा पीठ ग्वालियर-चंबल संभाग में आता है। इस दौरान वह यहाँ स्थानीय नेताओं से भी मुलाकात और रोड शो करेंगी। गांधी परिवार को पता है कि मप्र सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही गिरी है। कांग्रेस भी उसी हिसाब को चुकता करने लिए प्रियंका को उनके क्षेत्र में उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने कभी उनके ऊपर सीधा हमला नहीं किया है। ग्वालियर-चंबल में मजबूत नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को प्रियंका गांधी से नई उम्मीद है। हालांकि अभी उनके आने की तारीख पक्की नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और भाजपा नेता शाहवर आलम का कहना है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट हार गए हैं, वह क्या नेतृत्व करेंगे। उप्र में भी प्रियंका गांधी 2 बार घूमि हैं, क्या परिणाम आया है। ऐसे में मप्र क्या देश में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्वालियर-चंबल की 16 सीटें हम जीतेंगे।

आरक्षण का मामला उठाने की बात कहकर अपनी सरकार का तो बचाव कर लिया है। गुर्जर आरक्षण का प्रभाव मप्र में भी पड़ना निश्चित है। एक नेशनल लीडरशिप होने के नाते भी वहाँ के गुर्जरों में भी सचिन पायलट की पैठ होना पक्का है। राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में सियासी घटनक्रमों के बाद गुर्जरों में सचिन पायलट को लेकर सहानुभूति भी है। उस समय सिंधिया समेत राजस्थान के अन्य भाजपा नेताओं ने पायलट के साथ ज्यादाती होने की बात कहकर उनका पक्ष लिया था लेकिन वापस लौटने के बाद विधानसभा में पायलट ने उन सभी नेताओं को घेरना जारी रखा जिससे उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा।

पायलट को मप्र के सियासी मैदान में प्रचार के लिए उतारने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास स्टार प्रचारकों के नाम पर कुछ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह की स्वीकार्यता संगठन में भले ही कितनी हो परंतु मप्र की सियासत में जो उठापटक हुई, उसके पीछे कहीं न कहीं दिग्गी राजा की अनभिज्ञता को भी माना जाता है। कमलनाथ स्वयं भले ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माहिर खिलाड़ी हों परंतु हजारों की भीड़ को मोहित करने वाला भाषण देने में सक्षम नजर नहीं आते।

कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी 2018 से पहले तक किसी न किसी तरीके से जनता के आकर्षण का केंद्र बन जाते थे परंतु कांग्रेस पार्टी के सरकार में आने और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, फैसले लिए, उससे कहीं न कहीं जीतू की सीमा मीडिया प्रभारी तक सीमित रह गई है। सज्जन सिंह वर्मा भी इतना बड़ा जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं देते।

बात करें दूसरी पीढ़ी के नेताओं यानी यूथ ब्रिगेड की तो दिग्विजय सिंह के युवराज जयवर्धन सिंह और कमलनाथ के उत्तराधिकारी नकुलनाथ अभी तक स्टार किड्स की पहचान से बाहर तक नहीं निकल पाए हैं। पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म के कारण उन्हें पद तो मिल गए परंतु जनता में जादू बिखरने की कला अभी तक नहीं सीख पाए हैं। दोनों में अपने पिताओं के 10 फीसदी गुण भी नजर नहीं आते। हालांकि दोनों खुद को मप्र का भावी मुख्यमंत्री मानते हैं। कुल मिलाकर कमलनाथ की टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समकक्ष नजर आता हो। ऐसे में कमलनाथ को उनकी बराबरी करने के लिए ही सचिन पायलट नाम का ब्रह्मास्त्र चाहिए जो न केवल शिवराज और सिंधिया को काट कर सके, कमलनाथ को सत्ता का सिंहासन भी दिला सके।

● कुमार राजेन्द्र

प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में भ्रष्टाचारी काकस ने सवा अरब कीमत की औद्योगिक जमीन के भू-खंड काटकर लोगों को बेच डाले। खास बात यह है कि इस जमीन को बेचने के पहले भू माफिया ने वाकायदा फर्जी दस्तावेजों के सहारे जिम्मेदार अफसरों से सांठगांठ कर सारी अनुमतियां भी हासिल कर लीं। फिलहाल भू माफिया के कारनामों में यह नया तरह का कारनामा भी जुड़ गया है। अब तक सरकारी, सीलिंग, नजूल से लेकर गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनों के ही वारे-न्यारे करने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब इस तरह का मामला सामने आया है। यह पूरा मामला इंदौर की चर्चित मालवा वनस्पति एवं कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जमीन से जुड़ा हुआ है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जब जिला प्रशासन द्वारा कमेटी बनाकर जांच कराई गई तो इस पूरे खेले की सच्चाई सामने आ गई। जांच में पाया गया कि रसूखदार माफिया ने इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगम से भी अनुमति हासिल कर ली थी। इस खुलासे के बाद अब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही दी गई अनुमतियां निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में कई विभागों के अफसरों की मिलीभगत की बात पूरी तरह से सामने आ रही है। इसकी वजह है आम आदमी को पूरे सही दस्तावेज होने के बाद भी यह अनुमतियां लेने में उसकी चप्पलें तक घिस जाती हैं, लेकिन इन माफियाओं को न केवल आसानी से यह सभी अनुमतियां मिल गईं, बल्कि उनकी लगातार बिक्री होती रही और जिम्मेदार पूरी तरह से आखें बंद किए रहे। जिला प्रशासन द्वारा मालवा वनस्पति की भूमि पर स्वीकृत कराए गए औद्योगिक प्लॉट के नक्शों की जांच के चलते प्रारंभिक तौर पर अनियमितता सामने आने के बाद जिला पंजीयक कार्यालय ने उक्त संपत्ति की खरीदी-बिक्री के पंजीयन पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने मालवा वनस्पति की औद्योगिक जमीन पर मंजूर कराए गए नक्शे में नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद उसकी जांच कराए जाने के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान पता चला कि उक्त भूमि के एफएआर में जहां वृद्धि कराकर भारी मुनाफा कमाया गया है, वहीं इंडस्ट्रीयल बेल्ट के रूप में मंजूर कराए गए नक्शे में रोड की चौड़ाई और बगीचे की भूमि का भी ख्याल नहीं रखा गया। इन अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच के बाद प्रशासन द्वारा पूरे मामले की जांच कर प्लॉट विक्रेताओं को जहां नोटिस दिए जाने और नक्शा निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है, वहीं निवेशकों और उद्यमियों को नुकसान से बचाने के लिए उक्त भूमि के प्लॉटों के पंजीयन पर भी

औद्योगिक जमीन को भू-खंड बनाकर बेचा



400 से ज्यादा नामांतरण भी हो गए

एक तरफ ये जमीनें बिकती गईं, दूसरी तरफ बिल्डरों-रसूखदारों ने राजस्व अमले के साथ ही मिलकर नामांतरण-डायवर्जन से लेकर अनुमतियां भी हासिल कर लीं। प्रशासन ने अपनी जांच में 400 से ज्यादा इन जमीनों पर हुए नामांतरणों को भी पकड़ा, जिनमें से सर्वाधिक नामांतरण तत्कालीन नायब तहसीलदार आलोक पारे और अपर तहसीलदार अजीत श्रीवास्तव द्वारा करना पाए गए। 431 से अधिक पट्टों की जांच में तत्कालीन तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई। शिकायत होने पर नामांतरण करने वाले ही कुछ तहसीलदारों ने स्वमोटो में धारा 32 में कुछ प्रकरणों को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की। ज्यादातर नामांतरण 2007-08 और उसके बाद ही किए गए और फिर यह मुद्दा विधानसभा के बाद जिला योजना समिति की स्थानीय बैठक में भी जोर-शोर से उठा, जिसके चलते तत्कालीन कलेक्टर ने दोनों तहसीलदारों पारे और श्रीवास्तव को निलंबित भी कर दिया। इन दोनों ने ही 600 से अधिक पट्टों में से 400 से ज्यादा का नामांतरण किया और बताया जाता है कि पौने 200 से ज्यादा पट्टों के रिकॉर्ड भी गायब हो गए।

रजिस्ट्रार कार्यालय ने फिलहाल रोक लगा दी है। कंपनी की तरफ से डायरेक्टर पांडुरंग ने भागीरथपुरा की जमीन सर्वे नं. 81, 82 (पार्ट), 83, 84/2, 85 (पार्ट), 86/1/1 (पार्ट), 86/2, 86/3 (पार्ट) एवं 87/1/1 (पार्ट) की कुल रकबा 11.484 हैक्टेयर में से 9.584 यानी लगभग 25 एकड़ जमीन पर फ्लोटेड फैक्ट्री उपयोग हेतु 7 दिसंबर 2018 को जगह का अनुमोदन करवाया था। जिसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश के अभिन्यास मंजूरी के बाद नगर निगम ने 13 मई 2019 को लेटेड औद्योगिक उपयोग की भवन अनुज्ञा जारी कर दी थी। इसके बाद उक्त जमीन पर डेवलपर्स फर्म ने प्लॉट तक का निर्माण किया। इसके चलते एमओएस, सडकों की चौड़ाई से लेकर अन्य अधिकतम क्षेत्र हासिल कर लिया गया, जो कि स्वीकृत एफएआर से लगभग दोगुना है। जबकि विकासकर्ता को फ्लोटेड फैक्ट्री की अनुमति के मुताबिक अलग-अलग मंजिलों पर प्रकोष्ठों का पंजीयन करवाकर विक्रय करना था, लेकिन इसकी बजाय भूखंडों की रजिस्ट्री कर बेच दिया गया।

अधिकारियों की कमेटी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में यह घोटाला 125 करोड़ से ज्यादा का है। हालांकि इसकी कीमत की गणना कलेक्टर

गाइडलाइन के आधार पर की गई है, बाजार दर तो इससे अधिक है। खास बात यह है कि इस जमीन को एक बार शासकीय भी घोषित किया जा चुका था। मालवा वनस्पति एवं कैमिकल्स प्रा.लि. की भागीरथपुरा स्थित यह जमीन शुरू से विवादित रही है। इसी के चलते पूर्व में प्रशासन इसे सरकारी घोषित कर चुका था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जिसमें प्रशासन द्वारा मजबूत तरीके से अपना पक्ष नहीं रखने से इस संबंध में लिया गया प्रशासनिक फैसला खारिज हो गया। इस मामले की प्रकाश माहेश्वरी द्वारा की गई शिकायत की जांच में अपर कलेक्टर अजयदेव शर्मा, मुख्य नगर निवेशक निगम विष्णु खरे और संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एसके मुदगल को शामिल किया गया था। इन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की रजिस्ट्री पहले कभी नहीं देखी गई है। इसके लिए कागजों को बड़ी होशियारी से तैयार किया गया और गोलमोल तरीके से कहीं भूखंड, तो कहीं फ्लोटेड एरिया बेचने की बात कही गई। रजिस्ट्री में प्रत्येक भूखंड के दो क्षेत्रफल लिखे गए। फिलहाल प्रशासन ने यहां रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगा रखी है।

● लोकेंद्र शर्मा

पी सीपीएनडीटी एक्ट लागू करने के बाद एक-एक गर्भवती महिला का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखा जाता है। दरअसल डॉक्टर की सलाह पर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करवाई जाती है, जिसके जरिए ये रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि सोनोग्राफी करवाते वक्त गर्भवती महिला से फार्म एफ भरवाया जाता है, जिसमें नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर भी दर्ज रहता है। इसका उद्देश्य यह है कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सोनोग्राफी के जरिए लिंग पता लगाकर बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या प्रदेश सहित देशभर में होती रही है। उसी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने यह एक्ट बनाया और सभी सोनोग्राफी सेंटरों को इसके दायरे में लिया गया है। प्रशासन ने समीक्षा के दौरान पाया कि बीते 3 सालों का 8 हजार गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अब कागजों पर लापता इन गर्भवती महिलाओं की तलाश करवाई जा रही है।

कुछ साल पहले तक सोनोग्राफी सेंटरों पर आसानी से लिंग परीक्षण हो जाता था, जिसके चलते लड़के और लड़कियों की जन्म दर में काफी अंतर आने लगा। देश के कई क्षेत्र तो ऐसे हैं, जहां 100 लड़कों के जन्म पर 70 से 80 लड़कियों की ही जन्म दर रह गई। इसके पश्चात केंद्र सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया, जिसमें लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया और ऐसा करने वाले चिकित्सकों, सोनोग्राफी सेंटरों को सजा और जुर्माने के दायरे में लाया गया और गर्भपात करवाने वालों को भी सजा देने के कठोर कानूनी नियम बनाए गए। इतना ही नहीं, एक-एक सोनोग्राफी मशीन पर शासन-प्रशासन ने चिप लगवाई, ताकि हर सोनोग्राफी की ट्रैकिंग की जा सके।

दरअसल डॉक्टरों की सलाह पर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करवाई जाती है, लेकिन उन सभी का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग रखता है और निजी, सरकारी अस्पतालों से लेकर जितने भी निजी सोनोग्राफी सेंटर, लेब हैं उन सभी को लाइसेंस देते वक्त पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी जाती है और सभी सेंटरों पर लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है। इस आशय के सूचना बोर्ड भी



8 हजार गर्भवती महिलाएं लापता

लगवाए गए हैं। हालांकि चोरी-छुपे लिंग परीक्षण की शिकायतें सामने आती हैं, जिसके चलते प्रशासन पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत सोनोग्राफी सेंटरों को सील और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अभी प्रशासन को समीक्षा के दौरान यह तथ्य पता चला कि बीते 3 सालों में गर्भवती महिलाओं की जितनी भी सोनोग्राफी हुई उसकी तुलना में उनके भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर और पीसीपीएनडीटी के प्रभारी पवन जैन ने इस मामले की जांच शुरू की।

स्वास्थ्य विभाग में पीसीपीएनडीटी सेल गठित है और जिला एवं महिला बाल विकास अधिकारी इसके प्रभारी रहते हैं। पीसीपीएनडीटी ने वर्ष 2018 में 6549 गर्भवती महिलाओं की सूची ई-मेल के जरिए प्रशासन को भेजी, जिनमें से लगभग साढ़े 4 हजार गर्भवती महिलाओं की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इसी तरह वर्ष 2019 में 5 हजार 115 और वर्ष 2020 में मार्च के महीने तक ही 660 गर्भवती महिलाओं की जानकारी दी गई। इनमें से साढ़े 3 हजार गर्भवती महिलाओं की जानकारी बाद में अप्राप्त रही। इस तरह इन तीन सालों में ही लगभग 8

हजार गर्भवती महिलाओं की जानकारी नहीं मिली। एक्ट के तहत गठित जिला सलाहकार समिति के सदस्यों ने भी पूर्व की बैठकों में गर्भवती महिलाओं का भौतिक सत्यापन कर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन को यह जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। लिहाजा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी डॉ. सीएल पासी को नोटिस भी थमाया गया है कि वह 15 दिन में इस साल और पूर्व के वर्षों की लंबित गर्भवती महिलाओं के भौतिक सत्यापन की जानकारी उपलब्ध करवाएं। संभवतः इनमें से कुछ महिलाओं के गर्भपात हुए होंगे, वहीं कई महिलाओं ने अन्य शहर यानी मायके में जाकर डिलेवरी करवाई होगी तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो घरों में ही प्रसव हो जाते हैं। अपर कलेक्टर पवन जैन का कहना है कि बीते 3 सालों का रिकॉर्ड अपडेट कराया जा रहा है, ताकि हकीकत सामने आ सके। इसका एक उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना भी है, क्योंकि घरों में प्रसव होने पर मां और नवजात बच्चे को खतरा रहता है। यही कारण है कि शासन-प्रशासन लगातार संस्थागत प्रसव, यानी अस्पतालों में डिलेवरी को प्रोत्साहित करता रहा है। इसके लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक से लेकर जननी एक्सप्रेस के जरिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

● अरविंद नारद

कोरोनाकाल में घट गई थी सिजेरियन डिलेवरी

कोरोनाकाल में वायु, ध्वनि सहित अन्य प्रदूषणों से राहत मिली, क्योंकि कर्फ्यू-लॉकडाउन के कारण पूरा देश ही बंद रहा। वहीं इस दौरान यानी अप्रैल-मई के महीने में इंदौर सहित देशभर में सिजेरियन डिलेवरी की संख्या भी घट गई। बीते कुछ वर्षों में सामान्य के बजाय ऑपरेशन के जरिए अधिक डिलेवरी करवाई जाती है, ताकि निजी अस्पतालों में डॉक्टर और अन्य इलाज का बिल अधिक वसूल किया जा सके। कोरोना काल में चूंकि अधिकांश अस्पताल और डॉक्टर काम पर कम थे, लिहाजा सिजेरियन, यानी ऑपरेशन से डिलेवरी की संख्या घटी और सामान्य डिलेवरी बढ़ गई। उसके बाद हालांकि फिर सिजेरियन डिलेवरी ज्यादा होने लगी है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिन निजी या सरकारी अस्पतालों या पैथालॉजी लेब में सोनोग्राफी मशीन लगी है, उनका पंजीयन स्वास्थ्य विभाग से कराना अनिवार्य है। हर सोनोग्राफी मशीन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है, जिससे एक-एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी का रिकॉर्ड रखा जाता है।

म प्र में सियासी दलों के केंद्र बिंदु में इन दिनों किसान हैं। किसान कर्जमाफी, किसान सम्मान निधि से लेकर सियासी दल हर आयोजन में किसान और किसान से जुड़े मुद्दों पर बयान देकर किसान वोटर को साधने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर सियासी संग्राम उठ खड़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के किसान बजट को घटाने का आरोप लगाते हुए किसान हित की योजनाओं पर ताला लगाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी योजनाओं को एक के बाद एक बंद कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे के मुताबिक, राज्य सरकार ने कृषक समृद्धि योजना, सूरज धारा योजना, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी योजना, खेत तीर्थ योजना, अन्नपूर्णा योजना, कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना में बजट घटाकर योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर ली है।

कांग्रेस का आरोप है कि कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों की फसलों पर समर्थन मूल्य के ऊपर प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने बजट में सिर्फ 3000 रुपए का प्रावधान किया है। इससे साफ है कि प्रदेश सरकार किसानों को पूर्व घोषित प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सूरज धारा योजना के तहत सरकार ने बजट प्रावधान शून्य कर दिया है। जो इस बात को बताता है कि योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को 75 फीसदी तक बीज के लिए मिलने वाला अनुदान अब बंद हो गया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए योजना में बजट का प्रावधान शून्य करने और महिला कृषक को योजनाओं का लाभ नहीं देने का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में भी कांग्रेस ने बजट का प्रावधान शून्य करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को खाद्यान्न किस्मों के बीज उपलब्ध कराने के बजट को भी जीरो कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन और ट्रैक्टर कृषि उपकरणों पर अनुदान जैसी योजनाओं में बजट आधा कर योजना को बंद करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने जवाबी हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता रजनीश

मप्र में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने मोर्चा सभाल लिया है। दोनों पार्टियों का पूरा फोकस किसान पर है। इससे यह साफ दिख रहा है कि दोनों पार्टियां किसानों के भरोसे उपचुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

किसान भरोसे जीत



कृषि विधेयक का मप्र में खास विरोध नहीं

केंद्र के कृषि विधेयकों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब सहित देश के सात राज्यों में विरोध देखा जा रहा है, हालांकि मप्र में अब तक इसका खास विरोध नहीं दिखाई दिया है। केवल ग्वालियर-चंबल अंचल में छिटपुट काम प्रभावित हुआ है। जबलपुर में किसान संघों का जुबानी विरोध सामने आ रहा है। मैदानी गतिविधियां नहीं के बराबर हैं। मालवा-निमाड़ अंचल में छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। विधेयकों का ग्वालियर-चंबल अंचल के कुछ जिलों में किसान, व्यापारी व मंडी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। व्यापारी व मंडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इससे कृषि मंडियों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उबरा में किसान कुछ दिन से धरना दे रहे हैं। श्योपुर में कृषि मंडी में व्यापारी व कर्मचारी अलग-अलग धरना दे रहे हैं। मुरैना, शिवपुरी में हड़ताल नजर आई तो भिंड-दतिया में कोई विरोध सामने नहीं आया।

अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं को कभी बंद नहीं किया गया। तीर्थ दर्शन योजना में भी भाजपा सरकार ने शुरू की थी योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस सरकार में हुआ है। भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक जनता की योजनाओं पर भाजपा राजनीति नहीं करती है।

बहरहाल, प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के फोकस में किसान वोटर हैं, क्योंकि इस बार उपचुनाव में किसान वोटर ही भाजपा और कांग्रेस की हार और जीत तय करेगा। यही कारण है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसान हित में बड़े फैसले लेकर किसान वोटरों को खुश करने की कोशिश में हैं, तो वहीं किसान कर्जमाफी के बाद किसान हितैषी योजनाओं को बंद करने के आरोप के सहारे कांग्रेस भाजपा को टक्कर देने में लगी हुई है।

गौरतलब है कि उपचुनाव में 28 सीटें सत्ता का स्वरूप तय करेंगी। सत्ता में बने रहने या सत्ता पाने के लिए इन सीटों की अहमियत है। माना जा रहा है कि जो जीता वही सत्ता का सिकंदर होगा। भाजपा यदि दस सीटें भी जीत लेती है तो उसकी सरकार मजबूत हो जाएगी, लेकिन यदि कांग्रेस

सर्वाधिक सीटें जीतती है तो समीकरण बदल सकता है। यही कारण है कि यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। दोनों पार्टियों के नेता एक-दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं।

आम चुनाव से भी अधिक नेता एक-दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं। शब्दों की मर्यादा टूट चुकी है। जो आमने-सामने शिष्टाचार का प्रदर्शन करते थे वे एक-दूसरे को चोर-डाकू, गद्दार जैसे विशेषणों से नवाज रहे हैं। एक-दूसरे को पछड़ने के लिए रोज मुद्दे और नारे गढ़े जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में भी कर्जमाफी ही सर्वाधिक चर्चा में है। दोनों पार्टियों ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। भाजपा पर तोहमत मढ़कर कांग्रेस अपना बचाव करना चाहती है तो भाजपा उसे नए सवालियों पर घेर रही है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्जमाफी बड़ा और निर्णायक मुद्दा था। दरअसल, कांग्रेस और कमलनाथ को यह भान था कि शिवराज सिंह चौहान की छवि किसान हितैषी है। किसानों के लिए भावांतर से लेकर कई योजनाएं भी शुरू हुई थीं। इसकी तोड़ के तौर पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में

कर्जमाफी योजना को आगे रखा था। भाजपा को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस की यह घोषणा उसके द्वारा बीते 15 वर्षों में किए गए किसान हितैषी कार्यों के आगे नहीं टिक पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों ने कमलनाथ के वचन पर भरोसा जताया और कांग्रेस का सत्ता से वनवास खत्म हो गया।

कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजते ही उन्होंने सबसे पहले आदेश 48 लाख किसानों की 54 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी का निकाला। इससे किसानों का भरोसा और बढ़ा, पर यह जितना आसान दिख रहा था, उतना था नहीं। खजाना खाली था और दो लाख रुपए तक का कर्ज चुकाने में लगने वाली राशि इतनी बड़ी थी कि यदि इसे पूरा करने लग जाते, तो दूसरे कोई काम नहीं हो सकते थे। लिहाजा, वित्त विभाग ने पेच फंसाना शुरू किया। कर्जमाफी का ऐसा फॉर्मूला बनाया कि दो खाते वाले, दो लाख रुपए से अधिक कर्ज वाले, खेती के अलावा अन्य कामों के लिए कर्ज लेने वाले किसान दायरे से बाहर हो गए। इसके बाद भी किसानों की बड़ी संख्या बची थी। इनका कर्ज माफ करने के लिए 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत थी, इसलिए इसे तीन चरणों में करने का निर्णय लिया गया। विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कई बार चेतावनी दी कि सरकार किसानों की कर्जमाफी करे। कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप उनके घर जाकर उन्हें कर्जमाफी के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्जमाफी से लेकर कई अन्य वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए हाथ को झटका दे दिया और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। कांग्रेस तब से लेकर अब तक कर्जमाफी के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है। भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं कि किसानों को कर्जमाफी का प्रमाणपत्र पकड़ा दिया, पर कर्जमाफी हुई नहीं। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से विधानसभा में कर्जमाफी के संबंध में प्रश्न किए। कई विधायकों के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने जो जवाब दिए वो सरकार को परेशानी में डालने वाले थे।

विधानसभा में स्वीकार किया गया कि पहले



चरण में दो लाख रुपए तक कालातीत खाते और पचास हजार रुपए तक चालू खाते पर कर्ज वाले किसानों की कर्जमाफी का निर्णय लिया। इसके लिए 20,23,136 किसानों के 7,108 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने के लिए स्वीकृत किए गए। दूसरे चरण में चालू खाते पर एक लाख रुपए तक कर्ज माफ होना था। इसके लिए 6,72,245 खातों के 4,538 करोड़ रुपए के प्रकरण स्वीकृत किए गए। इस प्रकार दोनों चरणों में 26,95,381 खातों का ऋण 11,646 करोड़ रुपए की कर्जमाफी के लिए स्वीकृत किया गया। यदि कर्जमाफी की यह प्रक्रिया पूरी होती तो 5,90,848 किसानों को और लाभ मिलता। कांग्रेस ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया और भाजपा सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच विधानसभा में दिए उत्तर से बैकफुट पर आने की जगह सरकार ने आक्रामकता के साथ कांग्रेस पर पलटवार किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि किसानों की कर्जमाफी नहीं हुई।

विधानसभा में अधिकारियों के स्तर पर झुटि हुई और गलत आंकड़े प्रस्तुत हो गए। जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वहीं, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों के साथ इससे बड़ी धोखाधड़ी कभी नहीं हुई। किसानों का दो लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन नहीं

हुआ। यह मुद्दा इस समय इसलिए ज्वलंत है, क्योंकि प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। भाजपा से वे लोग चुनाव मैदान में होने वाले हैं, जो कर्जमाफी के वचन के सहारे ही सत्ता तक पहुंचे थे। कुछ मंत्री तो कर्जमाफी के कार्यक्रमों में शरीक भी हुए थे।

प्रदेश कांग्रेस के आव्हान पर गत दिनों राजधानी भोपाल के कमला पार्क स्थित रेत घाट पर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेसजनों ने जंगी प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जमकर कोसा। केंद्र सरकार ने जो काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं, आज देश के 62 करोड़ किसान, 250 से अधिक किसान संगठन इस कानून के खिलाफ हैं और मोदी सरकार से इन कानून को वापिस लेने की मांग कर रहे हैं। संघीय ढांचे का उल्लंघन कर संविधान को रौंदकर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर बगैर किसी रायशुमारी के मोदी सरकार द्वारा तीन काले कानूनों को पारित किया गया। कांग्रेस ने इसी कड़ी में हजारों की संख्या में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं किसानों के साथ एकत्र होकर काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर उसका पुरजोर विरोध किया है तथा केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी इन कानूनों को वापिस लिए जाने की मांग का दस सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा।

● रजनीकान्त पारे

उपचुनाव में किसानों के मुद्दे पर मप्र से दिल्ली तक सियासत

प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें आने से पहले ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं। चुनावी समर में जुबानी जंग तेज हो गई है। वार-पलटवार भी शुरू हो चुका है। इस जंग के केंद्र में किसान और उनसे संबंधित मुद्दे ही हैं। इस मुद्दे पर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल वोटों को साधने की जुगत में लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर आपतिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, कमल पटेल जब सदन में कर्जमाफी के सवाल का जबाब दे रहे थे तो क्या उस वक्त शराब पीकर या भांग खाकर बोल रहे थे। पटेल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या उनका अध्ययन। मंत्री कमल पटेल ने कहा, राहुल गांधी व कमलनाथ ने नशे में कर्जमाफी की घोषणा की। अब कोई कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे राहुल गांधी आए या राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। पटवारी को लेकर बोले, सत्ता जाने से लूटखसोट बंद हो गई, इसलिए मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।

सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित और प्रभावित हजारों लोगों को जो मिला है, वह निश्चित ही दुनिया की किसी अन्य परियोजनाओं में इतने बड़े पैमाने पर नहीं मिला होगा, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया गया। शासन करने वालों से लेकर समाज के विभिन्न तबकों, बुद्धिजीवियों, श्रमजीवियों से लगातार संवाद के बाद यह संभव हो पाया। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक के समक्ष सवाल उठाने पड़े, तब परियोजना पर पुनर्मूल्यांकन के लिए निष्पक्ष आयोग गठित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह परियोजना केवल गलत मार्ग अपनाकर ही पूरी की जा सकती है अन्यथा नहीं। हमें सर्वोच्च अदालत में पहली बार छह सालों तक और फिर बार-बार खड़ा होना पड़ा। न्यायालय में हर प्रकार के अनुभव हमने सही तरीके से जांचे और धरातल से जुड़े रहे जनशक्ति के साथ और युवा व महिलाओं के योगदान लगातार सच्चाई को उजागर करते रहे।

मप्र, महाराष्ट्र और गुजरात में हमारी ताकत थे वहां के स्थानीय नागरिक, संगठन और आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, मछुआरे, केवट, व्यापारी आदि। विस्थापितों की हिम्मत और जीवटता के साथ कार्यकर्ता डटे हैं पिछले 35 सालों से। लेकिन वे आज भी न चुप बैठ पा रहे हैं, ना महोत्सव से अपने अनुभवों और सफलताओं को प्रचारित करना चाह रहे हैं। इसीलिए उनकी आंखों के सामने आज भी वे चेहरे, गांव और लोग संघर्ष करते दिख पड़ रहे हैं, जिनका अब तक पुनर्वास बाकी है। क्या वे ऐसी कोई चीज या लाभ मांग रहे हैं, जो कि कानूनी या नीतिगत दायरे से बाहर हो? क्या वे कोई जोर जबरदस्ती से छीन लेना चाहते हैं, किसी लालच में आकर? क्या उन्होंने कभी हिंसा या अवैधता को अपनाया? गांधी जी के चौरीचौरा जैसे आंदोलन की तरह भी कभी माफी नहीं मांगनी पड़ी जबकि वे उन्हीं के अहिंसा के मूल्य को गले लगाके रहे। यह उनके संघर्ष का ही नतीजा था कि वह अब तक एक और 'जालियांवाला बाग' की पुनरावृत्ति नहीं कर पाई। हर हालात में उनके लोग शांति का रास्ता पकड़कर चलते रहे। गलत तो नहीं किया। इससे भी कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हैं। हिंसा के विविध रूपों में से एक होता है विस्थापन। आज महाराष्ट्र, मप्र और गुजरात के 214 किलोमीटर तक फैले 40,000 हेक्टेयर के जलाशय के क्षेत्र में उसके किनारे आज भी डटे हजारों परिवारों का संघर्ष जारी है।

पिछोड़ी, आवल्या, कडमाल, एकलवारा जैसे निमाड़ (मप्र) के मैदानी गांवों से उखाड़कर टिन शेड्स में फेंके गए परिवारों का संघर्ष आज भी जारी है। महाराष्ट्र के चिमलखेड़ी गांव में घरों में भी पानी घुस आया है। मणिबेली की

दावे 35 साल में भी पूरे नहीं



बांध के लाभ के जाल में फंसे तीन राज्य

नर्मदा नदी पर बने बांध के लाभों के जाल में आज भी फंसे हैं तीन राज्य (राजस्थान, गुजरात और मप्र)। सरदार सरोवर से लाभ दिलाने का दावा झूठ साबित हुआ है। बांध पूरा होते ही 18 लाख हेक्टेयरस की सिंचाई का दावा अपने आसपास भी नहीं है। इसके अलावा गुजरात को 91 और राजस्थान को 9 प्रतिशत पानी का हिस्सा आज तक नहीं मिल पाया है। यही नहीं 20,000 किमी लंबाई की छोटी-बड़ नहरों का निर्माण बाकी रहते ही बांध को 138.68 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा दिया गया। सरदार सरोवर निगम के अध्यक्ष का वक्तव्य बताता है कि अभी इस बांध के लिए 50 प्रतिशत नहरों का निर्माण बाकी है। सरदार सरोवर जलाशय से एक बूंद पानी न मप्र को, न ही महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने तो 2015 में अपने हक का आधा पानी (5 टीएमसी) गुजरात को देने का अनुबंध भी किया, जो कि नर्मदा ट्रिब्युनल के फैसले के भी खिलाफ है। जहां तक गुजरात की बात है अब तक कच्छ की नहरें भी पूरी नहीं बन पाई हैं। यही हाल सौराष्ट्र का भी है।

जीवनशाला भी डूबने की कगार पर है। आज न केवल बांध के ऊपरी, बल्कि निचले हिस्से में भी किसान और मछुआरे परेशान हैं। इनका कभी डूबग्रस्तों या विस्थापितों की सूची में नाम ही नहीं है।

पर्यावरणीय सुरक्षा कानून, 1986 के तहत दी गई मंजूरी से यह स्पष्ट था कि कई प्रभावों पर न अध्ययन हुए थे और ना ही नुकसान के बारे में बात। बांधों के कारण नर्मदा नदी का पानी निर्मल न रहने की बात पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को भी मंजूर न थी साथ ही वह यह जातने थे कि बांधों के निर्माण से नदी का अंत निश्चित है। सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की तमाम रिपोर्ट खोखली साबित हुई हैं अब तक। बांध की उपयोगिता और उसके लाभ पर देश की सर्वोच्च अदालत में बहस पूरे छह साल (1994 से 2000) तक चली। अंत में न्यायाधीश भरूचा ने अक्टूबर,

2000 के बहुचर्चित फैसले में स्वतंत्र राय देते हुए कहा है, इस परियोजना का नियोजन ही पूरा नहीं हुआ है, तो जरूरी है कि इसे तब तक आगे न बढ़ने दिया जाए जब तक कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की समिति से पूरी जांच न करवाई जाए। उसी जांच के बाद इस योजना के लाभ-हानि का पता चलेगा। लेकिन अदालत में बहुमत (2 विरुद्ध 1) का फैसला इसे अनदेखा कर चुका है।

नर्मदा घाटी परियोजना में 30 बड़े, 135 मझौले और 300 छोटे बांधों के निर्माण का सिलसिला आज भी नहीं थमा है। बर्गी, इंदिरासागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर के विस्थापितों का दर्द नहीं मिट पाया है, ऊपर से अब नए चुटका परमाणु योजना ने बांधों से पहले से ही विस्थापितों के सिर पर एक बार फिर से विस्थापन की तलवार लटक रही है।

● जितेंद्र तिवारी

भारत की एक बड़ी प्राथमिकता देश की कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। कृषि में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते से भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं

छोड़ी है। लेकिन अभी भी देश के किसानों की जो स्थिति है, वह चिंताजनक ही है। इसकी वजह यह है कि आज भी यहां की खेती मौसम के भरोसे है। यही कारण है कि जब मौसम अच्छा रहता है तो उत्पादन का रिकार्ड बनता है और जब खराब हो जाता है तो किसान की किस्मत मारी जाती है।

अनाज के रिकार्ड उत्पादन में पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड पा चुके मप्र में इस बार पीले सोने यानी सोयाबीन की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। प्रदेश में इस बार अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने रिकार्ड 58.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की थी। इसके कारण उम्मीद जताई जा रही थी कि गेहूं की तरह इस तिलहन फसल का भी बंपर उत्पादन होगा, लेकिन फसल येलो मोजेक वायरस और बारिश की चपेट में आ गई है। अधिकांश जगह सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ गए और पौधे सूख चुके हैं। कई जगह अफलन (फली न लगना) की शिकायतें सामने आ रही हैं। मालवा, निमाड़, महाकौशल सहित अन्य क्षेत्रों में करीब 25 फीसदी तक फसल के प्रभावित होने की आशंका है। नरसिंहपुर में 40, दमोह में 10, सिवनी में पांच फीसदी तक नुकसान की बात सामने आई है।

देश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाले मप्र में इस साल कई जिलों में सोयाबीन फसल को भारी नुकसान हुआ है। पहले कीड़ों ने फसल बर्बाद की तो अब लगातार हो रही बारिश मार रही है। बची फसल किसान समेटना चाहते हैं, लेकिन बारिश के कारण मुश्किल हो रही है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस बार कुल 141 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में खरीफ फसलों की बोवनी की गई है। बारिश में लंबा अंतराल और तापमान अधिक होने के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने नुकसान का आंकलन करने के लिए कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर अभी तक किसानों का फसल बीमा नहीं हो पाया है। बीमा के लिए कंपनी तय करने में समय लगने के कारण अब प्रीमियम जमा करने की समयसीमा 17 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

फसल खराब होने की सूचनाओं को देखते



पीले सोने पर मौसम की मार

कैसे आत्मनिर्भर होगा किसान

देश और प्रदेश की सरकारों किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जुटी हुई हैं। लेकिन हर साल जिस तरह किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है, वैसे में किसान आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा? आज भी देश का किसान खुशहाल नहीं है। सरकार खुद मान रही है कि देश के हर किसान पर औसतन सैंतालीस हजार रुपए का कर्ज है। हर किसान पर औसतन बारह हजार रुपए कर्ज साहूकारों का है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसानों की बहाली व्यवस्था की देन है। करीब अट्ठान फीसदी अन्नदाता कर्जदार हैं। एनएसएसओ के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज्यादा 61,032 रुपए प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर 56,362 रुपए औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30,921 रुपए के साथ राजस्थान है। हमारे नीति नियंता ऐसी स्थिति कब पैदा करेंगे कि किसानों को अपनी उपज का अच्छा और पूरा दाम मिले और कर्ज लेने की नौबत ही न आए। इन आंकड़ों को देखने से साफ होता है कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए ज्यादा काम नहीं हुआ। नतीजा यह है कि कर्ज किसानों के लिए मर्ज बन रहा है और वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कड़वा सच यह है कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए किसानी और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। लेकिन कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों का योगदान लगातार घटता जा रहा है। उदारीकरण के दौर में खेतिहर आबादी की आमदनी अन्य पेशेवर तबकों की तुलना में बहुत ही कम बढ़ी है। यह हकीकत है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। ज्यादातर किसान परिवार जीविका का कोई अन्य विकल्प मौजूद न होने की मजबूरी में ही खेती में लगे हैं।

हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने गत दिनों भोपाल के पास बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव तारा सेवनिया और बगोनिया में निरीक्षण किया। यहां सोयाबीन की 100 फीसदी तक फसल बर्बाद हुई है। सोयाबीन की फलियों में दाने नहीं हैं। पूर्व कृषि संचालक डॉ. जीएस कौशल के अनुसार येलो मोजेक वायरस का असर सोयाबीन में बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। मालवा, निमाड़ और महाकौशल से फसल प्रभावित होने की सूचनाएं आ रही हैं। रतलाम जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ ने बताया कि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल येलो मोजेक, सफेद कीट सहित अन्य बीमारियों से प्रभावित हुई है। सोयाबीन इतना बढ़ गया कि उसमें फलियां ही नहीं लगीं। मालवा-निमाड़ में सोयाबीन की फसलों में दो तरह के कीट सफेद मक्खी (व्हाइट फ्लाय) और तनाछेदक मक्खी (स्टेम फ्लाय) का प्रकोप हो रहा है। ये दोनों कीट सोयाबीन की पत्तियां और तना दोनों को

खोखला कर रहीं हैं। सोयाबीन पकने से पहले ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इस साल मालवा-निमाड़ में 29.80 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी हुई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश रकबा इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, खंडवा, शाजापुर, नीमच जिले में है। कीट के प्रकोप का आंकलन अभी नहीं हुआ है। किसानों का कहना है कि इंदौर में कुछ इलाकों में 10 से 50 फीसदी तक असर हुआ है। वहीं देवास में करीब 50 फीसदी फसलों पर असर है।

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक के मुताबिक हमारे त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, सीहोर, हरदा, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में फसल को सबसे ज्यादा 10 फीसदी तक नुकसान हुआ है। शुरुआत में बोई गई फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा।

● विकास दुबे

देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले मद्र के जंगल महकमे में हमेशा से जंगलीराज चलता रहा है। यहां अधिकारियों की मनमानी पदस्थापना नवाचार का रूप ले चुकी है। आलम यह है कि इस विभाग में दागदार अधिकारियों का दम दिन पर दिन बढ़ता रहता है। विभाग में जो भी बड़ा अधिकारी पदस्थ होता है वह इस विभाग को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकताओं में वन विभाग हाशिए पर है। यही वजह है कि यहां गड़बड़ी करने वाले एक से बढ़कर एक अफसरों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी अपनी स्वार्थ साधना के लिए जूनियर पद मुख्य वन संरक्षक पद पर पोस्टिंग के लिए दबाव बना दिया है। इस आशय का प्रस्ताव भी महकमे ने शासन को भेज दिया है। वन विभाग के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था की सीनियर अधिकारियों को नीचे के पद पर पदस्थ किया गया हो। विभाग में यह नवाचार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रमुख सचिव और वन विभाग के प्रमुख अशोक वर्णवाल ने किया। पिछले दिनों वन विभाग ने 4 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रस्ताव को 4 सर्किलों में पदस्थ करने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।

दिलचस्प पहलू यह है कि जिन चार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को सर्किल में पदस्थ करने का प्रस्ताव भेजा गया है, उनमें से सबसे विवादित अफसर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा है **जिनके खिलाफ अभी भी 2 जांचें** लंबित हैं। एक जांच की रिपोर्ट शासन को सबमिट कर दी गई है परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुख्यालय में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मीणा का प्रस्ताव बैतूल मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार वन विकास निगम में पदस्थ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक यूके सुबुद्धि को भोपाल में पदस्थ करने का प्रस्ताव है। जबकि उनके **खिलाफ लोकायुक्त में मामला विचाराधीन** है। सुबुद्धि जब सीहोर में पदस्थ थे, तब लोकायुक्त में मामला पंजीबद्ध किया था। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार जांच अंतिम चरण में है। प्रतिनियुक्ति पर विभाग के बाहर पदस्थ पीएल धीमान को इंदौर सर्किल में पदस्थ करने की तैयारी है।

अखिल भारतीय वन सेवा कैडर में मुख्यालय में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 25 पद स्वीकृत है। इनमें से 9 पद अभी खाली है। यानी मुख्यालय में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद निरंतर खाली होते जा रहे हैं। जहां अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रिक्त पदों पर अधिकारियों की पदस्थापना नहीं हो पा रही है, वहीं वन विभाग कतिपय आईएफएस अफसरों



जंगल महकमे में जंगली राज

प्रमोशन के लिए नहीं मिल पा रहे हैं योग्य अधिकारी

वन विभाग में पहले से ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद खाली पड़े हैं। इस पद पर प्रमोट करने के लिए निर्धारित योग्यता वाले मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। इस पद पर प्रमोट होने के लिए कम से कम सेवाकाल के 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 25 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने वाले एक भी अफसर वन विभाग में नहीं है जिसे ए पीसीसीएफ के पद पर प्रमोट किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सर्किल में पदस्थापना गैर बाजी प्रतीत होती है।

के दबाव में आकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के दागी अफसरों को सर्किल में पदस्थ करने जा रहा है। जबकि वह पद सीसीएफ स्तर के अधिकारी के लिए है। इस पद पर भी विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल अपने चहेते अफसर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सत्यानंद को पदस्थ कराना चाह रहे हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा के बैतूल सर्किल में पदस्थ किए जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। रेंजर एसडीओ से लेकर डीएफओ तक में हड़कंप मचा हुआ।

दरअसल मीणा की जहां-जहां भी पोस्टिंग रही है, उनकी विवादित कार्यशैली से मातहत अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पीड़ित होते रहे हैं। माधव नेशनल पार्क और सिंह परियोजना उनकी पोस्टिंग के दौरान हुए गड़बड़ी और प्रताड़ना आज भी नहीं भूले हैं। बिना आरोप के रेंजर डिप्टी रेंजर को निर्लंबित करना और राजसात किए गए वाहनों को नियम विरुद्ध छोड़ने के कृत्य की जांच अभी भी चल रही है। इसके पहले बालाघाट सर्किल में पदस्थ रहे, तभी विवादों के चलते ही उन्हें वहां से हटाया गया था।

पहले तो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत के लिए पापड़ बेले। जब पदोन्नति मिल गई तब उन्हें एहसास हुआ कि मुख्यालय में आकर वे एक 'बड़े बाबू' की हैसियत में काम कर रहे हैं। बंगले पर मंडराने वाले 8-10 नौकर-चाकर अब यहां नहीं मिल पा रहे हैं। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अब अपने बंगले पर नौकर रखने के लिए सीसीएफ से मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अन्य शौक-सुविधाएं और ऐशो-आराम के लिए अपने जेब की रकम ढीली करनी पड़ती है। इसीलिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के चार-पांच अधिकारियों ने शासन पर दबाव बनाकर फिर से सर्किल में पदस्थ होने का प्रस्ताव मूव करा दिया है।

● प्रवीण कुमार

10 सालों से सिर्फ घोषणाएं ही



एक साल बाद भी इंदौर मेट्रो का एक पिलर तक नहीं

इंदौर को मेट्रोपोलिटन सिटी बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंदौर मेट्रो की रफतार थमी हुई है। इसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट को लेकर जनरल कंसल्टेंट और दिलीप बिल्डकॉन के बीच विवाद चल रहा है। गत दिनों मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के टेक्निकल डायरेक्टर जितेंद्र दुबे इंदौर पहुंचे तो उनके सामने ही कॉन्ट्रैक्टर कंपनी दिलीप बिल्डकॉन और जनरल कंसल्टेंट के प्रतिनिधि आमने-सामने हो गए। दिलीप बिल्डकॉन ने देरी के लिए कंसल्टेंट को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल, इंदौर के साथ भोपाल मेट्रो में भी विदेशी कंसल्टेंट हैं। इंदौर मेट्रो के शुरुआती दौर में इटली के कंसल्टेंट गेबरियेले थे। उनके बाद जॉन आए। इसके बाद एक और जॉन रहे और अब साइमन शॉरी कंसल्टेंसी दे रहे हैं। वे लॉकडाउन के पहले से साउथ अफ्रीका में हैं और वहीं से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं। नागपुर मेट्रो के एमडी कहते हैं कंसल्टेंट के भरोसे काम छोड़ने से कुछ नहीं होगा। कंसल्टेंट तो चाहते ही हैं कि काम लंबा खिंचे और उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें फॉलो न करते हुए लीड करें। जनरल कंसल्टेंट के 72 कर्मचारियों को तनखाह दी जाना है। विडंबना यह है कि इंदौर की मेट्रो की कंसल्टेंसी साउथ अफ्रीका में बैठा कंसल्टेंट दे रहा है। इसके पहले तीन विदेशी कंसल्टेंट एमपीएमआरसी द्वारा बदले जा चुके हैं।

शामिल किया गया, लेकिन अब इसमें से देवास और उज्जैन को हटाकर 1200 वर्ग किलोमीटर में सीमित किया गया है, यानी 800 वर्ग किलोमीटर कम कर दिया गया। अब नए तय किए गए 1200 वर्ग किलोमीटर के मुताबिक मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि पुनर् प्रस्ताव के मुताबिक ही पूरे एरिया को शामिल करना था, क्योंकि इससे महु-पीथमपुर जोन तो विकसित हो जाएगा, लेकिन धार रोड, उज्जैन रोड के लिए योजनाएं नहीं बन सकेंगी, जबकि मेट्रो का विस्तार भी उज्जैन-देवास तक किया जाना था, तब ही पूरी विंग में विकास बेहतर तरीके से संभव होता, लेकिन अब महु-पीथमपुर नगरीय निकायों और पंचायतों को ही शामिल किया गया है।

74वें संविधान संशोधन के मुताबिक आबादी के मान से इंदौर को वर्षों पहले ही महानगर घोषित किया जाना था, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम 70 वार्ड ही हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश शासन ने विशेष नियमों के तहत ही इंदौर और भोपाल में निगम वार्डों की संख्या बढ़ाई गई और इंदौर निगम की सीमा बढ़ाने के साथ ही वार्डों की संख्या 85 कर दी गई, जिसके चलते कई वार्ड बढ़े और ज्यादा आबादी के भी हो गए, मगर अब वार्डों की संख्या और अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, जिसके चलते अब मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी का गठन अनिवार्य हो गया है। इसमें नगर निगम और अधिक ताकतवर होगा ही, वहीं प्राधिकरण का भी वैसे तो निगम में विलय होना था, मगर अब शिवराज सरकार इस बारे में क्या निर्णय करती है इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा, जब अथॉरिटी के गठन का पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा।

● राकेश ग्रोवर

मेट्रोपोलिटन एरिया यानी महानगर क्षेत्र गठित करने का निर्णय शिवराज कैबिनेट ने गत दिनों लिया, जिसमें इंदौर महानगर क्षेत्र में महु और पीथमपुर को शामिल किया गया, लेकिन उज्जैन, देवास को छोड़ दिया। बीते 10 सालों से इसकी कवायद चल रही है, जिसमें कई मर्तबा परिवर्तन भी किए गए। पूर्व कमलनाथ सरकार ने 2 हजार वर्ग किलोमीटर के लिए इंदौर मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी बनाने की घोषणा की थी, मगर निर्णय पर अमल करने से पहले ही सरकार धराशायी हो गई और अब उपचुनावों में फायदा लेने के लिए फिर इस तरह की घोषणा की गई। दरअसल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए इंदौर और भोपाल को मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित करना जरूरी है।

इंदौर को महानगर बनाने के दावे सालों से होते रहे हैं। अब तो 40 लाख तक जिले की आबादी पहुंच गई है, जिसमें पुलिस कमिश्नरी को भी लागू करने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है। वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट का काम भी धीमी गति से चल रहा है। वैसे भी संविधान के 76वें संशोधन के प्रावधानों के मुताबिक 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों को महानगर के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें आसपास के जिलों, पालिकाओं, पंचायतों को जोड़ा जा सकता है। मास्टर प्लान की संरचना में भी राऊ, महु, नगरीय भाग से लेकर बेटमा, पीथमपुर, देपालपुर, मांगलिया, सांवेर को शामिल किया गया है। इंदौर को महानगर घोषित करने की पहल प्रबुद्ध वर्ग, **मीडिया से लेकर** राजनीतिक दलों द्वारा लगातार की जाती रही है, मगर उसके प्रावधानों को लागू करने से सरकार बचती रही है, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से लेकर उन्हें महानगरों की तर्ज पर दी जाने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं।

अब देखना यह है कि इस बार भी चुनावी घोषणा ना साबित हो जाए, क्योंकि भाजपा की पूर्व सरकार की पूर्व कैबिनेट में मई 2018 में यह प्रस्ताव आया था, लेकिन तब विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे टाल दिया था। अभी भी मेट्रो अथॉरिटी के अधिकार और उसका किस तरह से क्रियान्वयन होगा यह स्पष्ट नहीं है। चूंकि इंदौर-भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसके चलते केंद्र का मेट्रो एक्ट लागू करना जरूरी है। पहले इसमें 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया शामिल किया गया था, जिसे अब घटा दिया है। हालांकि इसमें भी विसंगति रहेगी। और प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था संभवतः पुरानी ही चलेगी।

पूर्व कमलनाथ सरकार ने 2 हजार वर्ग किलोमीटर के लिए इंदौर मेट्रोपोलिटन एरिया का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें इंदौर के साथ-साथ महु, पीथमपुर, देवास, उज्जैन को

संसद में पारित तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। इसके खिलाफ पूरे देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में किसान धरना-प्रदर्शन कर रहे हों। जनवरी से सितंबर 2020 के बीच 9 माह में 20 राज्यों में कम से कम 50 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, जबकि जनवरी, मई, अगस्त व सितंबर में किसान 4 देशव्यापी प्रदर्शन कर चुके हैं। ज्यादातर प्रदर्शन हरियाणा और पंजाब में हुए हैं। वे कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि सरकार मंडियों को खत्म कर देगी। इन मंडियों का संचालन कृषि उपज विपणन कमेटियों के माध्यम से किया जाता है। चर्चा है कि सरकार किसानों से तय कीमतों पर उपज खरीदना बंद कर देगी और उन्हें निजी खरीदारों के भरोसे छोड़ देगी। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म की और न ही मार्केट कमेटी की मंडिया खत्म होंगी। लेकिन न तो किसान इस पर भरोसा कर पा रहा है और न ही विपक्ष। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा रही अकाली दल (ब) कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर कैबिनेट से इस्तीफा दे चुकी हैं। इससे पहले 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर किसान देशव्यापी प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दिन देश के लगभग 250 किसान संगठनों ने एक साथ कॉर्पोरेट भगाओ, देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया था। इस साल की शुरुआत में जनवरी 2020 में किसानों ने प्रदर्शन किया। यह बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें श्रमिक, कर्मचारी, किसान, ग्रामीण मजदूर शामिल थे और उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों के अपने मुद्दे थे, जिनमें कर्जमाफी और बाढ़, सूखा की वजह से बर्बाद फसल की बीमा योजना को सही ढंग से लागू करना शामिल था। इस प्रदर्शन को लगभग 200 किसान व खेतियार मजदूर संगठनों ने एक दिन के ग्रामीण भारत बंद आंदोलन को समर्थन दिया।

सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान कहा कि कृषि अकेला ऐसा क्षेत्र है, जिसने कोरोनावायरस संक्रमण के दौर में वृद्धि की, जबकि दूसरे जैसे मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर असर दिखाई दिया। बावजूद इसके, किसानों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और वे

किसान नाखुश क्यों?



विरोध प्रदर्शनों का भूगोल बदल रहा है

उत्तर पूर्व के किसानों में भी विरोध बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट और एनसीआरबी द्वारा 2018 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़े बताते हैं कि कुछ ऐसे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं, जहां अमूमन किसान पहले प्रदर्शन नहीं करते थे। उदाहरण के लिए, 2016, 2017 और 2018 में आंध्र प्रदेश के किसानों ने प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन 2020 में अब तक कम से कम चार प्रदर्शन हो चुके हैं। इसी तरह, एनसीआरबी के अनुसार, गोवा में 2016 और 2018 के बीच किसानों ने आंदोलन नहीं किए, लेकिन फरवरी 2020 में राज्य के गन्ना किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। उत्तर पूर्व में भी किसानों के बीच संकट बढ़ गया है। असम में, 2016 और 2018 के बीच कृषि आंदोलन में नौ गुना वृद्धि हुई। 2018 में, एनसीआरबी के अनुसार, 2016 में जहां किसानों ने असम में चार प्रदर्शन किए थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गए। मणिपुर और त्रिपुरा में 2016-2018 के किसानों द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं किया गया था, जबकि 2020 में यहां भी आंदोलन हुआ। तीन कृषि विधेयकों के अलावा किसान कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 15 राज्यों में 37 प्रदर्शन दर्ज किए गए। लगता है कि 2020 ये सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन कब समाप्त होता है।

धरना-प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। इस साल के 9 महीने के दौरान 20 राज्यों के किसान 50 बड़े प्रदर्शन कर चुके हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मप्र, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उप्र शामिल हैं। पंजाब के किसान इस मामले में सबसे आगे हैं। यहां के किसान मई माह से लगातार कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां किसान आंदोलन की वापसी हाल ही में हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2018 के बीच यहां कोई प्रदर्शन दर्ज नहीं किया गया।

उत्तर पूर्व में बाढ़ और चक्रवात अम्फन जैसी मौसम की घटनाओं के कारण किसानों को उनकी फसल को नुकसान होने के कारण कर्ज में

दूबना पड़ रहा है। वे कर्जमाफी और मुआवजे के लिए विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा उपज और श्रम की सही कीमत न मिलना एक और बड़ी वजह रहा है। इस साल उत्पादन अधिक रहा है। फिर भी किसानों की आय पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। खरीद के खराब प्रबंधन के कारण भी किसानों में असंतोष है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में किसान फरवरी में सरकार की धान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार ने भी 23 सितंबर को संसद में स्वीकार किया था कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की निजी डेयरियों द्वारा दूध कम खरीदे जाने के कारण कीमतें गिर गई थीं। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का सही मुआवजा न मिलने के कारण भी किसानों ने विरोध किया।

● श्याम सिंह सिकरवार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरल और पश्चिम बंगाल से अलकायदा के लिए काम करने वाले नौ लोगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी अनहोनी टाल दी है। ये लोग राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों को धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन ठोस सूचनाओं के आधार पर एनआईए ने जिस तरह की सतर्कता दिखाई, उससे आतंकी हमलों की साजिश विफल हो गई। यह पहला मौका नहीं है जब अलकायदा के आतंकी पकड़े गए हों। इससे पहले भी अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले पकड़े जाते रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और त्यौहारी मौकों पर ऐसे हमलों के खतरे बढ़ जाते हैं। इन गिरफ्तारियों से एक बात तो यह साफ हो गई कि आतंकियों का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका है और ये गुप्तचुप तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कश्मीर ऐसे ही राज्य हैं जहां आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में आतंकी हमलों की ऐसी साजिशों के पीछे पाकिस्तान है। एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा है, उन्होंने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि वे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा लंबे समय से करता आ रहा है। वह भारत में गरीब और बेरोजगार नौजवानों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें प्रलोभन देता है और फिर प्रशिक्षण देकर उन्हें आतंकी हमलों के लिए तैयार करता है। अलकायदा और आईएस के लिए पाकिस्तान बड़ा ठिकाना बन चुका है, जहां से ये आतंकी संगठन भारत सहित कई देशों में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पिछले साल ईस्टर के मौके पर चर्च और पांच सितारा होटल पर हुए आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों घायल हो गए थे। इस हमले में भी आईएस और अलकायदा के हाथ की पुष्टि हुई थी। पाकिस्तान आईएस और अलकायदा से ऐसे ही हमले भारत पर कराने की कोशिशें कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ लड़ाकू अभियानों में पाकिस्तान इन आतंकी संगठनों के लड़ाकों को इस्तेमाल करता रहा है।

खुफिया जानकारियां बता रही हैं कि अलकायदा ने पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इसका बड़ा कारण बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ है। अगर वाकई ऐसा है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने खुद कहा है कि राज्य अवैध बम बनाने का अड्डा बन चुका है और कानून व्यवस्था की रक्षा करने वाला तंत्र नाकाम



आतंक का जाल

ऐश और फैश से लुभा रहे युवाओं को

खुफिया विभाग के एक अधिकारी कहते हैं कि आतंकी अभी तक मग्न को अपनी शरणस्थली के तौर पर इस्तेमाल करते थे लेकिन अब इनके मसूबे यहां के युवाओं को बरगलाकर देश में बड़े पैमाने पर धमाके कराने के साथ इन्हें अपने संगठनों में शामिल करना भी है। इसके लिए आईएसआईएस में सिमी के प्रभाव वाले क्षेत्रों इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, बुरहानपुर, शाजापुर, जबलपुर के अलावा सतना, रीवा, कटनी, बालाघाट और ग्वालियर-चंबल अंचल में अपनी पैठ बना रहा है। इसके लिए युवाओं को ऐश और फैश से लुभाया जा रहा है। गौरतलब है कि पूर्व के वर्षों में मग्न में आतंकी संगठनों से जुड़े कई नेटवर्क के खुलासे हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन प्रदेश की खुफिया एजेंसियां यहां पैठ जमा रहे आतंकी संगठनों की टोह नहीं ले पाती हैं। सूत्रों के मुताबिक अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए आईएसआईएस के निशाने पर ज्यादातर धार्मिक तालीम हासिल करने वाले युवा हैं। बताते हैं कि आतंकी गतिविधियों में जुड़े लोग अपने संगठन से युवाओं को जोड़ने के लिए दावत खिलाते हैं और इस दौरान वह आतंकी ट्रेनिंग से जुड़ी वीडियो और ऑडियो के साथ पाक में बैठे कई आतंकियों की धार्मिक स्पीच सुनाकर भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मग्न पुलिस के खुफिया विभाग के एक अधिकारी कहते हैं कि प्रदेश में केवल आईएसआईएस ही नहीं बल्कि जैश, अलकायदा, एक्वआईएस के साथ ही सिमी भी सक्रिय है।

साबित हो रहा है। हालांकि यह खेद का विषय है कि आतंकियों के गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक दलों में आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए और आतंकी नेटवर्क के विस्तार के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है।

कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय होता है। ऐसे में पहली जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बनती है कि वे अपने खुफिया तंत्र को मजबूत रखें और ऐसे नेटवर्क के प्रसार को रोकें। अगर सीमाओं से घुसपैठ हो रही है तो निश्चित ही यह हमारी ओर से बड़ी कमी है कि हम घुसपैठियों को रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसी कमियों को केंद्र और राज्य मिलकर दूर कर सकते हैं। आतंक के खिलाफ सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है, न कि ऐसे अवसरों को भुनाने की।

खुफिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, आईएसआईएस ने 2014 के बाद से सीरिया और इराक के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर बांग्लादेश, माली, सोमालिया और मिस्र जैसे देशों में उसकी शाखाएं स्थापित कर लिया है। भारत में अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वह लश्कर-ए-तैयबा, अलकायदा, जैश और सिमी जैसे अन्य आतंकी संगठनों के साथ काम कर रहा है। मग्न सहित देशभर में युवाओं को बरगलाने के लिए इस्लामिक स्टेट इंटरनेट आधारित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे देखते हुए संबद्ध एजेंसियां साइबर स्पेस की सतत निगरानी कर रही हैं। सरकार के पास सूचना है कि इन लोगों को वित्त कैसे मुहैया कराया जा रहा है और अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उन्हें विदेशों से कैसे मदद मिल रही है।

● नवीन रघुवंशी

देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले मप्र में जंगल खतरे में हैं। वनाधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले भू अधिकार पत्र (पट्टे) के लिए अतिक्रमणकारी लगातार पेड़ों की कटाई कर वन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर वनकर्मियों पर हमले, हवाई फायर, पथराव जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पत्र व्यवहार हो रहा है लेकिन कब्जाधारियों की बेदखली इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अभी प्रदेश में उपचुनाव हैं।

इसका फायदा उठाकर प्रदेशभर में वनों की अवैध कटाई जोरों पर है। प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां वनों की अवैध कटाई न हो रही हो।

वर्ष 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रदेश में दो साल में 68.49 प्रतिशत वर्ग किमी में जंगल बढ़ने की

घोषणा की थी लेकिन इस साल तस्वीर बिल्कुल अलग है। प्रदेश में इस साल वन अधिकार पत्रों के लिए कुल 1 लाख 65 हजार 139 दावे किए गए हैं। इनमें से 20 हजार 41 दावों को जायज माना गया है। यानी 88 प्रतिशत दावे खारिज कर दिए गए। सबसे कम करीब 4 प्रतिशत दावे चंबल संभाग में सही पाए गए हैं। बड़े पैमाने पर दावों के अमान्य होने के कारण जंगल की कटाई करके अवैध अतिक्रमण करना, एक से ज्यादा जिलों में जाकर दावा करना, गलत दस्तावेज देने जैसे कारण सामने आए हैं। मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किमी में जंगल है। वन अधिकार पत्र हासिल करने के लिए ग्राम समिति अनुमोदन करती है, फिर तहसील स्तर की समिति और अंत में जिला स्तरीय समिति। ग्राम समितियों ने भी बिना दस्तावेज जांचे और भौतिक सत्यापन किए दावे मान्य किए हैं। उनकी भूमिका भी संदिग्ध है।

7 सितंबर को वनमंत्री विजय शाह के गृह जिले खंडवा के गुड़ी वनक्षेत्र के ताल्याधड़ जंगल में अतिक्रमणकारियों ने वनकर्मियों और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। धमकी दी कि पेड़ की तरह काट डालेंगे। 12 जुलाई को गुना जिले के मूंदोल में वन विभाग के अफसरों के सामने ही बड़ी तादाद में अतिक्रमणकारियों ने जंगल में पेड़ काटे। उन्हें रोका नहीं गया। अफसरों का कहना था- हमारे पास अमला नहीं है।

7 अगस्त को बुरहानपुर जिले के घाघरला में 200 से ज्यादा लोग जंगल कटाई में लगे थे। वन विभाग का अमला ग्रामीणों के साथ रोकने पहुंचा तो हथियार से हमला कर दिया। करीब 100 लोग घायल हुए। 7 सितंबर को नेपानगर आए वनमंत्री विजय शाह वनों की कटाई करने वालों को नहीं बख्शने का दावा कर गए। इसके दूसरे दिन अतिक्रमणकारियों ने पेड़ काटकर और पत्थर डालकर घाघरला के जंगल में खुली चुनौती दी।



कट रहे जंगल, बढ़ रहा जंगलीपन

खेती और पट्टे के लिए कब्जा

ग्रामीणों ने बताया कि सहरिया आदिवासी समुदाय की आड़ में वन माफिया काम करता है। वह उनसे जमीन साफ करवाकर उस पर कब्जा करके खेती करता है। आदिवासी समुदाय गरीब का गरीब बना रहता है। उनका कहना है कि गांव वाले यह समझने लगे हैं कि वनों पर उनकी जिंदगी निर्भर है। अगर वे न रहे तो न तो मवेशियों को चराने के लिए जगह बचेगी न ही बारिश होगी। इसके लिए ग्रामीण भी पहल कर चुके हैं लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से जंगल कटाई नहीं रुक पा रही है। वहीं पट्टों को लेकर भी ग्रामीण कब्जे करने जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं क्षेत्र में जंगलों को बचाने की पहल 15 अगस्त से एकता परिषद और महात्मा गांधी सेवा आश्रम के द्वारा शुरू की है। जिसके तहत गत दिनों ग्राम परौदा के मंदिर में ग्रामीण आदिवासियों को राहत सामग्री देकर 300 पौधे रोपे गए। जिसमें मंदिर परिसर में सामुदायिक जमीन पर 300 फलदार वृक्ष लगाकर सामुदायिक वृक्षारोपण का संदेश दिया। इससे पहले भी राजस्थान सीमा पर स्थित स्टापडेम पर पौधे लगाए गए थे। वहीं पिछले माह रामगढ़ धरावला और बनियानी में चल रही कटाई की सूचना पर इन जंगलों के आसपास गांवों में रहने वाले लोगों ने जब जंगल काटने वाले लोगों पर दबाव बनाया था तब वन अमले ने मौके पर जाकर कटाई रुकवाई थी। जंगलों से इमारती लकड़ी के साथ-साथ अवैध जलाऊ लकड़ी का कारोबार भी दिनोंदिन फल-फूल रहा है। इन लकड़ियों का प्रयोग होटलों, ढाबों, ईट भट्टों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है।

28 अगस्त को खरगोन जिले के वड़िया झिरी फलिया में दो चचेरे भाई पकड़े गए। उन्होंने पट्टे की जमीन पर 29 लाख के गांजे के पौधे लगाए थे। पुलिस पूछताछ में आदिवासियों को लालच देकर खेती की बात सामने आई।

बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 57 किमी दूर घाघरला का जंगल है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां प्रशासन और वन विभाग की नहीं अतिक्रमणकारियों की अपनी हदबंदी है। जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटकर और खूंटे गाड़कर जमीन बांट रखी है, कि यह जमीन तेरी, यह मेरी। एक-एक अतिक्रमणकारी द्वारा कब्जा की गई जमीन 100-200 फीट नहीं, बल्कि पांच से सात एकड़ तक है। दो महीने में वन अमले और ग्रामीणों पर तीन बार हो चुके हमले का खौफ इस कदर है कि मजदूर और किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। दूर कहीं कुल्हाड़ी चलने की आवाज सुनते ही लोग सहम जाते हैं। अकेले खेत जाना तो किसी के भी बस की बात नहीं रही। जंगल से लगे घाघरला, नावरा, गोराडिया, मझगांव और अमुल्ला सहित अन्य गांव हैं। इन गांवों के जंगल में कहीं एक तो कहीं दो कम्पार्टमेंट हैं। एक कम्पार्टमेंट में करीब 1200 हेक्टेयर जमीन है। लेकिन अब यहां कुल्हाड़ी चल रही है। गांव से एक किमी दूर जंगल से लगे खेत में मौजूद रमाकांत पाटिल और रघुनंदन पाटिल ने बताया मजदूर खेत तक आने से डर रहे थे। ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठाकर लाए हैं। पांच से सात लोगों को एक साथ खेत आना पड़ रहा है। यहां काम करते हुए भी आंखें और कान जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर चौकन्ने हो जाते हैं। हम यहां खतरे के बीच रह रहे हैं।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

बुं देलखंड की खनिज संपदा पत्थर और बालू की बयार डेढ़ दशक से परवान चढ़ी है। दोनों खनिज फर्श (धरती) से अर्श (आसमान) पहुंच गए। इसमें राष्ट्रीय कंपनियां भी कूद पड़ीं। कुदरत से मिली मुफ्त संपत्ति को करोड़ों का कारोबार बना दिया। खादी और खाकी से लेकर बाहुबली और माफिया की एंट्री हो गई। इन सबके खजाने खनिज से भर रहे हैं। लेकिन इस अवैध खनन का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खदान में काम करने वाले मजदूरों से लेकर इलाकाई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। किसी को अस्थमा तो किसी को टीबी जैसी गंभीर बीमारी है। वहीं, स्टोन की धूल से सिलिकोसिस बीमारी का प्रकोप काफी है। इसमें शरीर में एलर्जी होती है। हर घर में बीमारी की दस्तक है। लेकिन इनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है।

गौरतलब है कि बुंदेलखंड आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का क्षेत्र है। इस कारण यहां देशभर के बड़े-बड़े कारोबारी खनन का कारोबार करने आते हैं। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी 13 जिलों में हर जगह क्रेशर मशीन चलती दिख जाएगी। पर्यावरण के निर्देशों को दरकिनार कर चल रहे क्रेशर बुंदेलखंड को बीमार कर रहे हैं। महोबा का कबरई क्षेत्र अवैध खनन का गढ़ रहा है। न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे एशिया में कबरई सबसे बड़ी पत्थर मंडी मानी जाती है। इसकी 1979 में दो क्रेशरों से शुरुआत हुई थी। 1982 के बाद क्रेशर लगाने की होड़ लग गई। आज तीन सौ से भी ज्यादा क्रेशर यहां चल रहे हैं। रात-दिन चल रहे क्रेशर आसपास के पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं। कबरई के मोचीपुरा और विशाल नगर के पास पहाड़ की चोटी से शुरू हुई खुदाई अब पहाड़ के कई सौ फीट नीचे गहराई तक पहुंच गई है। पानी निकल आया है। इसे पाताल तोड़ खुदाई कहते हैं।

महोबा जिले में खनन और स्टोन क्रेशर ने बुंदलेखंड को बीमारियों ने जकड़ लिया। खदान में काम करने वाले मजदूरों से लेकर इलाकाई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। किसी को अस्थमा तो किसी को टीबी जैसी गंभीर बीमारी है। वहीं, स्टोन की धूल से सिलिकोसिस बीमारी का प्रकोप काफी है। इसमें शरीर में एलर्जी होती है। हर घर में बीमारी की दस्तक है। इसके बावजूद मजबूरी में उसी धूल में ग्रामीणों को रहना पड़ रहा है। कबरई से सटा हुआ एक डहरा गांव है। यहां पर पत्थर मंडी है। गांव से चंद कदम दूर हर दिन पहाड़ों में ब्लास्ट होते हैं। दिन रात डंपर पत्थरों को ढोते हैं और पास में लगे क्रेशरों में पत्थरों की कटाई होती है। ये गांव खनन और क्रेशर से बेइंतहा प्रभावित है। गांव निवासी भरत सिंह परिहार बताते हैं कि यहां हर



बीमार होता बुंदेलखंड

157 स्टोन क्रेशर कारखाने सील

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुंदेलखंड के चार जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर में संचालित स्टोन क्रेशर कारखानों में से 157 को सील कर दिया है और उन पर 13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बांदा स्थित कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी घनश्याम दत्त ने बताया कि क्रेशर नियमों का उल्लंघन करने पर दो माह के अंदर चित्रकूट धाम मंडल बांदा के चार जिलों बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर में संचालित 393 में से 157 स्टोन क्रेशर कारखाने सील कर उन पर 13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 71 क्रेशर मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दत्त ने कहा कि बांदा जिले में संचालित कुल 30 क्रेशर कारखानों में से 13 को सील कर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चित्रकूट में 75 में से 58 क्रेशर सीलकर पांच करोड़ रुपए, महोबा में 283 में से 81 क्रेशर सीलकर 5 करोड़ रुपए और हमीरपुर जिले की सभी पांच क्रेशर कारखाने सीलकर उन पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घनश्याम दत्त ने बताया कि कोई भी क्रेशर कारखाना बस्ती से करीब एक किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर दूर होना चाहिए। साथ ही कारखाने में प्रतिदिन फव्वारे से पानी का छिड़काव किया जाना जरूरी है। क्रेशर कारखाने में पौधरोपण करना प्रमुख शर्त है, जबकि क्रेशर मालिकों ने इन नियमों का उल्लंघन किया है।

घर में तीन चार लोग बीमार मिलेंगे। किसी को टीबी तो किसी को अस्थमा व सिलिकोसिस है। भरत ने बताया कि पूरे गांव की बात करें तो तकरीबन 70 फीसदी लोग बीमार हैं। जिसकी

वजह ये खनन और क्रेशर से निकलने वाली डस्ट है।

बुंदलेखंड पर खनन और क्रेशर के प्रभाव को लेकर कुछ खास शोध नहीं हुए हैं। मगर सन् 2011 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एसवीएस राणा, अमित पाल और शेख असदुल्ला का एक अध्ययन जर्नल ऑफ ईकोफिजियोलॉजी एंड ऑक्युपेशनल हेल्थ में प्रकाशित हुआ, जिससे यहां पर स्टोन डस्ट से होने वाली बीमारियों के बारे में अहम जानकारी मिलती है। अध्ययन के मुताबिक, खदानों और स्टोन क्रेशर में काम करने वाले 45.11 फीसदी मजदूर सांस की बीमारी से ग्रसित हैं। 43.33 फीसदी लोग त्वचा रोग, 21.53 फीसदी लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। 14.66 फीसदी लोग दमा और 17.8 फीसदी लोग आंखों की बीमारी से ग्रसित हैं। इसी तरह इलाकाई लोगों पर भी प्रभाव पड़ा है। वो भी इन्हीं बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये अध्ययन तीन सौ लोगों पर किया गया था। जो क्रेशर चलने वाले इलाकों व वहां काम करने वाले थे।

महात्मा गांधी ग्रामोदय वि्वि के महेंद्र कुमार उपाध्याय और सूर्यकांत चतुर्वेदी का एक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च में 2016 में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन में बुंदेलखंड के बांदा, भरतकूप और महोबा के कबरई क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसके मुताबिक स्टोन क्रेशर से निकलने वाली डस्ट को नियंत्रित करने का कोई भी उपाय नहीं किया गया। ये डस्ट सीधे हवा में उड़ती है। जिससे दमा, अस्थमा, टीबी और त्वचा रोग हो रहा है। रिसर्च के मुताबिक कबरई के 40 फीसदी लोगों की रेडियोलॉजी रिपोर्ट असामान्य आई थी। इससे यहां के लोगों के स्वास्थ्य कितना स्वस्थ है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

● सिद्धार्थ पांडे

बाबरी से सब बरी



अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-धार्मिक विवाद था, जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर था। इन दोनों मुद्दों का 2020 में पटाक्षेप हो गया है। इसके साथ ही राजनीति का एक ऐसा मंच समाप्त हो गया, जिसको लेकर बार-बार राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही थीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद धर्म की राजनीति पर विराम लग जाएगा। अब काशी और मथुरा के विवादों को हवा दी जा रही है।

● राजेंद्र आगाल

आ ज से करीब 35 साल पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद राजनीतिक युद्ध का ऐसा मैदान बना कि इस मुद्दे पर शह और मात का खेल होता रहा। लेकिन 2020 स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है, क्योंकि इस साल राम

जन्मभूमि और बाबरी विध्वंस मामले पर पटाक्षेप हो गया है। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की अदालत ने मामले में दोषी बनाए गए सभी 32 लोगों को बाइजत बरी कर दिया है। सीबीआई इस मामले पर मुंह के बल जा गिरी। पूरा मामला पत्रकारों और अखबार की कटिंग पर आधारित था। संघ परिवार, भाजपा व अन्य हिंदू

संगठनों से जुड़े नेताओं को बाबरी मस्जिद गिराने का साजिशकर्ता बताया गया, लेकिन उनकी साजिश को पूरा किसने किया इसका कहीं अता-पता नहीं। दरअसल, बाबरी का विध्वंस उन्मादकारी तत्वों के हाथों हुआ था। देर से ही सही अब इस मामले का पटाक्षेप हो गया है। यह देश के लिए शांति की ओर एक कदम है।

वास्तव में 6 दिसंबर 1992 को लगभग 9:30 बजे कारसेवकों का एक जत्था तेजी से विवादित ढांचे की ओर बढ़ा और फावड़े, गैंती, बड़े-बड़े हथौड़े से विवादित ढांचे को गिराना शुरू किया। इस प्रयास में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग मारे गए और बड़ी संख्या में कारसेवक घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुछ पत्रकारों सहित कई लोगों की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। सीबीआई के सामने ही पूरा रिकॉर्ड था कि उस ढांचे को गिराने वाले कौन लोग थे और इसके लिए क्या-क्या तैयारियां की गई थीं। लेकिन इस पक्ष की ओर सीबीआई ने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में मंदिर आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं को यह पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई घटना होने जा रही है। संघ परिवार के एक बड़े नेता ने कहा कि उन्हें जरा भी जानकारी होती कि इस तरह की तैयारी कारसेवकों के एक वर्ग द्वारा की गई है तो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को अयोध्या बुलाते ही नहीं। यह उनकी सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार जो इस मामले पर धिरी हुई थी वह लक्ष्य बनाकर तीर चला रही थी। वह उन भाजपा नेताओं को किनारे लगा कर एक वर्ग का गुस्सा शांत कर देना चाहती थी जो मंदिर आंदोलन के अगुआ थे। इसीलिए 120-बी यानी आपराधिक षड्यंत्र के सहारे ही सारा मामला आगे बढ़ा और नेताओं पर निशाना साधा गया। यह अलग बात है कि सारा केस अखबारों की कटिंग व वीडियो पर आधारित था।

विध्वंस सुनियोजित नहीं था

फैसला सुनाते हुए सीबीआई अदालत के विशेष जज एसके यादव ने कहा कि विध्वंस सुनियोजित नहीं था। उल्लेखनीय है कि 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया था और देश में व्यापक अशांति फैल गई थी। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ ठोस व पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हुए। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत ऑडियो-वीडियो टेप की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई। यह भी कि विवादित ढांचे को गिराने वाले असामाजिक तत्व थे। साथ ही आरोपी नेताओं के भाषणों की ऑडियो क्लिप स्पष्ट नहीं थी।

अदालत के फैसले के वक्त जहां शेष सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे, वहीं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े थे। जाहिर तौर पर भाजपा, संघ व विहिप के नेताओं ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। वहीं मुस्लिम संगठनों ने न्याय की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ऊंची अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही। उनका दावा है कि घटनाक्रम के साक्ष्यों के आधार पर जब इन नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने और



कोर्ट में नहीं टिक पाए सीबीआई के सबूत

अयोध्या विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में फैसला 2300 पन्नों का था। सीबीआई ने कोर्ट के सामने कई सबूत पेश किए, लेकिन वह सभी नाकाफी साबित हुए। सभी सबूत पर्याप्त नहीं थे। वहीं सीबीआई कोर्ट ने माना कि यह घटना अचानक हुई थी। यह कोई पूर्व सुनियोजित साजिश नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि केवल फोटो के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी को जिस तरह से साबित किया गया वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। कोर्ट में टैपड सबूत पेश किए गए थे। ढांचा गिराने की घटना अचानक हुई थी, इसमें कोई साजिश नहीं थी। ढांचा गिराने में किसी भी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। अज्ञात लोगों ने विवादित ढांचा गिराया था। जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उनका इस घटना से लेना-देना नहीं। सीबीआई 32 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रही है। गवाहों के बयान कहते हैं कि कारसेवा के लिए जुटी भीड़ की नीयत बाबरी ढांचा गिराने की नहीं थी। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि अंदर मूर्तियां थीं। विवादित जगह पर रामलला की मूर्ति मौजूद थी, इसलिए कारसेवक उस ढांचे को गिराते तो मूर्ति को भी नुकसान पहुंचता। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। अखबारों में लिखी खबरों को सबूत नहीं माना जा सकता। सबूत के रूप में कोर्ट में सिर्फ फोटो और वीडियो पेश किए गए। जो की टैपड थे। उनके बीच-बीच में खबरें थीं, इसलिए इन्हें भरोसा करने लायक सबूत नहीं मान सकते। चार्टशीट में तस्वीरें पेश की गईं, लेकिन इनमें से ज्यादातर के निगेटिव कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। इसलिए फोटो भी प्रामाणिक सबूत नहीं हैं।

सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप थे तो उन्हें बरी कैसे किया गया। विभिन्न राजनीतिक दलों की तल्लख प्रतिक्रियाएं इस फैसले को लेकर आई हैं। उनकी दलील है कि 28 साल बाद 2300 पन्नों के फैसले में न्याय कहां है? उल्लेखनीय है कि इस विध्वंस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो गई और बचे 32 आरोपी बरी कर दिए गए। पिछली 16 सितंबर को सीबीआई अदालत ने सुनवाई पूरी करके फैसला 30 सितंबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया था।

बहरहाल, इस फैसले को लेकर देश की शीर्ष जांच एजेंसी का सवालियों के घेरे में आना स्वाभाविक ही है कि वह 28 साल में ठोस प्रमाण क्यों नहीं जुटा पाई। हालांकि, एजेंसी अब कह रही है कि ऊंची अदालत में अपील हेतु वह न्यायिक सलाह लेगी। इसके अतिरिक्त प्रश्न यह भी है कि यदि बरी किए लोग दोषी नहीं थे तो अराजक तत्व कौन थे, उन्हें किसने प्रेरित किया, जिसके चलते उन्होंने सुनियोजित तरीके से विवादित ढांचे को नेस्तनाबूत कर दिया। यह भी कि यदि यह साजिश नहीं थी तो पूरे देश से इतने लोग कैसे जुटे थे? उन्हें उद्देलित करने वाले भाषण किसके थे? इस फैसले के खिलाफ बाबरी एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील करने की घोषणा कर दी है। बहरहाल, इस प्रकरण में खूब राजनीति हुई। मगर राजनीति से इतर जो स्वाभाविक प्रश्न हैं कि यदि उस दिन अयोध्या में कोई अपराध हुआ था तो दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए था। वहीं इस मामले में शिवसेना की दलील है कि राम जन्मभूमि मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद विवादित ढांचे के ध्वंस विवाद की प्रासंगिकता खत्म हो गई। वहीं कुछ कानून के जानकार कहते हैं कि जब 6 दिसंबर 1992 को कोई कानून तोड़ा गया था और यदि किसी को दंडित नहीं किया जाता



इन 49 लोगों पर था बाबरी विध्वंस का आरोप

28 साल पहले हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 32 लोग जीवित हैं। जिन्हें अदालत ने इस मामले से बरी कर दिया है। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपालदास, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, रामविलास वेदांती, धरम दास, सतीश प्रधान, चंपत राय, पवन कुमार पांडेय, ब्रजभूषण सिंह, जय भगवान गोयल, महाराज स्वामी साक्षी, रामचंद्र खत्री, अमननाथ गोयल, संतोष दुबे, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, विनय कुमार राय, लल्लू सिंह, ओमप्रकाश पांडेय, कमलेश त्रिपाठी उर्फ सती दुबे, गांधी यादव, धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर, रामजी गुप्ता, विजय बहादुर सिंह, नवीन भाई शुक्ला, आचार्य धर्मेन्द्र देव, सुधीर कक्कड़, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव आदि शामिल हैं। वहीं 18 लोग वे हैं, जिनका ट्रायल के दौरान निधन हो गया। इनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, बालासाहेब ठाकरे, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावे, महंत अवैद्यनाथ, विनोद कुमार वत्स, राम नारायण दास, लक्ष्मी नारायण दास महात्यागी, हरगोविंद सिंह, रमेश प्रताप सिंह, देवेन्द्र बहादुर राय, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, विजयराजे सिंधिया, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश कुमार नागर आदि शामिल हैं।

तो यह फैसला कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। यह भी कि सीबीआई ने अपना काम ठीक से नहीं किया। यही वजह है कि तमाम साक्ष्यों व 350 प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के बावजूद मुकदमा तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचा। तर्क दिया जा रहा है कि जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष अलग और स्वायत्त होने चाहिए। सीबीआई के 'पिंजरे का तोता' होने के शीर्ष अदालत के आरोप फिर हकीकत बनते नजर आते हैं। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि घटना के बाद शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने इसे कानून का भयावह उल्लंघन बताया था तो उल्लंघन के दोषियों को दंडित क्यों नहीं किया गया। वहीं राम जन्मभूमि मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने फैसले का स्वागत किया है।

अयोध्या के दोनों विवाद निपट गए

अयोध्या में वर्षों से खड़े दो विवाद एक के बाद एक निपट गए हैं। पहले शांतिपूर्ण ढंग से राममंदिर पर फैसला आया और सौहार्द्रपूर्ण

माहौल में भूमिपूजन हो गया। 30 सितंबर को यह भी अदालत से ही स्पष्ट हो गया कि विवादित ढांचे को गिराने में कोई साजिश नहीं थी। लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन जिस तरह विवादित ढांचे के नीचे रामजन्मभूमि मंदिर होने के पुख्ता सबूत के आधार पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ लोगों का रास नहीं आया था, उसी तरह सबूतों के अभाव में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का रिहा होना भी कईयों को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग इसे काला दिवस बता रहे हैं, कुछ सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल अपनी मर्जी के फैसले चाहिए होते हैं। फैसला अलग हुआ नहीं कि सवाल खड़े।

कांग्रेस, वाम जैसे कुछ दलों की ओर से तत्काल विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस अवलोकन के खिलाफ है जिसमें कोर्ट ने ध्वंस को गैरकानूनी कहा था। तो विशेष अदालत

6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढहाया

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद लगभग कई दशकों पुराना है। इसकी शुरुआत सन् 1528 में हुई थी। 6 दिसंबर, 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। जल्दबाजी में एक अस्थायी राम मंदिर बनाया गया।

16 दिसंबर, 1992: मस्जिद की तोड़-फोड़ की जिम्मेदार स्थितियों की जांच के लिए एमएस लिब्रहान आयोग का गठन हुआ।

अप्रैल 2002: अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की।

मार्च-अगस्त 2003: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं।

सितंबर 2003: एक अदालत ने फैसला दिया कि मस्जिद के विध्वंस को उकसाने वाले सात हिंदू नेताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाए।

जुलाई 2005: संदिग्ध इस्लामी आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक जीप का इस्तेमाल करते हुए विवादित स्थल पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया।

जुलाई 2009: लिब्रहान आयोग ने गठन के 17 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

30 सितंबर 2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

21 मार्च 2017: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पेशकश की। चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष राजी हो तो वो कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार हैं।

19 अप्रैल 2017: सुप्रीम कोर्ट ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की रोज सुनवाई का आदेश देते हुए दो साल में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।

15 जुलाई 2019: अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले की सुनवाई करने वाले स्पेशल जज ने सुप्रीम कोर्ट से छह माह का और समय मांगा है।

24 जुलाई 2020: सीबीआई ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया और कहा कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वह राजनीतिक कारणों से थे।

30 सितंबर 2020: सीबीआई की अदालत ने सभी आरोपियों को बरी किया।

तस्वीरों में 6 दिसंबर 1992



ने कब कहा कि जो हुआ वह कानूनी था। कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि अराजक तत्व ध्वंस के लिए जिम्मेदार थे।

साजिश के तहत फंसाया गया

सीबीआई को एक बार फिर से सरकार का 'तोता' कहा जाने लगा है। लेकिन सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई और सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद राजनीतिक स्तर पर एक और साजिश शुरू हुई थी, जिसका पर्दाफाश अदालत के फैसले में हुआ है। यह साजिश थी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेताओं को इस मामले में फंसाने की। आडवाणी समेत कई नेताओं को तो बहुत पहले ही कोर्ट ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को नहीं बदला तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी हो गई। वर्ष 2010 में सीबीआई को एक और एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर किया गया, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल समेत भाजपा व विहिप के 48 वरिष्ठ नेताओं को आरोपी बनाया गया।

एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इतने हाईप्रोफाइल केस का फैसला आने में इतना अधिक समय क्यों लग गया। तो इसका जवाब भी भाजपा और वरिष्ठ नेताओं को फंसाने के लिए की गई साजिश में ही छुपा है। सीबीआई से दो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस क्रम में यह ध्यान में रखा गया कि एक विवादित ढांचे को गिराने की साजिश के दोनों के केस का अदालती कार्रवाई का दायरा भी अलग-अलग हो गया है। एक लखनऊ में तो दूसरा रायबरेली में। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दशकों तक एक पूरी कानूनी जंग इस अदालती कार्रवाई के दायरे को तय करने को लेकर होती रही। कानूनी पेंच इस बात पर भी फंसता रहा कि दो एफआईआर की चार्जशीट भी दो होगी या एक। यदि दो चार्जशीट होती है तो उसकी सुनवाई रायबरेली और लखनऊ की अलग-अलग अदालत में होगी या फिर एक ही अदालत में। यदि एक ही अदालत में सुनवाई होगी तो फिर रायबरेली या लखनऊ की अदालत में किसमें सुनवाई की जाएगी। आखिरकार 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि दोनों केस एक साथ रायबरेली की अदालत में ही सुने जाएंगे। अदालत के फैसले से विवादित ढांचे के गिरने के बाद भाजपा व विहिप के वरिष्ठ नेताओं को फंसाने की गई राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश हो गया।

सुनवाई में देर कहाँ हुई?

इस मामले में 4 साल तक कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से कागज तक नहीं हिला। 12 फरवरी 2001 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा, कल्याण सिंह और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा हटाने का आदेश दिया। तीन महीने के भीतर 4 मई 2001 को लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर 197/92 और 198/92 को अलग-अलग सुनवाई के लिए लिया। यह भी कहा कि 21 आरोपियों के खिलाफ रायबरेली की कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, 27 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई लखनऊ में होगी। सीबीआई ने तब इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक साजिश का आरोप हटाने के आदेश का रिव्यू करने के लिए याचिका लगाई, लेकिन यह याचिका खारिज हो गई। 16 जून को सीबीआई ने उग्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि ट्रायल दोबारा शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। जुलाई 2003 में सीबीआई ने आडवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप वापस ले लिया और रायबरेली कोर्ट में नए सिरे से चार्जशीट दाखिल की। लेकिन, जुलाई 2005 में हाईकोर्ट ने आडवाणी के खिलाफ 'नफरत फैलाने' का आरोप तय किया। 2010 तक दोनों केस अलग-अलग अदालतों में चलते रहे। 2011 में सीबीआई आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां यह तय हुआ कि रायबरेली की सुनवाई भी लखनऊ ट्रांसफर की जाए। अगले 7 साल तक अदालतों में आरोप तय होने को लेकर रिव्यू याचिकाएं दाखिल होती रहीं। 19 अप्रैल 2017 को आडवाणी और अन्य आरोपियों पर फिर से आपराधिक साजिश का आरोप तय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को त्रुटिपूर्ण करार देते हुए सीबीआई की भी इस बात को लेकर खिंचाई की कि उस आदेश को पहले चुनौती क्यों नहीं दी गई? तकनीकी तौर पर 2010 में ही ट्रायल शुरू हो सका। आरोप तय होने के स्टेज पर सुनवाई अटकी रही क्योंकि अधिकांश आरोपी हाईकोर्ट में थे।

बाबरी ढांचे के विध्वंस से जुड़े मामले में 30-40 हजार गवाह थे। ट्रायल में मौखिक गवाही महत्वपूर्ण रही। मौखिक सबूतों में गवाहों के पुलिस को दिए बयानों को लिया गया। सीबीआई ने जांच के दौरान 1,026 गवाहों की सूची बनाई। इसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और पत्रकार थे। 8 भाजपा और विहिप नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप साबित करने के लिए

मौखिक आरोप ही हैं। इस वजह से सीबीआई ने अतिरिक्त प्रयास किए ताकि ज्यादा से ज्यादा गवाहों को जुटाया जा सके। 2010 से सीबीआई की कई टीमों ने देशभर का दौरा किया और लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन दिए। कुछ को तो इंग्लैंड और म्यांमार में भी ट्रेस किया है। हजारों में से सिर्फ 351 गवाह ही कोर्ट में बयान देने पहुंच सके। मौखिक सबूतों में इन नेताओं की ओर से दिए गए भाषण शामिल हैं। खासकर 1990 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा शुरू की, उस दौरान दिए गए बयानों को सबूत माना गया। यह बताता है कि ढांचे को गिराने का विचार 1990 में ही आया, जो बताता है कि यह साजिश थी।

आखिर किसने ढहाया था ढांचा ?

फैसला सुनाते हुए विशेष सीबीआई जज एसके यादव ने कहा- 'हमारी कानून व्यवस्था का इससे अधिक मखौल नहीं उड़ाया जा सकता है। यह तो सभी को पता था कि किसी बड़े नेता को सजा नहीं होगी लेकिन सभी को बरी कर देना सिर्फ और सिर्फ यह दिखाने की कोशिश है कि हम जो चाहेंगे वह करेंगे। यह एक नए आंदोलन को बढ़ावा देगा, जिसकी शुरुआत मथुरा से हो चुकी है।' गौरतलब है कि बीते 25 सितंबर को उप्र के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई है। बाबरी विध्वंस मामले में कई सालों से सुनवाई चल रही थी, जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पूरे होने की दिशा मिली थी।

प्रधान कहते हैं, 'अप्रैल 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई करने और रायबरेली व लखनऊ की अदालतों में चल रहे मामलों को एक कर सुनवाई करने का आदेश दिया था तब ही अदालत ने साफतौर पर यह कहा था कि यह साजिश है और सभी के खिलाफ साजिश का मामला चलाया जाए।' बाबरी मस्जिद विध्वंस को साजिश न मानने के विशेष सीबीआई जज के फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रधान कहते हैं कि यह तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ही विरोधाभासी है। उन्होंने कहा, 'इससे पहले हाईकोर्ट ने सभी को बरी करते हुए कहा था कि साजिश नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा साजिश का मामला शुरू कराया था। उस साजिश को विशेष अदालत ने नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का फैसला दिया था, तब उसने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि विध्वंस एक कैलकुलेटेड एक्ट था। कैलकुलेटेड एक्ट का मतलब होता है साजिश। यह पूरी तरह से उसके विपरीत है।'



काशी और मथुरा पर नजर

अयोध्या में 'सफल मनोरथ' होने के बाद से ही शुभचिंतकों ने 'काशी विवाद' को नए सिरे से उद्गारना आरंभ कर रखा है और अब वे मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान परिसर के पास स्थित मस्जिद को वहां से हटाने की मांग कर कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच पांच दशक पुराने समझौते को निरस्त कर मस्जिद की पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए। दरअसल, काशी में विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है, जिसे कुछ लोग अकबर के शासनकाल में तो कुछ अन्य औरंगजेब के राज में निर्मित बताते हैं। इसी तरह मथुरा का शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक बना हुआ है। हिंदू 'सम्प्रदायवादी' मानते हैं कि अयोध्या में रामजन्मभूमि की ही तरह बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शंकर व कृष्ण में उनकी आस्था के इन दो केंद्रों को मुक्त कराना भी आवश्यक है। और हां, वे तभी उन्हें मुक्त मानेंगे, जब उनके निकट से ज्ञानवापी मस्जिद और ईदगाह हट जाएं। यों, उनके द्वारा यह भी प्रचारित किया जाता है कि दिल्ली व अहमदाबाद की जामा मस्जिद भी हिंदुओं के पूजास्थलों को तोड़कर ही बनाई गई है। वे जानते हैं कि इनकी आड़ में उनकी स्वार्थ या कि सत्ता साधना तभी तक सफल हो सकती है, जब तक देशवासी इतिहास के इस सच से वंचित रहें कि अतीत में धर्मस्थलों के, वे किसी भी धर्म के क्यों न हों, तोड़े जाने का प्रमुख आधार साम्प्रदायिक या धार्मिक वैमनस्य न होकर राजे-महाराजाओं, सम्राटों व बादशाहों वगैरह के बीच अपनी सत्ता का सिक्का जमाने और संपत्ति हड़पने की प्रतिद्वंद्विता हुआ करती थी। अन्यथा कई बार वे धर्मस्थलों को जागीरें और भूमि वगैरह दान भी दिया करते थे।

सबूत पर्याप्त नहीं

विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में सबूत के तौर पर जो वीडियो फुटेज की कैसेट पेश कीं, उनके दृश्य स्पष्ट नहीं थे और न ही उन कैसेट्स को सील किया गया। घटना की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किए गए। अदालत के इन तर्कों पर प्रधान कहते हैं, 'यह बड़ा साफ है कि जिस तरह का निर्णय दिया गया है वह सही नहीं है। यह मान लेना कि सारे सबूत बकवास हैं, सीबीआई का मखौल उड़ाना है। अब यही दिखा रहे हैं कि देखिए सीबीआई ने तो केस बनाया लेकिन जो है, सब बकवास है।'

अदालतों में पेश वीडियो फुटेज के मामले पर उन्होंने आगे कहा कि इस देश में जब-जब नेता किसी मामले में शामिल रहे हैं तब-तब वीडियो रिकॉर्डिंग को नकारा गया है, चाहे वह वीडियो अभिषेक मनु सिंघवी का हो, मुलायम सिंह यादव का, वरुण गांधी का, या चाहे अमर सिंह का। ये सब बरी हो गए। जो भी गलत काम या गलत बात करते हुए पकड़े गए उन सभी का फैसला यही आया कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई या उसे बनाया गया था। उन्होंने कहा, 'यह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि यह मानकर चला जाता है कि नेता कोई गलत काम नहीं करता है। आम आदमी तो जेल में बंद भी हो जाएगा और सजा भी हो जाएगी। इस मामले में तो और भी बड़े-बड़े नेता शामिल हैं। यह दिखाता है कि किस तरह से हमारी न्यायिक प्रणाली को तोड़ा-मरोड़ा जाता है। कानून के शासन की जगह अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मसला हो गया है।' फैसले में यह भी कहा गया कि सीबीआई पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी। आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, बल्कि आरोपियों द्वारा उन्मादी भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया था।

वामपंथियों की वापसी

समूचा पश्चिम बंगाल कोरोनावायरस संक्रमण की बेकाबू लहर और रह-रहकर लॉकडाउन के थपेड़ों से झुलस रहा है। बावजूद इसके, यहां कई लोगों, खासकर सियासी सरपरस्तों की नजरें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर जमी हुई हैं। 40 बरस के बढ़ई कादेर मुल्ला कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के रोनॉल्ड रॉस बिल्डिंग के गलियारे के आखिरी कोने में डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। सुंदरबन इलाके के रहने वाले मुल्ला ने कुछ साल पहले माकपा से नाता तोड़ तृणमूल कांग्रेस की ओर रुख कर लिया था, जैसा अमूमन चलन रहा है। उनके हिसाब से 2021 में विधानसभा चुनावों के नतीजे इस सवाल से तय होंगे कि, क्या 2019 में भाजपा की ओर चला गया वामपंथी पार्टियों के वोटों का 20 फीसदी या कम से कम उसका आधा लौट आता है या नहीं?

भले यह इकलौती वजह न हो, लेकिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण वजह है कि तृणमूल कांग्रेस यह आश्वस्त करे कि माकपा हर जगह अपने दफ्तर खोले और रैलियां करे। खासकर वहां, जहां 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद माकपा के दफ्तर तोड़ दिए गए या कब्जा लिए गए। मुल्ला कहते हैं, हमारे इलाके में माकपा ने अपने दफ्तर खोल लिए हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। तृणमूल का गणित यह है कि वामपंथियों की चुनावी मैदान में दमदार वापसी से आक्रामक भाजपा से लड़ाई उसके हक में आ जाएगी। इस गणित के अनुसार, अगर तृणमूल विरोधी वोट वाम मोर्चे और भाजपा में बंट जाता है तो उसकी जीत तय है, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ और भाजपा राज्य की कुल 42 संसदीय सीटों में से 18 जीत गई थी। 2019 में 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 121 पर भाजपा की बढ़त ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी को डरा दिया है।

पिछले 6 वर्षों में बंगाल के लेफ्ट मतदाताओं के दक्षिणपंथ की ओर झुक जाने का साफ सबूत 2019 में मिला, जब वाम मोर्चे की वोट हिस्सेदारी 25.69 फीसदी (2016 के विधानसभा चुनावों में) और 29.99 फीसदी (2014 के लोकसभा चुनाव में) से घटकर 7.53 फीसदी रह गई। भाजपा का वोट शेयर 17 से 40 फीसदी पर पहुंच गया। सो, तृणमूल मशक्कत में जुट गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, अगर माकपा के कम से कम 2-4 फीसदी वोट भी उसकी ओर लौट जाते हैं, तो हमारी राह सुरक्षित हो जाती है। जमीन पर ऐसी हलचल दिख भी रही है। माकपा अमूमन कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम जैसे अपने पुराने गढ़ों में बड़ी रैलियां कर रही है, जहां भूमि अधिग्रहण विवाद के खिलाफ हुए बहुचर्चित आंदोलन से ही वाममोर्चे की गर्दिश शुरू हुई थी। गत दिनों विधानसभा में वाम विधायक दल के नेता



पूँजीवाद से मोहभंग

माकपा के दक्षिण 24 परगना जिला कार्यालय में लाल रंग से पुते कोने वाले कमरे में बैठे सुजोन चक्रवर्ती पार्टी के लिए हालात बदलने में स्थानीय मुद्दों के साथ वैश्विक घटनाक्रम को जोड़कर देखते हैं। वे कहते हैं, लोगों का पूँजीवाद से मोहभंग हो रहा है। आखिर उन्हें एकाधिकार दबदबे वाले पूँजीवाद से क्या मिल रहा है। उनका यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार सृजन के अपने वादे को निभाने में नाकाम रही है। वैश्विक कीमतें कम हो रही हैं मगर यहां तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। श्रमिकों के अधिकार तेजी से गायब हो रहे हैं, जबकि बंगाल में तो पूरी अराजकता है। चक्रवर्ती कहते हैं, ये तमाम हालात वामपंथ के लिए जगह बना रहे हैं। वे इस बात को सिर से नकार देते हैं कि तृणमूल वामपंथी दलों को सरकार विरोधी वोट बांटने के लिए बढ़ावा दे रही है। वे कहते हैं, तृणमूल की जमीन खिसक रही है, उसके लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसके पास हमें रोकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन असली सवाल वही है, जो कोलकाता में मुल्ला ने उठाया कि क्या वामपंथ से मुंह मोड़ चुका 20 फीसदी वोट उसकी ओर लौटगा? चक्रवर्ती लगभग बुदबुदाते हुए कहते हैं, यही लाख टके का सवाल है। लंबी चुप्पी के बाद थोड़ा संभलकर वे कहते हैं, हमें बड़ी संख्या में अपने वोट वापस पाने की उम्मीद है। संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हैं। बकौल उनके, एक तो तृणमूल और भाजपा का धुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का नजरिया है। वे मानते हैं कि सांप्रदायिक आधार पर खासकर मुसलमानों और वामपंथियों के खिलाफ धुवीकरण से तृणमूल और भाजपा दोनों को फायदा होगा।

सुजोन चक्रवर्ती और कांग्रेस के अब्दुल मन्नान ने नंदीग्राम से सटे खेजुरी ब्लॉक में साझा रैली की। इसी खेजुरी में 2006 और 2011 के बीच हुई हिंसा से लेफ्ट की ताकत टूटी थी और तृणमूल को शह मिल गई थी। अब 2020 में भाजपा और तृणमूल के बीच लगातार जारी जुबानी बयानबाजी और हिंसक वारदातों से तंग आ चुके और सरकार विरोधी रुझान से असंतुष्ट वोटों का मन बदला है इसलिए इन इलाकों में फिर माकपा को बढ़त मिलने लगी है।

यही कहानी उत्तर बंगाल के कूचबिहार की भी है। वहां हाल में दिनहाटा में कथित तौर पर स्थानीय तृणमूल नेताओं ने स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के राज्य सचिवालय सदस्य शुभ्रलोक दास को परेशान करने के लिए लड़कों को भेजा, तो उन्होंने तत्खोनिक् (फौरन) रैली करने का फैसला किया। दास कहते हैं, हमने रैली के लगभग 12 घंटे पहले फेसबुक पर इसकी घोषणा की तो करीब 500 लोग जुट गए। वाकई, एक साथ कोविड-19 और अमफेन चक्रवात के झटकों से हलकान राज्य के हर जिले हसुआ-हथोड़ी वाला लाल झंडा पूरे भरोसे से लहराने लगा है। माकपा के राज्य स्तरीय नेताओं का कहना है कि यह कठिनाई के दौर में स्वयंस्फूर्त प्रतिक्रिया है। राज्य समिति के एक सदस्य कहते हैं, कुछ महीने पहले तक, हमारे पास अग्रिम मोर्चे पर लड़के-लड़कियों की फौज कम ही दिखती थी। लेकिन अमफेन चक्रवात के राहत कार्य में हमारे साथ बहुत-से ऐसे जुड़े, जो बीसेक साल उम्र के हैं। यह वाकई उत्साहवर्द्धक है। दास की भी यही राय है। वे कहते हैं, भाजपा और उसके छात्र विंग के पास हिंदुत्व है, तो एसएफआई के पास असली मुद्दे हैं।

● राजेश बोरकर

2013-14 में भाजपा ने जिस सोशल मीडिया को आधार बनाकर कांग्रेस की 10 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था आज उसी सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी की जमकर फजीहत हो रही है। हर तरह के जोड़-तोड़ के लिए मशहूर भाजपा की आईटी सेल इस समय वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बचाव नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा का आईटी सेल कमजोर हो गया है। अगर ऐसा है तो यह भाजपा के लिए चिंता का विषय है।

साल 2014 में आकाशवाणी पर शुरू हुआ 'मन की बात' एक लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम है जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट करते हैं। हर महीने के आखिरी इतवार को प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, राजनीति और सरकार से जुड़े मुद्दों से इतर बातचीत करते हैं। इसे न सिर्फ उनके समर्थक और आलोचक काफी ध्यान से सुनते रहे हैं बल्कि इसमें कही गई बातें कई दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं। इसका ताजा (68वां) एपिसोड बीते अगस्त की 30 तारीख को प्रसारित हुआ था। लेकिन इस बार मन की बात कार्यक्रम अपने विषय या प्रधानमंत्री के विचारों-सुझावों के चलते नहीं बल्कि किसी और ही वजह से चर्चा का विषय बना। वह वजह थी, यूट्यूब पर मन की बात कार्यक्रम के वीडियो को लाखों की संख्या में डिसलाइक किया जाना।

भाजपा के यूट्यूब चैनल से लाइव स्ट्रीम किए गए इस वीडियो पर महज 24 घंटों में सवा पांच लाख से अधिक डिसलाइक आ चुके थे। जबकि तब तक इस पर आए लाइक्स की गिनती महज 79 हजार ही थी। यहां पर चौंकाने वाली बात यह रही कि **डिसलाइक्स कैम्पेन** से अचकचाकर भाजपा ने अपने इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट का ऑप्शन ही कई दिनों के लिए बंद कर दिया। भाजपा के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी इसे अपलोड किया गया था। इस पर भी महज 13 घंटों में 40 हजार से ज्यादा डिसलाइक्स किए जा चुके थे। इन वीडियोज से जुड़ी ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि बीच में डिसलाइक्स की गिनती हजारों की संख्या में कम भी हो गई। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल, भाजपा के चैनल पर प्रतिक्रियाओं के सभी विकल्प खोल दिए गए हैं और वहां मन की बात के वीडियो पर लगभग 12 लाख और नरेंद्र मोदी के चैनल पर दो लाख 86 हजार डिसलाइक्स देखे जा सकते हैं।

मन की बात कार्यक्रम का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा इकलौता वीडियो नहीं था जिस पर डिसलाइक्स की भरमार रही। हाल ही



कमजोर पड़ती ताकत!

अब युवाओं ने संभाला विरोध का मोर्चा

आईटी सेल के बेअसर दिखने की वजहों पर गौर करें तो पहला कारण यही समझ में आता है कि इस बार उसकी भिड़ंत ऐसे युवाओं से हुई है, जो न सिर्फ सोशल मीडिया का हर तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं बल्कि इस पर चलने वाले दांव-पेचों से भी भलीभांति वाकिफ हैं। वे इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से ही प्रेरित होकर सृजनात्मक तरीकों का सहारा लेते हैं और बिना ज्यादा गाली-गलौज या भद्दी भाषा का प्रयोग किए आईटी सेल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। वे अपने अभियान को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करने वालों से भी बचते दिखते हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री तक अपनी अलग-अलग मांगें पहुंचाने की कोशिश कर रहे इन युवाओं की संख्या भी लाखों में है। आईटी सेल और उसके सहयोगी समूहों को मिलाकर भी इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम कुछ हजार ही बैठेगी। ऐसे में सेल के लिए इन युवाओं की आवाज को किसी जवाबी हैशटैग या ट्रेंड्स के जरिए दबा पाना मुश्किल हो रहा है।

में वे हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के दीक्षांत परेड समारोह में भी वचुंअली शामिल हुए थे। इस आयोजन के उनके वीडियो पर भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया देखी गई। भाजपा के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को एक दिन पहले ही प्रीमियर कर दिया गया था। यानी जो लाइव वीडियो कुछ घंटे बाद आने वाला था, उसे लोग पहले ही शेयर कर सकते थे या उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे। यहां पर देखने वाली बात यह रही कि स्ट्रीमिंग के 13 घंटे पहले ही वीडियो पर एक हजार लाइक्स के मुकाबले 11 हजार डिसलाइक्स आ चुके थे। नतीजतन, इस वीडियो पर भी प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों का विकल्प बंद कर दिया गया। वीडियो जारी होने के बाद

जब इसे फिर शुरू किया गया तो कुछ ही घंटों में 88 हजार डिसलाइक्स दर्ज हो चुके थे। इसके बाद से रिपोर्ट लिखे जाने तक इस वीडियो पर ये विकल्प डिसेबल ही रखे गए हैं। प्रतिक्रियाओं का यही क्रम प्रधानमंत्री के उस वीडियो पर भी रहा जिसमें वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यों के राज्यपालों के साथ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करते दिखाई दे रहे थे।

नरेंद्र मोदी के वीडियोज पर एकतरफा प्रतिक्रियाओं की भरमार होना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार इनका पलड़ा उनके पक्ष में न होना जरूर नई और अनोखी बात है। अनोखी इसलिए कि इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की आलोचनात्मक टिप्पणियां या ट्रेंड्स पहले तो सामने आते नहीं थे

और अगर ऐसा होता भी था तो भाजपा की आईटी सेल समय रहते इनमें से ज्यादातर से निपट लेती थी। लेकिन अब वह इस मामले में उतनी प्रभावी नजर नहीं आ रही है। बीते कुछ हफ्तों से चल रहे छात्रों और युवाओं के सोशल मीडिया अभियान से जुड़ी कई बातें हैं जो इसकी तरफ इशारा करती हैं। इसे चलाने वालों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा (नीट और जेईई) को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे छात्र और तमाम बेरोजगार युवा शामिल हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तिथि, किसी के नतीजे या ये सब हो जाने के बाद अपने जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं।

अगर युवाओं के इस कैंपेन को ध्यान से देखें तो यह भाजपा की आईटी सेल को उसी की भाषा में जवाब देता दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो पर आई डिस्लाइक्स की यह भरमार पिछले दिनों सड़क-2 के ट्रेलर पर आए रिकॉर्ड डिस्लाइक्स से प्रेरित थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय और निष्पक्ष मौजूदगी रखने वाले कई लोगों का मानना है कि सड़क-2 के खिलाफ चला यह अभियान भाजपा आईटी सेल का भी कारनामा था। इन लोगों का मानना था कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने, बिहार और महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक हितों को साधने और ऐसा करने में कथित तौर पर भाजपा की मदद करने वाली कंगना रनौत को मदद करने के उद्देश्य से आईटी सेल इस अभियान में शामिल थी। कैंपेन चला रहे युवा आईटी सेल से उसी के तरीके से निपटने की तैयारी में थे, इसका अंदाजा इस बात से भी लग जाता है कि जब मन की बात वाले वीडियो पर आने वाले डिस्लाइक्स को भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने तुर्की से आने वाले बॉट्स बताए तो अगले वीडियो में छात्रों ने अपने शहर-कस्बों के नाम भी लिख दिए। कई छात्रों ने व्यंग्य करते हुए अपने शहरों को तुर्की या कनाडा बता डाला।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन का अगला चरण भाजपा आईटी सेल से आगे बढ़कर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकी लेता हुआ भी दिखाई दिया और यहां पर भी आईटी सेल कुछ भी करने में अक्षम ही दिखी। 5 सितंबर को युवाओं ने जहां छात्र कर्षु आयोजित कर 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाई वहीं 9 सितंबर को वे रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाकर रोजगार की मांग करते दिखाई दिए। युवाओं ने सितंबर के तीसरे हफ्ते को बेरोजगार सप्ताह की तरह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तरह मनाया। इस दिन सोशल मीडिया पर हैशटैग बेरोजगार सप्ताह और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के साथ लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए। इसके जवाब में अगले दिन आईटी सेल



संसद में भी घिरी भाजपा

कोरोनाकाल में केंद्र सरकार ने कृषि सहित कई बिल पारित करवाए हैं, जिसका संसद में जमकर विरोध हुआ। आलम यह हुआ कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। आजादी के बाद के दशकों के कानूनों या सरकारी फैसलों को लें तो जिस तरह से भाजपा की सरकार उनमें से ज्यादातर को बदल रही है, वह इस बात का सबूत है कि देश का नया बहुमत उन कानूनों के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता। इसलिए लोकतंत्र में विपक्ष को साथ लेना जरूरी है। राज्यसभा में उप सभापति के साथ जो बर्ताव हुआ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष के 8 सांसदों को जिस तरह निर्लंबित कर दिया गया है वह भी ठीक नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवहार एक-दूसरे को सजा देने में नहीं हो सकता। लोकतंत्र के रक्षकों को व्यवहार में भी लोकतांत्रिक मिजाज दिखाना चाहिए। क्या एक परिपक्व परिवार में पिता हमेशा बेटे-बेटियों की पिटाई करता रहेगा, क्योंकि वे छोटे हैं। या फिर क्या ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता रहेगा। इन्हीं कमियों से निपटने के लिए लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और भारत में तो बिहार के वैशाली में लोकतंत्र की लंबी परंपरा रही है। सरकार भी देश की रक्षा के लिए बनी संस्थाओं से ताकत लेती है। उसे इस ताकत का इस्तेमाल विपक्ष या विरोधी आवाजों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी आवाज को शामिल करने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र की यही पहचान है। अगर संसद के पास अपने सदस्यों को सजा देने के अधिकार है तो वे आज के जमाने से मेल नहीं खाते। संसद में विरोध करने वाले सदस्य अपराधी नहीं, उन्हें सजा देकर उन्हें अपराधी का दर्जा भी नहीं दिया जाना चाहिए। आज की संसद किसी अंग्रेजी सरकार की संसद नहीं वह सार्वभौम भारत के नागरिकों द्वारा चुनी और सरकार बनाने और उस पर कंट्रोल करने वाली संसद है। उसे नई परंपराएं गढ़ने का हक है।

हैशटैग राष्ट्रीय बार डांसर दिवस ट्रेंड करवाती दिखाई तो दी लेकिन तमाम लोगों ने इसे न सिर्फ गैरजरूरी बल्कि आईटी सेल की खिसियाहट भी कहा।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि रोजगार की मांग कर रहे इन युवाओं में एक बड़ी संख्या उनकी भी होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था या अब तक उनका समर्थन करते रहे थे। आमतौर पर सोशल मीडिया पर आईटी सेल द्वारा चलाए जाने वाले किसी प्रोपगैंडा कैंपेन को युवा वर्ग का समर्थन भी हासिल रहा करता था जिसके चलते उनके ट्वीट या ट्रेंड्स बड़े-बड़े आंकड़े हासिल करते दिखाई पड़ते थे। लेकिन न केवल युवा इस समय आईटी सेल के प्रोपगैंडा को कम समर्थन दे रहे हैं बल्कि अन्य लोगों द्वारा उसे मिलने वाला समर्थन भी इन दिनों कम हो गया लगता है।

आम दिनों में, आम यूजर अपनी आंखों पर धर्म-संस्कृति की पट्टी लगाए बैठा रहता था लेकिन कोरोना त्रासदी ने उनकी आंखें कुछ हद तक खोल दी हैं। कुछ हद तक शब्द का इस्तेमाल कोई अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए नहीं कर रहा बल्कि लोगों में आई जागरूकता की मात्रा को देखकर किया जा रहा है। दरअसल, कई लोग इस बात से प्रभावित हुए कि उनके किसी करीबी की नौकरी गई, कई इससे कि उनका कोई जानने वाला जब कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो अस्पतालों ने खून के आंसू रुला दिए, वहीं कई अपने आसपास मची बाकी अफरा-तफरी को देखकर मीडिया और सोशल मीडिया दोनों से विरक्त हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय आशीष मिश्रा कहते हैं, 'इसका फायदा ये हुआ है कि अब वे व्हाट्सएप फॉरवर्ड को क्रॉसचेक करने लगे हैं या घर के बच्चों से पूछते हैं कि यह सच है क्या। इन सब ने मिलाकर आईटी सेल की रफ्तार कम की है।

● इन्द्र कुमार

जमीन खो चुकी कांग्रेस



6

भारत की राजनीति में यह मान्यता है कि जिस पार्टी की सरकार उत्तरप्रदेश में रहती है, वही केंद्र में शासित होता है। इसकी वजह यह है कि उत्तरप्रदेश की राजनीति का प्रभाव कई राज्यों पर पड़ता है। इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश पर अपना ध्यान सबसे अधिक केंद्रित किया है। प्रियंका गांधी वहां फुल टाइम पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। वहीं अब राहुल गांधी भी उत्तरप्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस अगर मेहनत कर ले तो वह उत्तरप्रदेश के रास्ते देश में अपनी खोई हुई जमीन पा सकती है।

देश में कांग्रेस की आज भी गहरी पैठ हैं। जानकारों का कहना है कि सही नेतृत्व की कमी के कारण कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। जिस राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व प्रभावशाली है वहां पार्टी मजबूत स्थिति में हैं। अब तो उग्र कांग्रेस के संगठन पर प्रियंका गांधी की कुशल रणनीति का प्रभाव भी स्पष्ट नजर आने लगा है, कांग्रेस संगठन आज प्रदेश में एक अलग कलेवर वाले संघर्षशील अंदाज में जनसमस्याओं को लेकर आए दिन सड़कों पर संघर्षरत नजर आने लग गया है, अब वो जनहित के मसलों पर जेल तक जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने लगा है।

कांग्रेस को फिर से उबारने की कोशिश करती प्रियंका गांधी के कुशल नेतृत्व व कारगर रणनीति के चलते ही, आज उग्र में कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि पार्टी नए जोशोखरोश के साथ उग्र के राजनीतिक मैदान में अघोषित मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के रूप में बेहद तत्परता के साथ, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, अन्य सभी वर्ग के आम लोगों की समस्याओं को उठाकर व आम जनता के बीच जाकर, एक बेहद सक्रिय राजनीतिक दल की भूमिका का पूर्ण ईमानदारी से निर्वाहन करने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी उग्र में पार्टी को लगातार समय दे रही है, वह पार्टी के संगठनात्मक नजरिए से बेहद अच्छा है और उसको देखकर

लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी यह समझ आ गया है, कि भविष्य में कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता उग्र की धरती से ही निकलेगा। इसलिए ही इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उग्र में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी खोई हुई जमीन व जनाधार को वापस हासिल करने के लिए दिन-रात एक करके अपनी संघर्षशील राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में धरातल पर जबरदस्त मेहनत कर रही है। जैसे पिछले बहुत लंबे समय से कांग्रेस हाईकमान के उपेक्षित व्यवहार के चलते उग्र में कांग्रेस पार्टी एकदम सुसुप्त अवस्था में चली गई थी। जिसको खड़ी करने के लिए अब प्रियंका गांधी दिन-रात मेहनत कर रही हैं।

जितिन पर मेहरबानी

पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उन 23 नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव और इसे और ज्यादा सजीव बनाने के लिए पत्र लिखा था। उग्र में इसको लेकर कुछ नेताओं ने विरोध भी किया था। हालांकि, जब गत दिनों केंद्रीय नेतृत्व ने बदलाव किया तो जितिन को प्रमोशन देकर यह साफ कर दिया कि उनके पत्र को सकारात्मक तौर पर लिया गया है। ऐसे में प्रदेश संगठन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह संदेश किसके लिए है? उनके लिए जिन्होंने जितिन के खिलाफ प्रदर्शन करवाया था? पत्र में पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की गई थी। साथ ही, संगठन को जीवंत बनाने की योजनाओं पर काम करने के लिए कहा गया था।

उग्र के सदन में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की कम संख्या बल की वजह से जो कांग्रेस के विधायकों की जनहित की आवाज दब गई थी, अब वो आवाज प्रियंका गांधी के दिए गए मंत्र से आए दिन सदन से लेकर सड़क तक जगह-जगह विरोध-प्रदर्शनों के रूप में गूंजती दिखाई देती है। अब प्रदेश के आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं में ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ है कि वो बेहद मुखर होकर जन विरोध के रूप में सड़कों पर दिखने लगा है। कांग्रेस पार्टी की सदन से लेकर सड़क तक इस बेहद मुखर होती आवाज से अब राज्य में सत्तापक्ष भी अपने भविष्य की चिंता करके कहीं ना कहीं प्रियंका

गांधी के फैक्टर से भयभीत है, वह कदम-कदम पर प्रियंका गांधी के फैक्टर की काट ढूँढ़ रहा है। उग्र में कांग्रेस को फिर से उबारने की कोशिश करती प्रियंका गांधी उस वजह से ही चिंतित होकर उग्र सरकार प्रियंका के प्रदेश दौरों के दौरान, उनकी राह में सरकारी तंत्र से अवरोध उत्पन्न कराने का कार्य करती है।

आज प्रियंका गांधी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार समय-समय पर विभिन्न तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी आम जनमानस की बेहद सशक्त आवाज बनकर बेखौफ होकर उग्र व केंद्र सरकार की बहुत सारी नीतियों को जनविरोधी बताकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से लेकर के राजनीति के अखाड़े तक में व जनता के बीच जाकर लगातार संघर्ष कर रही हैं। वो लोगों से संपर्क करके उनके दुख-दर्द में भागी बनने का प्रयास कर रही हैं। यह शैली उनके बेहद कुशल राजनेता होने के गुण को प्रदर्शित करती है।

प्रियंका गांधी की इस संघर्षशील कार्यशैली को देखकर, बहुत सारे देशवासियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी में देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है। लोग उनके दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति, अपनी बात को बेबाक होकर सरल मृदुभाषी हिन्दी में रखने वाली शैली व आम जनता के बीच रहने वाली शैली को देखकर मानते हैं कि वो आने वाले समय में देश की बेहद लोकप्रिय जननेता के रूप में खुद को बहुत ही जल्द स्थापित कर सकती है। हालांकि लोगों का मानना है कि इसके लिए उनको कांग्रेस की गांधी, नेहरू, पटेल, शास्त्री, इंदिरा व राजीव गांधी वाली विचारधारा पर दृढ़ संकल्प के साथ कायम रहना होगा, कांग्रेस के कुछ **वरिष्ठ नेताओं** पर हावी होती अन्य विचारधारा को अपने ऊपर व अपने आसपास के माहौल में हावी होने से रोकना होगा और उस विचारधारा के लोगों को अपने सिस्टम में एडजस्ट होने देने से बचना होगा। आज कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के साथ-साथ देश के बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए उनके सामने भी आम जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरने की बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है।

आज देश के राजनीतिक हालात देखकर अधिकांश लोगों का मानना है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है कि देश में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी हमेशा बरकरार रहे। इसके साथ ही यह भी बेहद जरूरी है कि विपक्ष का नेतृत्व भी एक ऐसे सशक्त समझदार शख्स के हाथ में हो, जो उसे सही दिशा देकर आम जनता की आवाज को सरकार के सामने बुलंद ढंग से उठा सके। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश व देश के लोगों को वह मजबूत चेहरा प्रियंका गांधी में दिखाई दे रहा है।



क्या प्रियंका उग्र फतह कर पाएंगी

प्रियंका गांधी ने उग्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला व शहर अध्यक्ष तक सभी बदल डालें हैं। दरअसल प्रियंका गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना चाहती हैं कि अब पार्टी में आरामतलबी नहीं चलेगी, आप सड़कों पर उतरकर जनहित के मसलों के लिए संघर्ष तो करो, अब वह दिन दूर नहीं है जब उग्र में कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस अवश्य मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ आरामतलबी से ग्रस्त कांग्रेस संगठन को प्रियंका गांधी अपनी इच्छा के अनुरूप धरातल पर संघर्षशील बनाने के लिए स्वयं सड़कों पर उतरकर जनहित के मसलों पर संघर्ष करके, पार्टी में नई तरह से जान फूंकने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को भी यह ध्यान रखना होगा कि गांधी-नेहरू की विचारधारा के लिए पहचाने जानी वाली कांग्रेस पार्टी पर अन्य किसी विचारधारा के लोग हावी ना हो पाए, क्योंकि यह भी कटु सत्य है कि कहीं ना कहीं यह लोग कांग्रेस के सिस्टम पर हावी होने लगे हैं और वो कांग्रेस के बेहद निष्ठावान व गांधी-नेहरू की विचारधारा वाले कांग्रेसियों को आए दिन परेशान कर रहे हैं। जिनके मान-सम्मान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी उग्र में कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी की है।

लॉकडाउन से पहले कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी की स्टार प्रचारक जोड़ी राहुल-प्रियंका के बलबूते देश में नागरिकता संशोधन कानून व अन्य मसलों को लेकर मजबूती से भाजपा सरकार को घेरने का कार्य किया था, वह जनता के बहुत बड़े वर्ग की नजरों में बेहद काबिले-तारीफ था। उस दौरान प्रियंका गांधी ने दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर लखनऊ की सड़कों पर बेहद मुखरता के साथ सरकार का विरोध किया था, जिसने जनता के बीच उनकी एक संघर्षशील राजनेता की छवि बनाने का कार्य किया था। उग्र में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी के खोए हुए जनाधार को वापस हासिल करने के प्रयास के रूप में एक अच्छा मौका कांग्रेस को मिला है। जनता की इच्छा रही तो यह प्रयास प्रदेश में कांग्रेस को बैसाखियों से मुक्त करके अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है और प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा धरातल पर बहुत लंबे समय के बाद किया गया कोई ठोस कारगर राजनीतिक रामबाण उपाय भी साबित हो सकता है।

प्रियंका गांधी की इच्छा के अनुरूप उग्र में कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार आरामतलबी से ग्रस्त व मृतप्रायः हो चुके कांग्रेस संगठन की पूर्ण

ओवरहालिंग करके उसको चुस्त-दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से उग्र कांग्रेस कमेटी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या व आम जनमानस के सरोकार के विभिन्न मुद्दों को लेकर बेहद आक्रामक अंदाज में प्रदेश सरकार पर आए दिन हमलावर है, उसमें अब प्रियंका गांधी की कार्यशैली की छाप स्पष्ट नजर आने लगी है। खैर यह तो आने वाला समय व जनता की सर्वोच्च अदालत ही तय करेगी कि प्रियंका गांधी अपने मिशन उग्र में कहां तक कामयाब होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी **आम जनमानस** के हित की लड़ाई की शैली से प्रदेश सरकार को यह दिखा दिया है कि जनता ने उग्र में कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए बेशक विधायक ना दिए हों, लेकिन वो अब अन्य दलों को पीछे छोड़कर जनता की बात को दमदार ढंग से उठाकर भाजपा के सत्ता सिंहासन को हिलाने का कार्य जरूर कर रही है। वैसे भी उग्र में कांग्रेस की सबसे बड़ी जरूरत राज्यभर में संगठन को मजबूती प्रदान करके उसमें नया जोश भरना है, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने अपने पहले दिन के साथ ही कर दी थी।

● दिल्ली से रेणु आगाल

छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की कवायद एक बार फिर से शुरू कर दी है। सरकार इस बार राशनकार्ड धारकों की संख्या को आधार बनाएगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार की कवायद को हाईकोर्ट से दोबारा झटका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अपने 19 सितंबर की बैठक में सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय एक बार फिर लिया है। कैबिनेट के निर्णय में कहा गया है, 'राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर 'सामान्य वर्ग' के लोगों को शासकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित हाईकोर्ट में लंबित मामले के निराकरण के लिए सरकार नया डेटाबेस तैयार करेगी। इसके लिए ओबीसी जनसंख्या का निर्धारण राशनकार्ड की संख्या के आधार पर किया जाएगा।' लेकिन आरक्षण के लिए अंतिम डेटा 2019 में सरकार द्वारा गठित छबीलाल पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में तैयार किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय में यह नहीं बताया गया है की ओबीसी जनसंख्या का निर्धारण राशनकार्ड से कैसे किया जाएगा लेकिन सरकार के अनुसार इस डेटा का अनुमोदन ग्राम सभा तथा नगरीय निकायों से कराया जाएगा। खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया, 'राशनकार्ड धारकों के नाम के आधार पर नगरीय और ग्रामीण निकाय स्तर पर उनकी जाति की गणना होगी और फिर जनसंख्या का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। यही कारण है कि सरकार आने वाले दिनों में राशनकार्ड की संख्या भी बढ़ाएगी जिससे उसका ओबीसी जनसंख्या प्रतिशत का दावा और पुष्ट हो सके।'

बघेल सरकार ने सितंबर 2019 में एक अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14 से 27 प्रतिशत, एससी आरक्षण 12 से 13 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत निर्धारित किया था। एसटी आरक्षण पूर्ववत् 32 प्रतिशत ही रखा गया। इस तरह बघेल सरकार ने राज्य की शासकीय नौकरियों में कुल 82 प्रतिशत आरक्षण कर दिया था। अध्यादेश जारी करने के बाद सरकार ने जनसंख्या का डेटाबेस बनाने के लिए पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का मंडेट राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर एक 'क्वॉटिफिएबल डेटा' तैयार करना था। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश की ओबीसी जनसंख्या 47 प्रतिशत है। सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में कई याचिकाकर्ताओं ने



ओबीसी आरक्षण कार्ड

भाजपा के सवाल

प्रदेश में विपक्ष का कहना है कि सरकार का ओबीसी आरक्षण का निर्णय राजनीति से प्रेरित है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार अपनी असफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए 'नए प्रपंच' गढ़ रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया, 'आरक्षण के मुद्दे पर सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले एक साल से चुप बैठे थे और अब अचानक ऐलान किया गया ओबीसी आरक्षण का निर्धारण फिर से किया जाएगा। यदि यह सच है तो पहले वाले अध्यादेश को क्यों रद्द होने दिया गया।' कौशिक आगे कहते हैं, 'सरकार ने समय रहते अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रबंधन में पूरी तरह असफल होने के बाद अब मुख्यमंत्री जनता को नए शगूफ़े से गुमराह कर हैं।' भाजपा के पूर्व विधायक और पार्टी के कद्दावर नेता देवजीभाई पटेल कहते हैं, 'सरकार को भी पता है कि उसके इस कदम का हथ्र वया होने वाला है। सरकार के पास आने वाले मरवाही विधानसभा उपचुनाव में उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री ओबीसी राजनीति का सहारा ले रहे हैं।'

चुनौती दी। उनके अनुसार सरकार का ओबीसी आरक्षण अध्यादेश नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ), आरबीआई और भारत सरकार के बीपीएल सर्वे के आंकड़ों पर आधारित था जो असंवैधानिक और गैरकानूनी था। हाइकोर्ट ने अक्टूबर 2019 में इन याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करते हुए सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। बाद में सरकार द्वारा अध्यादेश को विधानसभा में नहीं लाए जाने से

वह अमान्य हो गया।

सरकार द्वारा जारी एक वक्तव्य में भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों ने खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए राशनकार्ड आधारित डेटाबेस को विश्वसनीय बताया है। सरकार के अनुसार उच्च न्यायालय के स्टे के मद्देनजर ओबीसी वर्ग का एक पारदर्शी एवं विश्वसनीय डेटाबेस बनाया जाएगा। राशनकार्ड धारकों के परिवारों की सूची ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में सार्वजनिक की जाएगी। इस संबंध में दावा-आपत्ति का निराकरण और छूटे हुए परिवारों का राशनकार्ड बनाने नए आवेदन भी लिए जाएंगे। कैबिनेट के निर्णय में कहा गया है कि सरकार नए डेटाबेस तैयार करने का काम पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में नई गाईडलाइन जारी कर करेगी। बता दें कि पटेल कमीशन की समयावधि 6 माह थी लेकिन सरकार ने उसकी रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया।

खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा कैबिनेट को दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी 66,73, 133 राशनकार्ड धारक हैं, जिनकी कुल सदस्य संख्या 2,47,70,566 है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से 31,52,325 कार्ड धारक ओबीसी हैं जिनकी सदस्य संख्या 1,18,26,787 है। यह कुल लाभान्वित जनसंख्या का 47.75 प्रतिशत है। वहीं सामान्य वर्ग के राशनकार्डों की संख्या 5.89 लाख और सदस्य संख्या 20,25,42 बताया है जो राज्य में कुल लाभान्वित जनसंख्या का 8.18 प्रतिशत है। 'राशनकार्ड की संख्या को आधार मानकर जनसंख्या सर्वे कराना कई प्रश्नों को जन्म देता है। पहले तो राशनकार्डों की संख्या ही प्रदेश में एक घोटाला साबित हुई है।'

● रायपुर से टीपी सिंह

देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत यूं भी मिले होते तो चर्चा तो होती ही। मीडिया की सुर्खियां बनतीं ही। लोग अपने-अपने तरीके से कयास भी लगाते ही, लेकिन चुपके-चुपके होटल पहुंचकर मुलाकात से रहस्य भी गहराएगा और बातें तो बनेंगी

ही! महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद भाजपा और शिवसेना के प्रमुख नेताओं की सामने आई ये पहली मुलाकात है। अगर ऐसी मुलाकातें मीडिया की नजर से छूट गईं हों तो और बात है। अब ऐसी मुलाकातें होंगी बरबस ध्यान तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर ही फोकस होगा- सब ठीक तो है ना? मुलाकात की जो वजह बताई गई है वो सुनकर सस्पेंस और भी बढ़ जा रहा है- इंटरव्यू के लिए! गजब बात करते हैं। इंटरव्यू के लिए संजय राउत भला कौनसी तैयारी करते हैं कि पहले मिलना पड़ता है। बड़ा सवाल तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस के एक इंटरव्यू के लिए संजय राउत को होटल में छुपके मिलाने की जरूरत क्यों आ पड़ी?

शिवसेना के मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू पढ़ने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। और जब इंटरव्यू प्रकाशित होगा तो देवेंद्र फडणवीस ऐसे दूसरे गैर शिवसेना नेता होंगे **जिनको ऐसा अवसर मिलेगा**। सामना में किसी गैर-शिवसेना नेता के पहले इंटरव्यू का रिकॉर्ड एनसीपी नेता शरद पवार के नाम दर्ज है। और जिन परिस्थितियों में संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, ऐसी ही चर्चाओं को अक्टूबर, 2019 में भी हवा दी गई थी। शरद पवार का इंटरव्यू जुलाई, 2020 में सामना में प्रकाशित हुआ था। तब संजय राउत महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाने के बाद शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे। मुलाकात के बाद इंटरव्यू की कोई बात तो नहीं बताई थी, हां, इतना जरूर समझाने की कोशिश की कि वो दिवाली की बधाई देने गए थे। शिष्टाचार वश। चूंकि उन दिनों मुलाकातें किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ करती रहीं, इसलिए संजय राउत की बातों पर उतने लोगों ने शक नहीं किया होगा जितने किसानों के नाम पर होने वाली मुलाकातों



मुलाकात के मायने

को लेकर किया करते थे। आखिरकार किसानों के नाम पर होने वाली मुलाकातों का ही नतीजा रहा कि भाजपा से गठबंधन तोड़कर शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया और उद्धव ठाकरे अपने पिता बालासाहेब ठाकरे के किए वादे को पूरा करते हुए एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिए, बिठा तो दिए लेकिन तिपहिंद पर खड़ी कुर्सी अक्सर डगमगाने लगती है। ऐसा कई बार हो चुका है और एक बार फिर से वही हो रहा है।

संजय राउत शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता हैं। अब्बल तो ये होना चाहिए कि संजय राउत के बयान के बाद किसी को संशय नहीं होना चाहिए। किसी भी मुद्दे पर, अपवादों को छोड़कर। मुश्किल तो ये है कि संजय राउत जितने बयान नहीं देते उससे ज्यादा सफाई देते फिरते हैं। मिसाल के तौर पर, संजय राउत ने कंगना रनौत को पहले 'हरामखोर लड़की' बताया। फिर समझाने की कोशिश की कि उनकी भाषा में 'नॉटी गर्ल', दरअसल, हरामखोर लड़की को कहते हैं- और फिर जब सामना में आर्टिकल लिखने बैठे तो 'नटी' लिख डाला- मराठी में नटी एक्टर को कहते हैं। हालांकि, ये गूगल ज्ञान है। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात को लेकर दोनों तरफ से एक सी जानकारी दी गई होती तो मन मान भी जाता, लेकिन अलग-अलग वजह बताकर शक पैदा कर दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता की तरफ से तो बड़े ही साफ शब्दों में

इंटरव्यू की बात बता दी गई है, लेकिन संजय राउत पलटकर सवाल पूछने लगते हैं- मिल नहीं सकते क्या? किसी भी मामले में जांच तभी होती है जब उससे जुड़े दो व्यक्ति अलग-अलग बात बताएं। इस मामले में भी करीब-करीब ऐसा ही हो रहा है।

महाराष्ट्र भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये की सलाह है कि मुलाकात को लेकर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण निकाले जाने की जरूरत नहीं है। केशव उपाध्ये ने मराठी में अपने एक ट्वीट में बताया है कि संजय राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू करना चाहते थे, सिर्फ इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। केशव उपाध्ये के मुताबिक, ये इंटरव्यू अभी नहीं होगा, बल्कि देवेंद्र फडणवीस जब बिहार चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद लौटेंगे तब वो इंटरव्यू देंगे। मतलब, ये इंटरव्यू का 'कमिंग अप' टीजर रहा। आखिर संजय राउत एक इंटरव्यू के लिए कितने राउंड इंटरव्यू लेते हैं? क्या पहले इंटरव्यू में वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि बंदा सामना में इंटरव्यू देने लायक है भी या नहीं? और फिर जब संतुष्ट होते हैं तब बात आगे बढ़ती है। मतलब, सामना में जो इंटरव्यू पढ़ने को मिलते हैं वो फाइनल होता होगा और उसके पहले कई बार प्री-इंटरव्यू सेशन के लिए मुलाकातें हो चुकी होंगी।

● बिन्दु माथुर

संजय राउत को ये भी पता है कि लोग देवेंद्र फडणवीस से मिलने को लुका-छिपी मुलाकात मानेंगे, इसलिए सफाई देने के दौरान ही ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इस मुलाकात के बारे में मालूम था। दोनों पक्षों की सफाई के बावजूद इस खास मुलाकात को सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद के राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से जोड़कर देखा जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच काफी तनावपूर्ण संवाद

मुद्दों पर चर्चा वाली मुलाकात के आगे क्या?

हुए। पहले तो भाजपा के पिता-पुत्र नेता नारायण राणे और नितेश राणे शिवसेना नेतृत्व उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर हमलावर रहे, लेकिन बाद

में भाजपा के ओर भी नेताओं के बयान आ गए। सुशांत सिंह केस की वजह से ही देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव में प्रभारी बनाकर पटना भेजा गया। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मौत की वजह से ड्रग्स की तरफ शिफ्ट हो चली है, ऐसा लगता है राजनीति की लाइन भी अब बदल चुकी है।

फिल्म सिटी की सियासत

उप्र की योगी सरकार ने उस 'मुंबई' को आइना दिखा दिया है जो 'बॉलीवुड' के चलते 'इतराया' करता है। बॉलीवुड की पहचान हिन्दी फिल्मों से जुड़ी है। बॉलीवुड में करीब 80 प्रतिशत कलाकार, लेखक, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ उत्तर भारत से आकर अपनी किस्मत

अजमाता है। जहां की मातृभाषा हिन्दी है। अक्सर कहा जाता है कि मुंबई लोगों की किस्मत 'संवारी' है। देशभर से हर दिन लाखों लोग अपने हसीन सपने पूरे करने मुंबई आते हैं। बॉलीवुड का नाम अंग्रेजी सिनेमा उद्योग हॉलीवुड के तर्ज पर रखा गया है। हिन्दी फिल्म उद्योग बॉलीवुड में बनीं

हिन्दी फिल्में हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों के लोगों के दिलों की धड़कन हैं।

बॉलीवुड में करीब 20 भाषाओं में फिल्में बनती हैं, लेकिन इसमें 80 फीसदी हिस्सा हिन्दी फिल्मों का है। हिन्दी फिल्मों में उर्दू, अवधी, बम्बइया हिन्दी, भोजपुरी, राजस्थानी जैसी बोलियां भी संवाद और गानों में देखने को मिल जाती हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में प्यार, देशभक्ति, परिवार, अपराध, भय, इत्यादि मुख्य विषय होते हैं। बॉलीवुड भारत में सबसे बड़ी फिल्मी नगरी है। यहां का देश के शुद्ध बॉक्स ऑफिस राजस्व में से 43 प्रतिशत का योगदान रहता है, जबकि तमिल और तेलुगू सिनेमा 36 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी के क्षेत्रीय सिनेमा का योगदान मात्र 21 प्रतिशत है। बॉलीवुड दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। बॉलीवुड कार्यरत लोगों और निर्मित फिल्मों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक है।

बॉलीवुड की फिल्मों की आत्मा हिन्दी है तो इस फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की नंबर दो हैसियत दिलाने में हिन्दी भाषी लोगों का विशेष योगदान है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बॉलीवुड भले हिन्दी भाषियों के कंधे पर खड़ा हो, परंतु उत्तर भारत से आने वाले कलाकारों को मुंबई कभी वह सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ जिसके वह हकदार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह शिवसेना जैसे राजनैतिक दल हैं, जो मुंबई को मराठी भाषियों की 'बपोती' मानती है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के साथ अक्सर बदसलूकी की जाती है। उन्हें भैया कहकर अपमानित किया जाता है। इनके रिश्ते और ठेले तोड़ दिए जाते हैं। आम उत्तर भारतीय तो दूर उत्तर भारत से आए बड़े-बड़े कलाकार तक मुंह नहीं खोल सकते हैं, जो



योगी के कदम की सराहना

खैर, अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प के साथ सिर्फ उप्र के कलाकार ही नहीं, सिने जगत के दिग्गज भी जुड़े हैं। बाहुबली फिल्म के लेखक विजयेंद्र प्रसाद ने हर संभव सहयोग देने की बात कही है। कहा है कि वह प्रस्ताव भी भेजेंगे। कला निर्देशक नितिन देसाई ने फिल्म इंस्टीट्यूट का सुझाव दिया। साथ ही सभी ने अपने-अपने सुझाव देने की बात कही है। फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित का कहना है कि मुंबई के बाद उप्र सरकार इकलौती है, जो इस दिशा में आगे आई है। उन्होंने भरोसा जताया है कि 2023 तक उप्र की फिल्म इंडस्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। मशहूर गायक उदित नारायण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में गाना गुनगुना रहे हैं, 'उप्र को जैसा मुख्यमंत्री चाहिए था, मिल गया।' वहीं, बॉलीवुड के ड्रग मामले पर बोले कि उप्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह संस्कारों की धरती है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को उप्र में फिल्म सिटी का निर्माण उत्सव जैसा लगता है। अनुपम कहते हैं, 'योगी जी की क्षमता पर सभी को भरोसा है। उप्र की फिल्म सिटी उप्र में तो होगी, लेकिन पूरी दुनिया इसे अपना मानेगी। यह ताजमहल की तरह ही दुनियाभर को आकर्षित करने वाली होगी।'

खोलता है उसका हश्र फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जैसा होता है। उत्तर भारत से आए फिल्मी कलाकारों के साथ हमेशा से दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ ने उप्र में नई फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की तो बॉलीवुड में काम कर रहे उत्तर भारतीय कलाकारों ने उन्हें हाथों-हाथ लेने में देरी नहीं की।

उप्र में नया 'बॉलीवुड' बसाने के सपने साकार करने में सिने जगत के दिग्गज हमकदम हो लिए हैं। उन्होंने रियायती दर पर जमीन की मांग से इसकी शुरुआत कर दी है तो सरकार ने भी रजामंदी का संकेत दिया है। फिल्मी दिग्गजों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उप्र में संपूर्ण फिल्म सिटी बनेगी। सबसे बड़ी नई

फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रेटर नोएडा में बनेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री बॉलीवुड के दिग्गजों अनूपम खेर, परेश रावल, सतीश कौशिक, सौंदर्या रजनीकांत, गीतकार मनोज मुंतशिर आदि से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिल चुके हैं। योगी ने फिल्मी दिग्गजों को विश्वास दिलाया है कि उनकी

सरकार उप्र में एक भव्य और आपकी जरूरतों को पूरा करने वाली सर्वसुविधायुक्त 'पूर्ण फिल्म सिटी' का विकास कर दुनिया को एक उपहार देगी। बॉलीवुड दिग्गजों ने भी माना कि मुंबई में सिर्फ शूटिंग की जगह है। उप्र में फिल्म सिटी का जो खाका बनाया गया है उसे तैयार करने में पटकथा लेखक विजयेंद्र प्रसाद, कला निर्देशक नितिन देसाई, फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित, गायक उदित नारायण, कैलाश खैर, निर्माता-निर्देशक शैलेश सिंह, भजन सम्राट अनूप जलोटा, मनोज जोशी, उप्र फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव की भी अहम भूमिका रही है।

बहरहाल, एक तरफ उप्र में नई फिल्म सिटी बनने से लोग खुश हैं तो दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, योगी सरकार पर उनकी सरकार के समय के एक और प्रोजेक्ट का फीता काटने का आरोप लगाया है। अखिलेश को इस बात का बेहद मलाल है कि आइडिया उनका था, फिल्म सिटी की घोषणा उन्होंने की और उस पर श्रेय योगी सरकार लेना चाहती है। अखिलेश ने ट्वीट कर फिल्म सिटी के उद्घाटन को पुरानी फिल्म की 'रीलांचिंग' करार दिया है। अखिलेश के रीलांचिंग वाले ट्वीट का जवाब मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने स्टैंडल में दिया। जलोटा ने अखिलेश को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि जब वह कानपुर में पढ़ाई करते थे, तब करीब पचास वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता ने उप्र में फिल्म सिटी की घोषणा की थी। ऐसे ही अखिलेश यादव ने भी की, लेकिन वह सपना योगी राज में साकार होते दिख रहा है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

राजस्थान खनन माफिया की जागीर बनता जा रहा है। सरकारों के संरक्षण में यहां हमेशा से माफिया का बोलबाला रहा है। शासन-प्रशासन उनके सामने नतमस्तक नजर आते हैं। यहां हमेशा माफिया का खूनी खेल चलता रहता है। माफिया की दहशतगर्दी का इससे बड़ा सुबूत और क्या होगा कि जहां कहीं भी उन्हें रोका गया, उन्होंने खून की नदियां बहाने में एक पल की भी देरी नहीं की। अलवर में बार्डर होमगार्ड की नृशंस हत्या और जालोर में पिता, पुत्र, पुत्री को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलने की हाहाकारी घटनाएं प्रतीकात्मक रूप से एक भयावह सच्चाई को उजागर कर रही थी कि राज्य की बागडोर अब माफिया सरदारों के हाथों में पहुंच गई है। अलवर में खनन माफिया के दुस्साहस की पराकाष्ठा थी कि पहले तो रोके जाने पर होमगार्डों को ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ाकर एक गार्ड की हत्या कर दी। फिर बजरी माफिया के गुंडे पत्थर बरसाकर भाग निकले। जालोर के खायला कस्बे में अवैध बजरी ले जा रहे ट्रैक्टर ने रोक-टोक किए जाने पर एक परिवार को ही कुचल दिया। पिछले पांच साल में माफिया के बढ़ते शिकंजे में कितने लोग जान गंवा चुके हैं। इसके आंकड़े ही चौंका देते हैं।

जल, जंगल और पर्वतों को खोखला करने वाले गिरोहबंद बेखौफ खिलाड़ियों की दस्तक को क्या अनसुना किया जा रहा है? सरकार इस मामले में सफाई देते हुए नहीं थकती कि पिछले तीन साल में बजरी माफिया से 100 करोड़ का जुर्माना वसूला जा चुका है। लेकिन साथ ही बुझे मन से प्रशासन अपराधीकरण को भी स्वीकार करता है कि माफिया के हौसले बुलंद हैं। इस मामले में सरकार द्वारा तैयार करवाई गई एक रिपोर्ट अवैध खनन की मोटी तस्वीर तो बयां करती है, लेकिन रिपोर्ट में इस खेल को रोकने की कोशिशों की स्पष्ट तस्वीर का जिक्र तक नहीं है। खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं कि 'यह कैसर तो हमें पिछली भाजपा सरकार ने दिया है। हमें तो इसे जबरन भोगना पड़ रहा है।

भाया यह कहते हुए अपनी परवशता जताते हैं कि इस कैसर का इलाज आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने माफिया को नेस्तोबूद करने के लिए यह कहते हुए नई नीति लाने का जिक्र भी किया कि एक सीमा तक खनन में वैधता निर्धारित कर दी जाए, ताकि यह खेल थम सके। लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि इस तरह के बयान तो खनन मंत्री की लफ्फाजी के सिवाय कुछ नहीं है। सवाल है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि पूरा खेल राजनीतिक संरक्षण और विभागीय अफसरों की मिलीभगत पर टिका है। भाजपा नेता इसका पूरा दोष सन् 2013 के दौरान सत्ता में रही कांग्रेस सरकार पर मढ़ते हैं कि यह नौबत तो तत्कालीन गहलोत सरकार की नीतियों का नतीजा है। खनन



खनन माफिया की जागीर

समितियां बेअसर

बजरी माफिया को बेकाबू करने के नाम पर अब तक समितियां बनती रही हैं और बैठकें होती रही हैं। लेकिन समितियों में शामिल अफसर बजरी माफिया की आहटों को सुनने तक को तैयार नहीं है। बजरी माफिया के हौसले बुलंद हैं और वो पूरी गिरोहबंदी के साथ सरकारी फौज पाटे से दो-दो हाथ करने को तैयार लगता है। इस मुहाने पर खान महकमा क्या कर रहा है? कोई खबर नहीं है। हैरत की बात है कि पिछली भाजपा सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाते हुए रेत खनन पर लगाए गए प्रतिबंध में कुछ रियायतें देने की याचिका लगाई थी। लेकिन विद्वान न्यायाधीश लाकोर ने दोहराया कि 'पारिस्थितिकी पर खनन के प्रभाव तथा रेत की फिर से भराई की दर के वैज्ञानिक आंकलन के बाद ही खनन की अनुमति दी जाए।' लेकिन यह आदेश खनन और निर्माण क्षेत्र में सक्रिय परिवारों को प्रभावित करने वाला साबित हुआ। नतीजतन रेत और बजरी के दाम आसमान छूने लगे। यहां सर्वोच्च न्यायालय के 2012 में दिए गए आदेशों का जिक्र करना भी प्रासंगिक होगा। इसमें कहा गया था कि 'बालू रेत के खनन से जुड़ी एक नीति बनाई जाए, जिसमें पर्यावरण की मंजूरी, उसकी निगरानी और लीज से जुड़े अन्य जरूरी प्रावधान भी शामिल किए जाएं। खनन का अधिकार इसी नीति के तहत दिया जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के बावजूद सरकार ढीली-ढाली ही बनी रही। अलबत्ता सरकारी अफसर इस मामले में लीपापोती ही करते रहे कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने का पूरा प्रयास कर रही है।

कारोबारी कुछ और ही पीड़ा बयां करते हैं। उनका कथन सरकार की मंशा को ही कटघरे में खड़ा करता है कि अवैध खनन रोकने के लिए बनाए गए 80 चैक पोस्ट हटाने का क्या मतलब था? खनन महकमे के भविष्य को लेकर दो धारणाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंत्रालय को ही समाप्त कर देना चाहिए। इसके कलुषित इतिहास को देखते हुए इससे बड़ा कोई विकल्प नहीं हो सकता।

बजरी खनन के अवैध खेल को लेकर मंत्रीजी का तर्क है कि इस बाबत तो केंद्र सरकार ही कोई नीति बनाए, तो बेहतर होगा। लेकिन सवाल है कि बजरी खनन के लालबाग में मजे करने वाला माफिया क्या किसी भी नीति को सफल होने देगा? परजीवी किस्म का माफिया क्यों नई पारबंदियों को चलने देगा? विशेषज्ञों का कहना है कि बजरी माफिया पर शिकंजा कसने की ताकत ही जब छीज रही हो, तो कोई कानून क्या कर लेगा? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बजरी माफिया के बुलंद हौसलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब तलबी की, कि 'अवैध बजरी खनन रोकने के लिए क्या किया? चार हफ्ते में बताए सरकार।' बीती फरवरी में जारी किए गए इस आदेश को 6 महीने गुजर चुके हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? 100 करोड़ का जुर्माना वसूला और 30 हजार वाहनों को जब्त किया। किन्तु बजरी खनन तो नहीं थमा। बजरी माफिया कितना ताकतवर है? इसकी तफतीश करें तो, तस्करी के तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा-दिल्ली तथा गुजरात और महाराष्ट्र तक जुड़े हैं। अरावली के खत्म होते पहाड़ों की तस्वीर पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 'क्या इन पहाड़ों को हनुमान जी उठा ले गए?'

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

बिहार के चुनावी अखाड़े में पहलवान अभी अपना पाला दुरुस्त करने में ही उलझे हैं कि चुनाव आयोग की सीटी बज गई। अब यह तय हो गया है कि 10 नवंबर को नई सरकार की सूरत सामने आ जाएगी। अब वह स्पष्ट होगी या धुंधली, यह समय ही बताएगा। अचानक तारीखों की घोषणा से बहुतों को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक दलों के जुड़ने-टूटने का सिलसिला अभी जारी है। टीमें बन पातीं, इससे पहले ही यह घोषणा हो गई। अब इस घोषणा के बाद तेजी से समीकरण बदलने की उम्मीद है।

बिहार में चुनाव को लेकर तरह-तरह की अटकलें जारी थीं। एक कोने से यह हवा भी उड़ रही थी कि चुनाव टल भी सकते हैं। लेकिन जब किसान बिल के विरोध में विपक्षी दल अपने आंदोलन को धार देने में जुटे थे, उसी समय चुनाव आयोग ने तीन चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी। चूंकि यह चुनाव कोरोनाकाल में हो रहा है, इसलिए तमाम नियम-कायदे व दिशा-निर्देश भी तय कर दिए गए हैं। द्वारे-द्वारे जाने व सभाओं को लेकर पुरानी प्रैक्टिस काम नहीं आने वाली। वचुअल रैली ही सहारा है। हालांकि सभी दलों ने इसको लेकर अपनी तैयारी कर रखी है। छोटे-छोटे वाट्सएप ग्रुप के जरिए मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में लगे हैं, लेकिन इसकी सफलता को लेकर सभी में संशय बरकरार है।

बहरहाल चुनाव की घोषणा होते ही सभी ने इसका स्वागत किया है कि वे लड़ाई को तैयार हैं। आज से तीन महीने पहले यह समझा जा रहा था कि बिहार में लड़ाई आमने-सामने की होगी। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अधिकांश दल लामबंद थे। एनडीए में लोजपा के ही थोड़े-बहुत नीतीश विरोधी स्वर उभर रहे थे, लेकिन उसे भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। समझा जा रहा था कि सत्तारूढ़ नीतीश को बनाए रखने और हटाने के मुद्दे पर ही चुनाव होगा। वैसी ही बिसात बिछी दिख भी रही थी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस समीकरण पर भारी पड़ने लगी। बड़े दलों के आगे सीटों पर बात न बनने से किले दरकने लगे। महागठबंधन में तेजस्वी यादव का विरोध करके पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अलग होकर नीतीश के साथ जा बैठा और उसके बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी (रालोसपा) के उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी को नीतीश की टक्कर का न मानते हुए गत दिनों अलग राह निकल लिए।

एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश विरोध पर तुली है और 143 सीटों पर अकेले लड़ने की बात कह रही है। लोजपा की मांग विधानसभा में 36 और विधान परिषद में दो

सज गया चुनावी रण



टिकट की दौड़ में कई नौकरशाह शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कई पूर्व आईपीएस व पूर्व आईएएस अधिकारी विभिन्न पार्टियों से टिकट पाने की दौड़ लगा रहे हैं। हाल में ही वीआरएस लेकर राजनीति में आए पूर्व डीजीपी गुपेश्वर पांडेय की चर्चा हो रही है, लेकिन गुपेश्वर पांडेय अकेले पूर्व आईपीएस अधिकारी नहीं हैं, जिनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार उन्हीं के बैचमेट रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी व पूर्व डीजी सुनील कुमार भी जदयू का दामन थाम चुके हैं। अब चर्चा यह है कि वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। जानकार मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीति से पुराना नाता रहा है। हालांकि, अभी पार्टियों की तरफ से टिकट मिलने की कहानी बाकी है, लेकिन राजनीति संभावनाओं और कयास का ही खेल है। प्रबल इच्छा ऐसी रही कि किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व आईपीएस अशोक कुमार गुप्ता ने निर्दलीय ही पटना साहिब से चुनाव लड़ लिया था, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वो राजद का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा डीजीपी रहे केएस द्विवेदी की भी भागलपुर से इस बार चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी राघव शरण पांडेय के बगहा से दोबारा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं, ट्रैफिक में काम लेकर चर्चा में आए पुलिस अधिकारी श्रीधर मंडल ने भी राजद का दामन थामा है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं।

सीटों की है। एनडीए में उनका मामला बिगड़ता देख रालोसपा ने अपनी संभावना टटोलने के लिए भाजपा से संपर्क साधा, लेकिन पांच से ज्यादा वहां भी मिलती नहीं दिख रही। जबकि इससे ज्यादा वह महागठबंधन में छोड़कर आई है।

अभी तक आमने-सामने के मोर्चे पर डटे एनडीए और महागठबंधन में पड़ती दरारों से तीसरे मोर्चे की तस्वीर उभरती दिखने लगी है। इन बड़े दो गठबंधनों में आपसी खींचतान के बीच छोटे दल अपनी संभावनाएं तलाशने में जुट गए हैं। जनअधिकार पार्टी (जाप) के पप्पू यादव छोटी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हैं। वह पहले ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार बता उनका महत्वाकांक्षा को हवा दे चुके हैं, जो अब गुल खिलाती नजर आ रही है और एनडीए में दरार का कारण बन रही है। वहीं महागठबंधन से दूरी बनाने और एनडीए में संभावनाओं के द्वार बंद होते देख रालोसपा का ठौर भी इनके साथ ही दिखने लगा है।

असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पहले ही समाजवादी जनता दल (डेमोक्रेटिक) देवेन्द्र यादव की पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। यह खेमा भी आगे इनके साथ जुड़ जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। दरअसल छोटे दलों का एकमात्र मकसद सदन में अपनी छोटी ऐसी हिस्सेदारी का है, जिसके बिना सरकार का गठन मुश्किल हो। इन्हीं कवायदों के बीच चुनाव आयोग की बजी घंटी ने अस्त-व्यस्त पहलवानों को सावधान की मुद्रा में ला दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सप्ताह भर के सीमित समय में कौन से समीकरण बनते हैं और किसके बिगड़ते हैं?

● विनोद बक्सरी

चीन ने इस साल मई से ही लद्दाख सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसी कड़ी में चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में जिन सैन्य साजोसामान की खेप बढ़ाई है उनमें हैवी आर्टिलरी गन, हैवी मशीन गन और एयरक्राफ्ट आदि शामिल हैं। 29-30 अगस्त के टकराव के साथ-साथ चीन ने और धमकाने वाले अंदाज में कैलास-मानसरोवर क्षेत्र में भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल बेस पर 2,200 किमी तक मारक क्षमता वाली डीएफ-21 बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। यह ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और करनाली जैसी उन नदियों के मुहाने पर है जो देशों की सीमाओं से परे बहती हैं। इनमें से करनाली तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएफ-21 भारत के भीतरी शहरों को भी निशाना बना सकती है। यह मिसाइल किसी भी पारंपरिक हमले की स्थिति में एक अहम कवच मुहैया कराती है। ऐसे में भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ सामरिक जमावड़ा बढ़ाना होगा।

भारत ने अभी तक रक्षात्मक रणनीति ही अपनाई है। ऐसे में इससे जुड़ी कमियों को दूर करते हुए जवाबी हमले की सटीक रणनीति बनानी होगी। वैसे 2013 से ही भारतीय सैन्य बलों ने एलएसी पर जमावड़ा बढ़ाकर सीमित आक्रामक नीति अपनाई है। अब भारत को लंबी अवधि के संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें स्थानीय स्तर पर लचीलापन अहम भूमिका निभाएगा। मिसाल के तौर पर भारतीय सेना और वायुसेना को नागरिक हवाई अड्डों का भी प्रभावी उपयोग करना चाहिए। हमले के बाद उससे उबरने की अचूक रणनीति भी तैयार करना निर्णायक होगा। अपनी हवाई क्षमताओं को इस प्रकार विस्तार देना होगा कि जिन स्थानों को निशाना बनाने की अधिक आशंका हो, उन्हें जल्द से जल्द दोबारा तैयार किया जा सके।

भारतीय वायुसेना में पांच राफेल विमानों के शामिल होने से भारत की हवाई ताकत मजबूत हुई है। राफेल विमानों की पहली खेप का वायुसेना में शामिल होना यह भी दर्शाता है कि अपनी सेनाओं की क्षमताओं में अपेक्षित विस्तार के लिए भारत को किस पैमाने पर संसाधन उपलब्ध कराने होंगे? लड़ाकू विमान जैसे साजोसामान की ऊंची कीमत से यह और अच्छे से प्रकट होता है। बात केवल विमान खरीदने तक सीमित नहीं है। उनके साथ कलपुर्जे और लॉजिस्टिक पैकेज भी लेना होता है। 36 राफेल विमानों वाले समग्र पैकेज पर लगभग 68,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इतनी बड़ी राशि का भुगतान एकमुश्त न होकर

चीन की सनक का इलाज जरूरी



राजनाथ सिंह के समक्ष कई जटिल चुनौतियां

सेना के एक पूर्व कमांडर ने जून 2018 में इस बात का संज्ञान लेते हुए कहा था कि भले ही भारतीय विनिर्माता दुनिया में बेहतरीन गुणवत्ता वाले जूते तैयार करते हों, पर भारतीय सेना दुनिया में सबसे घटिया कांबैट बूट्स पहनने पर मजबूर है। इस प्रकार देखा जाए तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष कई जटिल चुनौतियां हैं। चूंकि चीन के साथ जारी गतिरोध के लंबी खिंचने की आशंका है, लिहाजा भारतीय सेना को खासतौर से 3,800 किमी लंबी एलएसी की सुरक्षा के लिए कमर कसनी होगी। 1962 की लड़ाई में भारतीय सैनिकों को गुणवत्तापरक कपड़ों और जूतों के बिना ही जंग के मैदान में उतार दिया था। इस गलती के लिए देश ने जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन को कभी माफ नहीं किया। हमें यही उम्मीद है कि 2020 में वह इतिहास नहीं दोहराया जाएगा।

चरणबद्ध तरीके से होगा। यह वार्षिक रक्षा बजट से ही किया जाएगा। इससे अंदेशा है कि अगले दो-तीन वर्ष तक यानी वर्ष 2023 तक गैर-विकास रक्षा व्यय में कमी आएगी। फिलहाल यही आसार दिख रहे हैं कि फरवरी 2021 में जब बजट पेश किया जाएगा, तब रक्षा व्यय इस साल पेश किए गए बजट के अनुमान से कम होगा। चालू वित्त वर्ष में 3.37 लाख करोड़ रुपए के रक्षा व्यय का अनुमान पेश किया गया था। इसमें पेंशन का हिस्सा शामिल नहीं था। इस राशि में करीब 65 प्रतिशत हिस्सा 10 लाख से अधिक की सेना और अपेक्षाकृत छोटी वायु सेना, नौसेना के वेतन-भत्तों और रखरखाव की मद में खपना है। हालांकि वायुसेना और नौसेना जैसी अपेक्षाकृत छोटे आकार वाली सेनाओं का खर्च मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय प्रधान है।

अपने सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए भारत जैसे देश को जरूरत तो इस बात की है कि न्यूनतम निरंतर आधुनिकीकरण और नए हथियारों की खरीद के लिए वह अपने रक्षा व्यय का 40 फीसदी पूंजीगत आवंटन के रूप में करे। अभी यह 34 प्रतिशत के स्तर पर है और फिलहाल रुपए पर पड़ती मार के चलते और सिकुड़ रहा है। इस प्रकार नौसेना और वायुसेना को आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम रकम

मिल पाती है। राफेल विमान की ही मिसाल लें तो 2011-12 में ही इसका चुनाव कर लिया गया था, लेकिन यह 2020 में जाकर ही बेड़े में शामिल हो सका। यह पूरा मामला निर्णय प्रक्रिया में देरी और आवश्यक वित्तीय आवंटन की पोल खोलता है। बहरहाल लड़ाकू विमान सिर्फ एक मसला है।

यथार्थ यह है कि सैन्य साजोसामान के मोर्चे पर तीनों सेनाओं की हालत खस्ता है। यहां यह स्मरण कराना उपयोगी होगा कि 2016 के मध्य में संसदीय समिति ने सैन्य बलों में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहे पुराने उपकरणों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा प्रतिष्ठान में लचर आधुनिकीकरण के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया था। प्रतिष्ठित सैन्य अफसर और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की अध्यक्षता वाली समिति ने टिप्पणी की थी कि सेना को पुराने हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। कुछ चीजों का विशेष उल्लेख करते हुए समिति ने कहा था कि वाहनों, छोटे हथियारों, इन्फैंट्री स्पेशलिस्ट वेपंस, साइट एंड सर्विलांस उपकरण, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन उपकरण, रडार के अलावा पावर इन्विवपमेंट्स और जेनरेटर्स की भारी कमी प्रतीत होती है।

● ऋतेन्द्र माथुर

जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, तब वहां कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है। उदार लोकतंत्र की मिसाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां नवंबर में आने वाले जनादेश का सम्मान किया जाएगा? उससे हिंसा भड़कने का डर है, जो पहले ही ध्रुवीकरण को हवा दे रही है। असल में कुछ मोर्चों पर हालात हाथ से फिसल से गए हैं। जैसे कोविड-19 से निपटने को लेकर वाशिंगटन की रणनीति। यह इतनी लापरवाह भरी रही कि कोई अमेरिका से जवाब की आस तक नहीं लगा रहा। दिसंबर 2019 में चीन के चुहान में कोरोना वायरस से फैली बीमारी फरवरी 2020 के अंत तक एक वैश्विक महामारी में बदल गई। कारगर उपचार के अभाव में उससे निपटने के लिए समूची अर्थव्यवस्था को बंद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। परिणामस्वरूप आज अमेरिका में बेरोजगारी की समस्या महामंदी के स्तर जितनी विकराल हो गई है।

आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में करीब एक लाख छोटे उद्यम बंदी के कगार पर हैं। वहीं व्यापार एवं तकनीक के मोर्चे पर चीन से संघर्ष वैश्विक राजनीति का बुनियादी टकराव बन गया है, जिसमें सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही। अमेरिका में कोरोना अभी भी कोहराम मचाए हुए है। उससे राहत के दूर-दूर तक आसार नहीं दिख रहे हैं। इस महामारी से होने वाली क्षति को कम करने में राजनीतिक नेतृत्व लाचार दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका द्वारा खुद के लिए गढ़ी गई वैश्विक नेता की छवि तार-तार होती दिख रही है। इस आपदा ने कल्याणकारी राज्य के रूप में अमेरिका की कमजोरी की कलाई खोलकर रख दी है और हालात से निपटने में लचर नीतियों ने मौजूदा संकट को और विकराल बना दिया है। अमेरिका में करीब 43 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं है। इन लोगों के पास सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी खास सहारा नहीं है। ऐसे में यह आपदा उन पर और बड़ी आफत बनकर टूटी है। अमेरिकी दुश्वारियों के लिए मानों इतना ही काफी नहीं था। जब कोरोना संकट उबाल पर था तब पुलिस बर्बरता के कारण अमेरिका में नस्लीय तनाव की आग भड़क उठी। 46 वर्षीय अफ्रीकी-अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मर्द में पुलिस के हाथों हुई मौत पर अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके कारण विरोध-प्रदर्शन, हिंसा, दंगे और पुलिसिया कार्रवाई की बाढ़ आ गई।

एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 55 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि पुलिसिया हिंसा एक बड़ी समस्या है। वहीं 58 प्रतिशत इस बात का समर्थन करते हैं कि नस्लवाद आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसी प्रकार दो-तिहाई अमेरिकियों को लगता है कि उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। एक ऐसा देश जो गवर्नंस और



सवालों के घेरे में अमेरिकी श्रेष्ठता

अमेरिका और ध्रुवीकृत होगा और उसकी राजनीति में बढ़ेगा टकराव

ऐसा लगता है कि अमेरिका और अधिक ध्रुवीकृत होगा और उसकी राजनीति में टकराव भी बढ़ेगा। यह शायद ऐसा पड़ाव है कि भारत आंतरिक दुश्वारियों से निपटने में अमेरिका को एकाध सलाह दे सके। भारत में तमाम लोगों के लिए देश के आंतरिक मामलों पर अमेरिकी आलोचना एक बड़ा संकेत होती है। पश्चिमी मीडिया में किसी एक आलेख से ही यह मान लिया जाता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में गड़बड़ी कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम भारत की उपलब्धियों को लेकर अधिक आत्मविश्वास का परिचय दें और भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप की अनदेखी के साथ ही उसकी आवश्यक भर्त्सना भी करें।

मानवाधिकार के मामले पर शेष विश्व को भाषण देता हो और जो खुद को दुनिया का नेतृत्वकर्ता मानता हो, वह अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटने में नाकाम दिख रहा है। अमेरिका में विरोध-प्रदर्शन आज भी जारी हैं। इससे अमेरिकी समाज और अधिक ध्रुवीकृत होता जा रहा है। ऐसे कठिन हालात में राजनीतिक नेतृत्व लोगों को एकजुट करने और देश को एक साथ लाने में इच्छुक नहीं दिख रहा है। दरअसल यह चुनावी दौर है और ऐसे में अपने-अपने वोट बैंक को साधना ही आवश्यक है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इसे कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर ऐसे तल्ख शब्दों के जरिए हमला किया कि एक मृत डेमोक्रेट ही वास्तव में बढ़िया डेमोक्रेट होता है।

फिलहाल अमेरिकी संस्थानों की साख रसातल में है। पुलिस बर्बरता के कारण अल्पसंख्यकों की हुई मौत और कोरोना के इलाज

में अफ्रीकी-अमेरिकियों के साथ हो रहे पक्षपात ने विरोध-प्रदर्शनों को और आक्रोश से भर दिया है। नस्ल का मुद्दा अमेरिकी समाज और राज्य व्यवस्था के दिलो-दिमाग में बसा है। जहां तक आंतरिक मामलों को संभालने की बात है तो जो अमेरिका इस मामले में भारत सहित दूसरे देशों को अक्सर हेय दृष्टि से देखता आया हो, वही आज एकजुटता की आंतरिक कमी से पीड़ित महसूस कर रहा है, जिसका फिलहाल कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा। कोविड-19 महामारी के परिणाम, बढ़ती सामाजिक-आर्थिक विषमता, राष्ट्रवाद का उफान और नस्लीय तनाव का मिश्रण अमेरिका को किस प्रकार से आकार देगा, इसकी अपने-अपने ढंग से कल्पना की जा रही है। कुछ लोग इसे इस रूप में देख रहे हैं कि अब वैश्विक मामलों में अमेरिकी सर्वोच्चता का अंत हो रहा है। यह भले सच हो या न हो, परंतु अमेरिका में स्वयं को उभारने की अथाह आंतरिक क्षमता है। इसे उसने अतीत में प्रदर्शित भी किया है।

अमेरिका की तुलना में भारत एक युवा राष्ट्र है। आंतरिक विरोधाभासों और विभाजक रेखाओं के बावजूद भारत एक लोकतंत्र के रूप में अपना वजूद बचाए रखने में सफल रहा है। इसके बावजूद भारत खुद को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में ढालने में जुटा है। इस राह में आने वाली चुनौतियों पर पश्चिमी आभिजात्य वर्ग ने रोने-पीटने से कभी परहेज नहीं किया। हालिया दौर में चाहे सीएए का मसला हो या फिर अल्पसंख्यकों का मुद्दा, उसमें एक रुझान यही देखने को मिला कि भारत को उस पश्चिमी मॉडल की धौंस दी जाए, जिसे वे उच्चस्तरीय मानते हैं। आज जब सर्वोच्चता का मिथक खंड-खंड हो रहा है तो भारत एक वैकल्पिक मॉडल यानी प्रतिरूप पेश कर सकता है। एक ऐसा प्रतिरूप जो कहीं अधिक भारतीय मूल्यों से ओतप्रोत हो।

● कुमार विनोद

कुछ महीने पहले आई यूएनडीपी की रिपोर्ट 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स' ने महिलाओं के बारे में स्थापित पूर्वाग्रहों का तथ्यपूर्ण खुलासा किया। यह रिपोर्ट 75 देशों के अध्ययन पर आधारित है, जहां विश्व की लगभग 80 फीसदी आबादी रहती है। रिपोर्ट बताती है कि इन देशों में 40 फीसदी से अधिक लोगों का

यह मानना है कि जब अर्थव्यवस्था धीमी हो, तब नौकरियां सिर्फ पुरुषों को ही मिलनी चाहिए। इस वर्ष जून में प्रकाशित अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक कई देशों में यह धारणा स्थापित है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में नौकरी की कम हकदार होती हैं। भारत और ट्यूनीशिया में ऐसा मानने वाले लोगों का प्रतिशत 80 है। कोविड-19 के नकारात्मक परिणामों से जूझती विश्व अर्थव्यवस्था उन तमाम उपायों को लेकर संवेदनशील है जिनसे लोगों की नौकरियों में बहाली हो सके। यह भी सबको पता है कि श्रम बाजार में महिलाएं हाशिए पर हैं। बावजूद इसके, उनकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही। श्रम बाजार के पुरुषीकरण ने इस मिथ्या धारणा को स्थापित कर दिया है कि विश्व अर्थव्यवस्था की बेहतर कुल कार्यबल में सिर्फ पुरुषों की भागीदारी से ही हो सकती है जबकि विश्व बैंक समूह की 2018 की रिपोर्ट इस धारणा को नकारते हुए बताती है कि कार्यबल में पुरुषों और महिलाओं की असमानता के चलते विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 ट्रिलियन (1 लाख 60 हजार अरब) डॉलर की क्षति उठानी पड़ी है।

कार्यबल में महिलाओं की अस्वीकार्यता सदियों से चली आ रही है क्योंकि पुरुष अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर अपनी सत्ता और प्रभुत्व को सुनिश्चित करते आए हैं। यही कारण है कि 18वीं सदी तक महिलाएं सिर्फ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों में ही संलग्न हो पाईं जहां उन्हें कम वेतन और भयावह परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ये परिस्थितियां तब परिवर्तित हुईं जब पहले विश्व युद्ध में सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली किए गए पदों की भरपाई महिलाओं द्वारा की गई। परिवहन, अस्पताल, उद्योग, यहां तक कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी महिलाओं को शामिल किया गया। उन्हें प्रेरित करने के लिए देशप्रेम की दुहाई देते हुए अनेक प्रेरक पोस्टर दीवारों पर लगाए गए।

रूस के उद्योगों में महिलाओं का हिस्सा 43 फीसदी हो गया। ऑस्ट्रिया में एक लाख महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस विश्व युद्ध में 60,000 रूसी महिलाएं बटालियन ऑफ डेथ का भी हिस्सा बनीं। फिर भी उस पुरुषवादी सोच को वे नहीं तोड़ पाईं जिसके अनुसार महिलाओं में मारक क्षमता और आक्रामकता की कमी होती है। 1918 में युद्ध समाप्ति का समय



असमानता का नतीजा

गलत मान्यताएं

पिछले दिनों हुई नोटबंदी के बाद जब भारत में रोजगार कम हुए तब भी पुरुषों के लिए जगह बनी रहे, इसके लिए महिलाओं को काम छोड़ने को विवश किया गया। अध्ययन बताते हैं कि नोटबंदी के बाद उन परिवारों का प्रतिशत, जिनमें दो या अधिक सदस्य रोजगार करते हैं 34.8 से घटकर 31.8 रह गया। तब भी ज्यादातर महिलाओं ने ही रोजगार खोए। इस धारणा को स्थापित करने के प्रयास किए गए कि महिलाएं स्वयं ही रोजगार नहीं चाहती, परंतु यह सच नहीं है। 2018 में नंदी फाउंडेशन के एक अध्ययन में बताया गया कि भारत की 8 करोड़ किशोरी लड़कियां कैरियर को लेकर डेरों उम्मीदें रखती हैं, पर उनकी उम्मीदें पूरी हो पाएंगी, कहना कठिन है क्योंकि उनके सामने वह ग्लास सीलिंग है जिसे तोड़ पाना सहज नहीं। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि विपदाओं और महामारियों के समय महिलाओं को श्रमबल से जोड़ने की तमाम कोशिशें की जाती हैं लेकिन स्थितियां सामान्य होते ही उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास किए जाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, परंतु बड़ी ही ढिंढाई के साथ यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

पास आते देख एक सोची-समझी नीति के तहत ब्रिटेन में 'द रेस्टोरेशन ऑफ प्री-वार प्रैक्टिस एक्ट 1919' की बहाली कर महिलाओं पर दबाव बनाया गया कि वे अपनी नौकरियां स्वतः छोड़ दें ताकि विश्वयुद्ध से लौटे हुए सैनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। यही नहीं, महिलाओं पर सामाजिक दबाव बनाने के लिए 1919 में 'द इलस्ट्रेटेड संडे हेराल्ड' में प्रश्न किया गया 'इज मॉडर्न वुमन हसी?' यानी क्या

आधुनिक महिला फूहड़ है? सांस्कृतिक रूढ़िवादियों के लिए यह प्रश्न नहीं, वह अभिकथन था जिसको स्थापित करने की वे हर संभव कोशिश करते रहे, ताकि महिलाओं का आत्मबल इतना कम हो जाए कि वे स्वयं ही घर के भीतर सीमित होकर रह जाएं। अंततः कार्यबल में महिलाओं की संख्या बहुत कम हो गई और यह स्थिति दूसरे विश्वयुद्ध तक बनी रही। 1939 में दूसरा विश्वयुद्ध शुरू होने के बाद फिर उसी इतिहास को दोहराया गया। इस दौरान 60 लाख महिलाओं ने तमाम ऐसी भूमिकाएं निभाईं जिन पर पुरुषों का वर्चस्व था परंतु युद्ध समाप्ति के बाद महिलाओं पर फिर दबाव बनाया गया कि वे अपने पदों को छोड़ दें।

1944 में यूएस विमिन ब्यूरो के एक सर्वेक्षण में 84 फीसदी महिलाओं ने युद्ध के दौरान आरंभ किए गए कार्यों को जारी रखने की इच्छा जताई। पुरुषवादी व्यवस्था का कड़वा सच यह था कि जो विज्ञापन एजेंसियां युद्ध के समय महिलाओं को श्रमबल से जोड़ने की प्रार्थना कर रही थीं, अब वे ही उन्हें अपना रोजगार छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती नजर आ रही थीं ताकि युद्ध से लौटे पुरुषों के लिए जगह खाली हो जाए। नतीजा यह कि 30 से 40 लाख महिलाओं ने अपने रोजगार छोड़ दिए। अमेरिकी लेखिका बेट्टी फ्रीडम ने अपनी पुस्तक 'फेमिनिन मिस्टिक' में लिखा कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद महिलाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती रही कि घर की चारदीवारी में ही उनके जीवन का सारा सुख है। वे नहीं जानती थीं कि पुरुषवादी व्यवस्था के ये प्रयास दशकों बाद भी जारी रहेंगे। महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिशें आज भी की जाती हैं।

● ज्योत्सना अनूप यादव

पौ राणिक कथाओं और उनकी सीख को आज के वक्त के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। हम इन कहानियों को पढ़कर पाएंगे कि कलियुग में भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस में ऐसी कई बातें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आज के युग में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ईश्वर होता है। एक दिन स्वामी नरहरिदास उनके गांव आए। उन्होंने ही तुलसी को आगे के जीवन की राह दिखाई। यह भेंट उनके लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हो गई। कवि तुलसी ने रामकथा को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने का माध्यम बना लिया। उन्होंने रामकथा में न केवल सुखद समाज की कल्पना की, बल्कि आदर्श जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया।

तुलसी ने गंगा को करुणा, सत्य, प्रेम और मनुष्यता की धाराओं में वर्गीकृत किया, जिनमें अवगाहन कर कोई भी व्यक्ति अपने आचरण को गंगा की तरह पवित्र कर सकता है। उन्होंने मनुष्य के संस्कार की कथा लिखकर रामकाव्य को संस्कृति का प्राण तत्व बना दिया। कविता का उद्देश्य लोक मंगल मानकर विपरीत परिस्थिति को तप माना। भाव भक्ति के साथ कर्म का संगम होने पर विद्या और ज्ञान स्वयं आने लगते हैं। तुलसी के राम सब में रमते हैं। वे नैतिकता, मानवता कर्म, त्याग द्वारा लोकमंगल की स्थापना करने का प्रयास करते हैं।

रामचरितमानस के अलावा, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामलला नहछू आदि अनेक कृतियां रचीं। अनेक चौपाइयां सूक्ति बन गई हैं। तुलसी ने सत्य और परोपकार को सबसे बड़ा धर्म और त्याग को जीवन का मंत्र माना। मानव-तन को सही अर्थों में मनुष्य बनाना मानवता की सार्थकता है।

भरत का त्याग, राम की करुणा, जटायू का परहित, शबरी-केवट प्रेम, हनुमान की भक्ति, सुमति जैसे शाश्वत लोकमूल्यों के माध्यम से उन्होंने विषम समस्याओं का समाधान किया। कर्म को सकारात्मक, भाग्य को नकारात्मक मानते हुए असत्य, पाखंड, ढोंग में डूबे समाज को जगाया।

**सिया राममय सब जग जानी
करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी।**

प्रत्येक मानव में रमते हैं श्रीराम



एक बार भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती! जब कोई र अक्षर से आरंभ होने वाले किसी भी शब्द का उच्चारण करता है तो मेरा मन आनंद से अभिभूत हो जाता है, मुझे यही आभास होने लगता है कि वह हमारे परमप्रिय स्वामी भगवान राम का ही नामोच्चारण कर रहा है...

**रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती
चेतः प्रसन्नतां याति रामनामाभिर्शंकया।।**

‘राम’ शब्द का उच्चारण करने मात्र से तन और मन में एक अलग तरह की अनुभूति होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। संतों-महात्माओं ने राम का नाम जपते-जपते मोक्ष प्राप्त कर लिया। राम शब्द का अर्थ है रमति इति रामः

**राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम बरानने।**

अर्थात् जो रोम-रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है वही राम है। इसी तरह ‘रमते योगितो यस्मिन् सः रामः’ अर्थात् योगीजन जिसमें रमण करते हैं वही राम है। राम का नाम ऐसा है जिसे सगुण भक्तों ने तो अपना प्राण माना ही है, निर्गुण निराकार वादियों ने भी राम के नाम को महत्व दिया है। देखा जाए तो है ही रकार मकार वर्णों की विशेषता। इस प्रकार ‘र’ शब्द परिपूर्णता का बोधक है और ‘म’ परमेश्वर वाचक है। चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दशरथ राम हो। सत्यता तो यह है कि ‘राम’ शब्द एक

महामंत्र है। संत तुलसीदास जी के लिए तो श्रीराम सब कुछ थे। रामचरितमानस में वर्णित नाम महिमा तो अपनी विशेषता के साथ अद्भुत अनूठी बन गई है। संत तुलसीदास जी के लिए राम तो...

**एक भरोसो एक बल एक आस विस्वास
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।**

राम जीवन का मंत्र है। राम मृत्यु का मंत्र नहीं है। राम गति का नाम है, धमने का नहीं। राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। राम महाकाल के अधिष्ठाता, संहारक, महामृत्युंजय शिवजी के आराध्य हैं। शिव, काशी में मरते हुए व्यक्ति को राम नाम सुनाकर भवसागर पार करा देते हैं, बंधन मुक्त कर देते हैं। ‘राम’ शब्द दो अक्षर का है, परंतु इस छोटे से शब्द में भ्रम और भटकाव तथा मद व मोह को समाप्त करने की शक्ति है। सर्वदा शिव के हृदयाकाश में विराजित राम भारतीय लोकजीवन के कण-कण में विद्यमान है। श्रीराम हमारी आस्था और

अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के अंशावतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम हिन्दुओं के आराध्य ईश हैं। जीवन में महाऊर्जा का नाम ही राम है।

यह भी सर्वविदित है कि सगुण रूप में राम में समस्त मानवीय एवं दैवीय गुणों को प्रतिष्ठित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी राम को निराकार ब्रह्म का अवतार ही मानते हैं। राम अनादि ब्रह्म है, अतः सभी संतों ने निर्गुण राम को अपने आराध्य रूप में प्रतिष्ठित किया है। कबीर के आराध्य भी राम ही हैं। वे अपने राम को सर्वथा निर्गुण व्यापक एवं विश्वमय ईश्वर मानते हैं। उनके राम असीम हैं।

वास्तव में राम अनादि हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं, परंतु भक्तों के स्नेहवश तथा ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से वे दशरथ राम बना स्वीकारते हैं। राम नाम में तीन वर्ण हैं-र+आ+म = र अग्नि का स्वरूप, आ आदित्य स्वरूप और म चन्द्र का प्रतीक है। एक-एक वर्ण एक-एक नाड़ी का प्रतीक हैं। इस प्रकार राम नाम त्रिकाल प्रकाशक है वह मणिदीप है जो दिन-रात आत्म ज्योति से प्रकाशित होता रहता है, यथा- राम नाम मणि दीप धरि, कहने का भाव है कि यदि तू भीतर बाहर दोनों जगह उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहरी पर राम-नाम रूपी मणि दीपक को रख।

● ओम

पड़ोसियत

आज सुबह उठते ही, मैं मेरा रोज का काम करने मतलब पानी भरने घर के बाहर निकली। अपने दो गुंडी उठाके बड़ी मां के घर के नल के पास पहुंच गई। नल के टाके में मैंने देखा तो पानी कुछ ज्यादा ही भर गया था। इसके वजह से गुंडी भरने में मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने इस पर उपाय के लिए नल को पाइप लगा दिया। पाइप लगाने के बाद पता चला की नल की धार बहुत ही कम हो गई है। जिसके वजह से पानी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। आखिर में निराश होकर मुझे नल से खाली गुंडी उठा के घर की ओर निकलना



पड़ा। मैं जैसे ही घर के गेट के पास पहुंची तब मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली रजिया ने आवाज लगाई और पूछा क्यों खाली गुंडी ले जा रही हो?

मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा- नल से पानी नहीं आ रहा है, तो इसीलिए। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और अपने नल से दो गुंडी पानी भर के दे दिया। वह भी मेरे बिना कुछ कहे या बिना मांगे। कमाल हैं ना! भगवान ने भेजा कोई दूत है, जिसका दूसरा नाम पड़ोसी है। जो बिना बोले ही हमारी परेशानी समझ जाते हैं और वक्त पे हमारे काम आते हैं।

- अंकुशा बुलकुंडे

श्रद्धा या श्राद्ध



पास वाले कमरे से बर्तन को जोर-जोर से पीटने की आवाज आ रही थी, लेकिन सुधा अपनी बहन से बात करने में मगन थी। बहू ने पास आकर सासू मां से कहा- मां जी, लगता है अम्माजी को कुछ चाहिए। आप जाकर देख लीजिए मैं रसोईघर में हूँ। सुधा ने बड़े ही अनमने मन से अपनी बहन से कहा... तू अभी कॉल काट दे, देखकर आती हूँ। पता नहीं, किस दिन इस बुढ़िया से मुक्ति मिलेगी... कहकर उसने फोन रख दिया। कमरे में जाकर देखा, उसकी सास पेट पकड़कर इशारे में बोल रही थी... भूख लग रही है। सुधा ने जोर से डंट लगाते हुए कहा- क्यों इतना शोर मचा रही हो, अभी थोड़ी देर है खाना लाने में, चुप हो जाओ !

पीछे से बहू ने आकर पूछा... मां जी अम्माजी के लिए रसीली सब्जी बना दूँ? कोई जरूरत नहीं, सूखी सब्जी बनी है उसी से खा लेंगी। आजकल इतनी महंगाई है, जरा सा खाती हैं फिर बिगड़ कर जाती

है। बहू ने सहमति में सिर हिला दिया। अचानक सुधा बोली और हां बहू सुन परसों तेरे दादाजी का श्राद्ध है। बहू ने पूछा- बताइए मां जी फिर क्या-क्या बनाना है। सुधा हिदायत देती हुई बोली... दो सब्जी, रायता, मूली का कस, दाल वाली कचौड़ी, मेवा वाली खीर और इमरती बाजार से आ जाएगी। बहू बोली- मां जी इससे क्या होता है? सुधा मुस्कराते हुए बोली... इससे दादाजी खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बहू के भाव अचानक से बदल गए और उदास होते हुए बोली... मां जी फिर तो अम्माजी भी मरने के बाद खुश रहेंगी, जीते जी तो उन्हें एक सूखी सब्जी से ही खाना पड़ता है जबकि उनके दांत साथ नहीं देते। कम से कम उन्हें इतने सारे व्यंजन तो मिलेंगे! इतना सुनते ही सुधा की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं।

- वर्षा वाष्ण्य

मन के दर्पण

अधरों को अपने खोल जरा।
मन के दर्पण कुछ बोल जरा।
चुप्पी ज्यादा बढ़ जाए न,
जिद के ताले जड़ जाएं न,
जीवन छोटा पड़ जाए न,
तू खुद ही खुद को तोल जरा।
मन के दर्पण कुछ बोल जरा।
दूजों से हंस कर मिलता है,
हर कहे पे उनके चलता है,
पर तुझे जहर ही मिलता है,
थोड़ा सा अमृत घोल जरा।
मन के दर्पण कुछ बोल जरा।
दुनिया कहती है कहने दे,
न संग चले तो रहने दे,
बेफिक्र सा खुद को बहने दे,
अब आंक ले अपना मोल जरा।
मन के दर्पण कुछ बोल जरा।

क्यों खोजे महल दुमहले

क्यों खोजे महल दुमहले तू,
क्या जाने कब तक डेरा है।
इस आनी-जानी दुनिया में,
है जितना भी बहुतेरा है।
चहुं ओर लिए पिंजरे-पिंजरे,
सैयाद फिर बिखरे-बिखरे,
पंखों में भर विश्वास तू उड़,
ये नील गगन बहुतेरा है।
कोई क्यों साथ भला देगा,
जितना देगा दुगना लेगा,
क्यों जोहे बाट तू औरों की,
मन मस्त मगन बहुतेरा है।
सूखे फूलों का गम न कर,
कल आएगा खुशबू ले कर,
दामन अपना लहराए जा,
यहां इत्र-ए-चमन बहुतेरा है।

- डॉ. मीनाक्षी शर्मा

मजबूत होता भारतीय क्रिकेट का बेच स्ट्रैथ!



भारतीय क्रिकेट इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से राज कर रही है। टीम इंडिया के सीनियर टीम में विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं इंडिया ए और जूनियर टीम में भी प्रतिभावान युवाओं की कमी नहीं है। इसी कड़ी में आईपीएल भारतीय क्रिकेट को निखारने का अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है। आईपीएल 2020 में अभी तक जितने भी मुकाबले हुए उसमें कही ना कही भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। इन खिलाड़ियों ने बताया कि वह टीम इंडिया का भविष्य हैं। वह आने वाले समय में भारत का नाम देश-विदेश में रोशन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया कि चाहे भारतीय क्रिकेट में कितने बड़े खिलाड़ी रिटायर हो जाएं, लेकिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का आना हमेशा लगा रहेगा। ऐसे में हम आपको कुछ उन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भारत के लिए लंबा क्रिकेट करियर बना सकते हैं।

● आशीष नेमा

पृथ्वी शॉ

2018 में भारत को अंडर-19 वर्ल्डकप जिताने वाले कप्तान पृथ्वी शॉ को एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी माना जाता है। इस खिलाड़ी ने साल



2018 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया, जहां उन्होंने पहले मैच में शानदार शतक जड़ा। इसके बाद से ही पृथ्वी शॉ को लगातार टीम इंडिया के लिए खेलने के मौके दिए गए। पृथ्वी टेस्ट में तो अच्छा करते

आवरों की क्रिकेट में गिने-चुने मौके पर ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए। लेकिन इस आईपीएल के अपने दूसरे मैच में पृथ्वी ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। पृथ्वी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 63 रन बनाए। जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। पृथ्वी शॉ की इस पारी को देखकर लगा कि वह आने वाले समय में लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में भी भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं अभी आईपीएल के आने वाले मैच में भी पृथ्वी शॉ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

शुभमन गिल

अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने के बाद शुभमन गिल को जूनियर डॉन ब्रेडमेन के नाम से जाना जाने लगा। यह खिलाड़ी



पिछले दो साल से चयनकर्ताओं की नजरों में है। लेकिन इसे सीनियर टीम के लिए ज्यादा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है। शुभमन गिल घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल

शुभमन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने ओपनिंग करने का जिम्मा दिया। अपने दूसरे मैच में शुभमन ने हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 70 रन की मैच विनिंग पारी खेली। शुभमन ने बताया कि वो किसी भी हालत में और किसी भी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ जीत दिलाना जानते हैं। शुभमन के तरकश में हर वो शॉट मौजूद है जो उन्हें रन दिला सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में शुभमन भारतीय क्रिकेट के लिए भी ऐसी पारियां खेलते जरूर दिखाई देंगे।

राहुल तेवतिया

इस खिलाड़ी ने पंजाब के खिलाफ मैच में जिस तरह से अपना दमखम दिखाया वह चमत्कारिक था। राहुल ने पंजाब के खिलाफ मैच में 53 रनों का पारी खेली। लेकिन



ये पारी एक अलग तरह की थी जो ज्यादातर क्रिकेट के मैदान में नहीं देखी जाती है। 27 साल के राहुल तेवतिया ने अपने पहले 19 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए थे। लेकिन अगले 12 गेंदों में राहुल ने 45 रन टोक डाले, जिसमें उन्होंने 7 छक्के लगाए और अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को जीत

दिला दी। राहुल की ये पारी दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य काफी सुनहरा है। भारतीय युवा खिलाड़ी अपने आप में विश्वास करना जानते हैं। युवा खिलाड़ी जानते हैं कि हालात कैसे भी हो उन्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। ऐसे में आने वाले समय में राहुल तेवतिया को यह पारी एक अलग तरह का आत्मविश्वास दे सकती है। राहुल अब सबकी नजरों में आ चुके हैं। ऐसे में उन्हें बाकि बचे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और अगर वह ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में वह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़े स्तर पर खेल सकते हैं।



रवि बिश्नोई: आईपीएल 2020 में अभी तक इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेगस्पिनर बिश्नोई ने हर किसी को अपना मुरीद बनाया। गुगली पर ज्यादा निर्भर रहने वाले रवि बिश्नोई लेग स्पिन और फिलपर का भी अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। अभी तक अपने खेले 3 मैचों में बिश्नोई ने किसी भी हालात में बल्लेबाज को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया। ऐसे में इस खिलाड़ी ने अगर आईपीएल के अपने आगामी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया तो यह भी जल्द भारतीय क्रिकेट में खेलते दिखाई दे सकते हैं।



90 के दशक में बाला सुब्रमण्यम के गाए गानों से टॉप पर पहुंचे थे सलमान खान



जाने-माने प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लगभग डेढ़ महीने से कोरोनावायरस संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती थे। 50 साल के सिंगिंग करियर में बाला ने 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। मैंने प्यार किया सलमान खान के कैरियर की तबौर एक्टर पहली फिल्म थी और ये ब्लॉकबस्टर थी। जब सलमान के गानों के लिए बालासुब्रमण्यम को चुना गया तो लोगों ने कहा कि सलमान पर यह



आवाज नहीं जंचेगी लेकिन यह बात गलत साबित हुई। नब्बे के दशक में बाला ने ही सलमान के सबसे ज्यादा हिट गाने गाए जिसकी बदौलत सलमान भी टॉप पर पहुंच गए। फिल्म के एक गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवॉर्ड मिला था।

कंपोजर राम-लक्ष्मण ने कहा, 'मैंने प्यार किया' के दौरान सलमान, भाग्यश्री, सूरज बड़जात्या और मैं खुद सब नए थे। नई टीम थी। लिहाजा म्यूजिक में भी हम नयापन चाह रहे थे। मुझे तब के तत्कालीन सिंगर कोई पसंद नहीं थे। सिवाय बालू जी के।

पिता के सामने गाने से डरती थीं लता दीदी

भारत रत्न लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50 हजार से ज्यादा गीत गाए हैं। बकौल लता जी, पिताजी जिंदा होते तो मैं शायद सिंगर नहीं होती...ये मानने वाली महान गायिका लता मंगेशकर लंबे समय तक पिता के सामने गाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थीं। फिर परिवार को संभालने के लिए उन्होंने इतना गाया कि सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराती रहीं।

लता जब गातीं तो मां डांटकर भगा देती थीं

लता मानती हैं कि पिता की वजह से ही वे आज सिंगर हैं, क्योंकि संगीत उन्होंने ही सिखाया। जानकर आश्चर्य हो सकता है कि लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर को लंबे समय तक मालूम ही नहीं था कि बेटी गा भी सकती है। लता को उनके सामने गाने में डर लगता था। वो रसोई में मां के काम में हाथ बंटाने आई महिलाओं को कुछ गाकर सुनाया करती थीं। मां डांटकर भगा दिया करती थीं कि लता के कारण उन महिलाओं का वक्त जाया होता था, ध्यान बंटता था।



पिता के शिष्य को सिखाया था सही सुर

एक बार लता के पिता के शिष्य चंद्रकांत गोखले रियाज कर रहे थे। दीनानाथ किसी काम से बाहर निकल गए। लता वहीं खेल रही थीं। पिता के जाते ही लता अंदर गई और गोखले से कहने लगी कि वो गलत गा रहे हैं। इसके बाद लता ने गोखले को सही तरीके से गाकर सुनाया। पिता जब लौटे तो उन्होंने लता से फिर गाने को कहा। लता ने गाया और वहां से भाग गईं। लता मानती हैं पिता का गायन सुन-सुनकर ही मैंने सीखा था, लेकिन मुझे मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके साथ गा सकूं।

पिता को था सफलता का अंदाजा... इसके बाद लता और उनकी बहन मीना ने अपने पिता से संगीत सीखना शुरू किया। छोटे भाई हृदयनाथ केवल चार साल के थे जब पिता की मौत हो गई। उनके पिता ने उन्हें गायिका बनते नहीं देखा हो, लेकिन लता की सफलता का उन्हें अंदाजा था।

'टशन' के फ्लॉप होने पर डिप्रेशन में चली गई थीं करीना कपूर खान

करीना कपूर खान दोबारा मां बनने वाली हैं। कभी मां बबिता और बहन करिश्मा के साथ फिल्मों के सेट पर चहल-कदमी करने वाली नटखट बेबो ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी से की थी। हालांकि यह फिल्म हिट नहीं साबित हुई लेकिन करीना के किरदार को काफी सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद मुझे कुछ कहना है, मुझसे दोस्ती करोगे और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों से उन्होंने आसानी से खुद को कमर्शियल सिनेमा में स्थापित कर दिया। लेकिन शायद करीना इतना करने के बाद भी चुप नहीं बैठना चाहती थीं। उनको सिर्फ शो-पीस कहने वाले आलोचकों को उन्होंने चमेली, देव और ओंकारा जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के दम पर चुप करा दिया। 2008 में आई टशन करीना कपूर के दिल के बेहद करीब फिल्म थी क्योंकि इसी फिल्म के दौरान उनकी सैफ अली खान से मुलाकात हुई थी। लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने से बेबो काफी मायूस हो गई थीं और डिप्रेशन में चली गई थीं।



करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब टशन नहीं चली तो मैं बुरी तरह टूट गई थी। तकरीबन छह महीनों तक मैं डिप्रेशन में थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि क्या हो गया। लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि यही नियति थी।

मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी सब बच्चे कॉमिक्स, कार्टून और फिर वीडियो गेम्स से ही मनोरंजन क्यों करते हैं? अमेरिका में मेरे सबसे छोटे भाई की चार साल की बेटी कुछ खाती ही नहीं थी। विनी द पूह देखकर कुछ खा लेती। एक बार मैंने ध्यान से देखा 'विनी का पेट शहद खाते-खाते फूलता जा रहा था' बच्ची हंसते-हंसते दोहरी होती जा रही थी। फिर इतना फूल गया कि बाहर ही न निकल पाया, तो बच्ची रोने लगी! तब पता चला कि वॉल्ट डिज्नी क्यों विश्व की उन महान हस्तियों में हैं, जिन्होंने मानव

खुद पर हंसने का कोई खतरा नहीं

मन की थाह पहचानी। अबोध बच्चे से लगाकर वयोवृद्ध तक, सभी हंसना चाहते हैं।

तय किया है, जब भी हंसना है तो खुद पर ही हंसना। खुद के अलावा किसी पर नहीं। खुद पर हंसने का कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरों पर हंसने के हजार खतरे हैं। अक्सर ही ये खतरे जानलेवा भी हो जाते हैं। जब से लोगों में बात-बात पर तुनक जाने का रिवाज चला है, उनके साथ बड़ा सोच-समझकर हंसना पड़ता है। क्या पता कब बिदक जाएं। अगर उनके बीच कभी मुझे अपने पर ही हंसना पड़ जाए तो मुंह पर रुमाल धर लेता हूँ। कहीं मेरी हंसी छिटककर बाहर न आ जाए। बैठे-बिठाए तमाशा न बन जाए।

न केवल नाते-रिश्तेदारों के बीच, बल्कि बीवी के सामने भी कोशिश मेरी यही रहती है कि कहीं हंसी न झूट जाए। हंसना पड़ भी जाए तो मुंह के भीतर ही हंसा जाए। मन ही मन में हंसने की कला सीख रहा हूँ। एक जिम्मेदार पति होने के नाते मेरा मानना है कि पत्नी की हंसी में कम से कम शामिल होना चाहिए। कब कौन-सी हंसी को खुद पर ले झगड़ बैठे। अतः हंसी-खुशी और पत्नी, दोनों से होशियार रहें।

हंसी का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहा कि कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी पर भी हंस लिए। अब हंसने से पहले सौ दफा सोचना पड़ता है। हंसी का कोई बुरा न मान जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि लोग ठठाकर हंसते तो आज भी हैं, पर अकेले में। पब्लिकली हंसने वाले को लोग पागल समझने लगे हैं। हाँ, यही पागलपन भरी हंसी अगर आप 'लाफ्टर क्लब' में जाकर हंस रहे हैं तो बुद्धिजीवी और स्वस्थ समझे जाएंगे। वहाँ जोर-जोर से हंसने पर कोई बंदिश नहीं। वहाँ तो राह चलता शख्स भी आपको देखकर न खींसे निपेरेगा, न मुंह बिगाड़ेगा। आखिर आप समूह में एक साथ हंस रहे हैं। पागल भी आपको देखकर

सोचता हूँ, कैसे मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। बताइए, बेबात हंसते रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि बात या बेबात हंसना दुनिया में अब मूर्खता समझा जाता है। मूर्ख न समझा जाऊँ इसीलिए मैं भी नहीं हंसता। दरअसल, हंसी को हमने नियंत्रित कर लिया है। सीमित हंसी हम अब सोशल मीडिया पर हंसते हैं।



पागल नहीं समझेगा। मुझे तो अब वे लोग भी बड़े बौद्धिमत्ता से लगते हैं, जिनके चेहरे पर हर समय हंसी रहती है। जिन्हें आपने कभी गंभीर होते हुए देखा ही नहीं। उनका मकसद ही हंसना और हंसते रहना है।

सोचता हूँ, कैसे मूर्ख होते हैं ऐसे लोग। बताइए, बेबात हंसते रहते हैं। उन्हें पता नहीं कि बात या बेबात हंसना दुनिया में अब मूर्खता समझा जाता है। मूर्ख न समझा जाऊँ इसीलिए मैं भी नहीं हंसता। दरअसल, हंसी को हमने नियंत्रित कर लिया है। सीमित हंसी हम अब सोशल मीडिया पर हंसते हैं। कभी फेसबुक पर आए कमेंट पढ़कर। कभी वॉट्सएप पर चुटकुला पढ़कर। कभी ट्विटर पर किसी को ट्रोल होते देखकर। सोशल मीडिया पर हंसी जाने वाली हंसी को बाहरी कोई देखता नहीं। या तो हम खुद देखते हैं या हमारा मोबाइल। कोई एक कोना पकड़ लीजिए, मोबाइल ले लीजिए फिर जितना मर्जी चाहे हंसते रहिए। आप क्यों हंस रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा।

दुनिया की नजरों से बचकर मैं भी अपने मोबाइल के साथ खुद ही हंसता हूँ। कभी अपनी ही बेवकूफी पर हंस लेता हूँ, मगर दूसरे पर नहीं हंसता। पहले मुझे वे लोग कतई अच्छे नहीं लगते थे, जो हंसते ही नहीं थे। जब देखो तो मुंह बिगाड़े रहते थे, लेकिन अब अच्छे लगने लगे हैं। अब तो मैं उन्हें दुनिया का सबसे खुशकिस्मत व्यक्ति समझता हूँ। हंसी की बात पर भी न हंसना बड़ी बात है।

बेवकूफ हैं वे जो कहते हैं कि हंसी को

बचाकर रखिए, क्या पता कब काम आ जाए। देख लिया मैंने जरूरत पड़ने पर पैसा ही काम आता है, हंसी नहीं। फिर भी, आप हंसने की ठाने ही हुए हैं तो खुद पर हँसिए।

खुद पर भी उतना ही हँसिए, जितना आपकी शरीर, आत्मा और स्वभाव झेल पाए। और भी अच्छा होगा कि मन ही मन हंसने का अभ्यास कीजिए। इस कला में पारंगत होने से आप जब चाहेंगे, हंस भी लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा हंसना सेहत के लिए हितकारी नहीं। मेरी बात पर मत हँसिए, मैं झूट नहीं बोल रहा, सच कह रहा हूँ। दिन में थोड़ा-थोड़ा वक्त निकालकर खुद पर मन ही मन हंस लेता हूँ। हंसने की तमन्ना भी पूरी हो जाती है, दूसरे बुरा भी नहीं मानते। झगड़े और किसी के नाराज होने का अंदेशा भी नहीं रहता।

कहाँ गए वो लोग? कोई हंसा क्यों नहीं पाता? अपशब्दों से भरे, प्रदूषण फैलाते कुछ विकृत जुमले अब हास्य कहे जा रहे हैं। जिन शो की काफी चर्चा हो रही है, उनमें भी बस किसी तरह, किसी न किसी का अपमान करने की एक भद्दी होड़ मची हुई है। पसंद किए जा रहे होंगे, किन्तु संभवतः यह आयरनी है हमारी। सभ्य समाज की। जो उल्टा हो जाए, वह आयरनी। जैसे कि प्राण का वह संवाद: तुमने ठीक ही सुना है, चोरों के 'ही' कुछ उसूल होते हैं। तो वही उल्टा हो रहा है। हंसाने वाले बस, पैसे-प्रसिद्धि और प्राइम टाइम कमाने के एक विचित्र चक्र में फँसकर, दर्शकों को त्रस्त कर रहे हैं।

● अंशुमाली रस्तोगी

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

आक्षेपक अक्ष



E-Magazine पढ़ने और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं
www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन: 0755-40 17788, 2575777

D-17008

**For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us**



Science House Medicals Pvt.Ltd.

17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) INDIA-462023

GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5  **Email : shbpl@rediffmail.com**

 **PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687**